VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स

Workbook

जुलाई 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

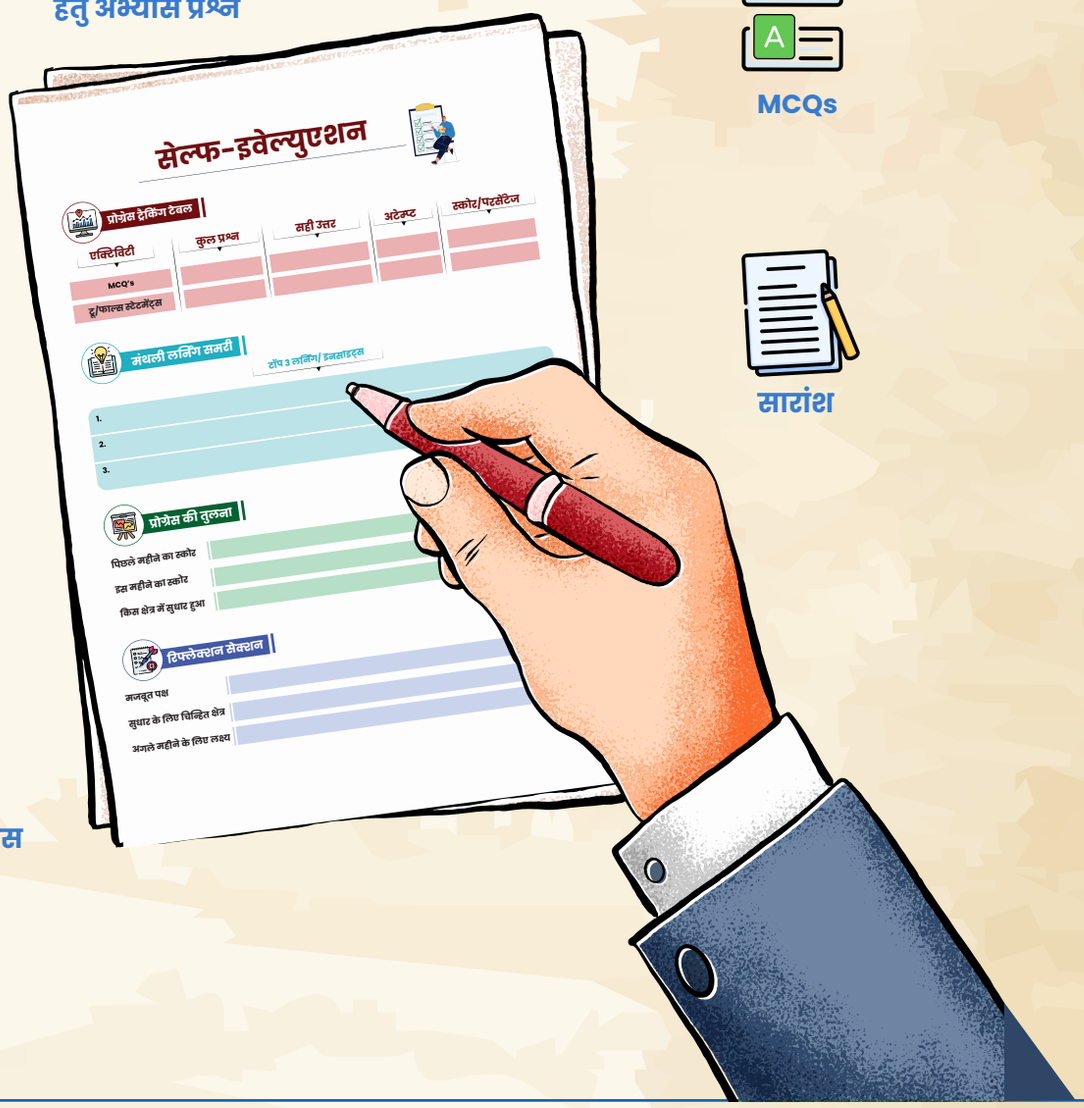

सारांश

स्मरणीय तथ्य

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई**

JODHPUR : 15 सितम्बर

फास्ट ट्रैक कोर्स 2025

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

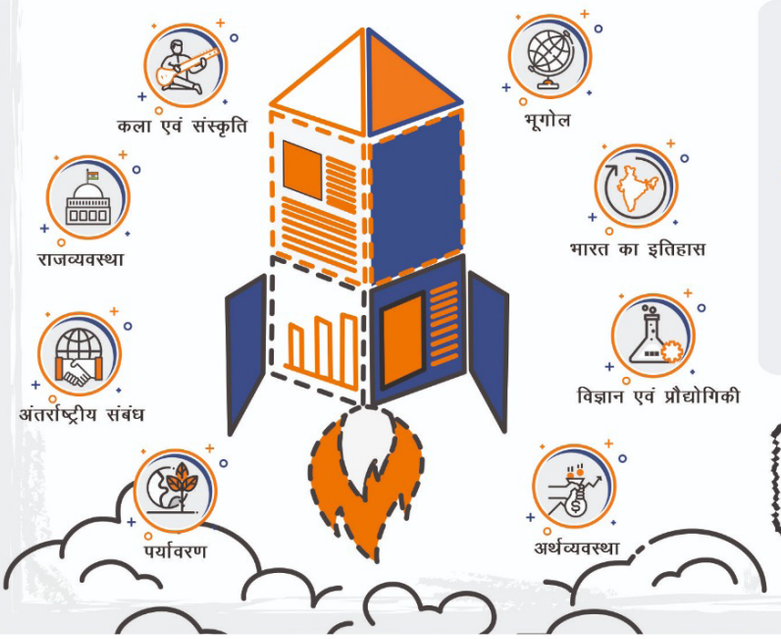

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिन्दी माध्यम
7 OCT, 5 PM

ENGLISH MEDIUM
13 OCT, 2 PM

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (POLITY & GOVERNANCE)

1.1. डिजिटल उपनिवेशवाद (Digital Colonialism) 6

1.2. ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन (Online Content Regulation) 7

1.3. राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 (National Cooperative Policy 2025) 8

1.4. PRI के वित्त स्रोत (PRI Finances) 9

1.5. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Dispute : ISWD) 10

1.6. भारत में राजनीति की लागत (Cost of Politics in India) 11

1.7. मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कम करना (Lowering of Age for Voting) 12

1.8. अन्य संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 13

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) {India-United Kingdom (UK) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)} 15

2.2. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations) 16

2.3. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना (China's Hydropower Project on the Brahmaputra River) 17

2.4. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations) . . 18

2.5. भारत-लैटिन अमेरिकी-कैरेबियाई देशों के मध्य संबंध (India Latin American and Caribbean Countries Ties) 19

2.6. ब्रिक्स रियो डी जनेरियो घोषणा-पत्र (BRICS RIO DE Janeiro Declaration) 20

2.7. AUKUS के तहत गीलोंग ट्रीटी (Geelong Treaty Under AUKUS) 21

2.8. गिरमिटिया समुदाय (Girmitiya Community) . . . 22

2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 23

3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

3.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना {Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)} 26

3.2. भारत में सार्वजनिक ऋण (Public Debt in India) . 26

3.3. भारत में लोगों की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास (Employability and Skilling in India) 27

3.4. फ्यूचर ऑफ वर्क (The Future of Work) 28

3.5. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना {Research Development And Innovation (RDI) Scheme} 28

3.6. भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India) 29

3.8. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights in India) 30

3.7. डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission) . . 30

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 30

4. सुरक्षा (SECURITY)

4.1. क्वांटम साइबर रेडीनेस (Quantum Cyber Readiness) 33

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 34

5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. अर्बन रेसिलिएंस (Urban Resilience) 35

5.2 इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) 36

5.3. वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना {CSS-Integrated Development of Wildlife Habitats Scheme (CSS-IDWH)} 37

5.4. वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 38

5.5. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific Ring of Fire) . 38

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 39

6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 5 वर्ष {Years of National Education Policy (NEP)} 43

6.2. छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं (Rising Suicides Among Students) 44

6.3. सामाजिक विलगाव (Social Isolation) 45

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 46

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

7.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह {NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) Satellite} 48

7.2. ब्लैक होल विलय (Black Hole Merger) 49

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 49

8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. चोल गंगम झील (Chola Gangam Lake) 51

8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप (Maratha Military Landscape) 53

8.3. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज चैंपियनशिप {International Chess Federation (FIDE) Chess Championship} 54

8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) 54

9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

9.1. सेलिब्रिटीज़ और उत्पादों का प्रचार (Celebrities and Endorsement of Products) 55

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

10.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना {Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)} 57

11. क्विक फैक्ट्स

12. एक्टिविटी (ACTIVITIES)

12.1. MCQS 63

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements) 66

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions) 66

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Study) 67

13. उत्तर और व्याख्या (ANSWERS AND EXPLANATION)

13.1. MCQ के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion) 68

13.2 ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers) 70

13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions) . . . 70

13.4. केस स्टडी हेतु दृष्टिकोण (Approach to Case Studies) 72

14. सेल्फ-इवेल्यूएशन

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

A.I.T.S

GS PRELIMS TEST SERIES 2026

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट

5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट

10 फुल लेंथ टेस्ट

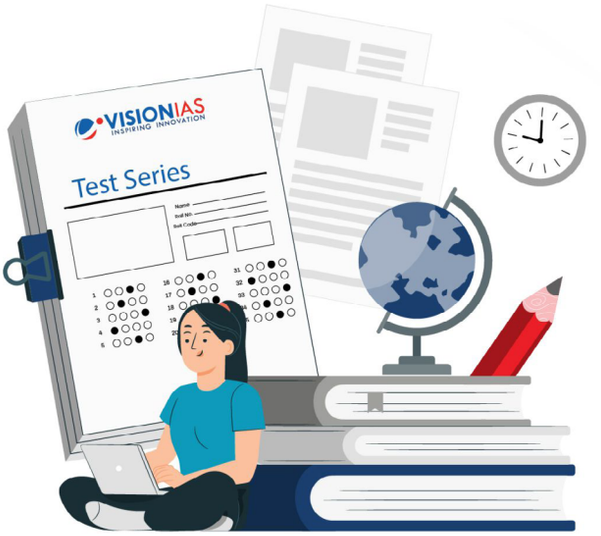

2026 | ENGLISH MEDIUM 7 SEPTEMBER | हिन्दी माध्यम 7 सितम्बर

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

वर्कबुक का जुलाई संस्करण आपकी UPSC तैयारी में सहायक बनने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है। इसमें सुनियोजित, विश्लेषणात्मक और परीक्षा-केंद्रित करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन के बाद वर्कबुक पर काम करने से आपकी जटिल मुद्दों को याद रखने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता मजबूत होगी, जो परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल हैं।

इस माह की वर्कबुक में भारत और विश्व को आकार देने वाले कई प्रमुख विषयों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। **राजव्यवस्था खंड** में, डिजिटल उपनिवेशवाद की चुनौतियों, ऑनलाइन कंटेंट विनियमन में सुधार तथा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 जैसी प्रमुख बहसों का विवेचन किया गया है। ये सभी टॉपिक गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी और नागरिक कल्याण के आपसी संबंधों को उजागर करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड में, भारत-यू.के. व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर, भारत-मालदीव संबंधों में प्रगति तथा ब्रह्मपुत्र पर चीन की जलविद्युत परियोजना जैसे प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये घटनाएँ क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति के परिदृश्य को आकार देने में भारत की सुदृढ़ होती भूमिका को प्रतिबिंबित करती हैं।

अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भी उतने ही महत्वपूर्ण खंड सम्मिलित हैं - क्वांटम साइबर तैयारी से लेकर जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में शहरी लचीलेपन तक - ताकि आपकी तैयारी समग्र और भविष्योन्मुखी बनी रहे।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

1. **मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्ख़ियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इस खंड का उद्देश्य एक्टिविटी में गहराई से जाने से पहले आपकी समझ की आधारशिला तैयार करना है।
2. **स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक:**

MCQs: महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।

ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स: मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।

एथिक्स केस स्टडी: हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।

उत्तर और व्याख्या: इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रू/ फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

4. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, और इसे अपनी UPSC तैयारी की यात्रा में एक भरोसेमंद माध्यम बनाएं। एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और सही साधनों के साथ आप न केवल करेंट अफेयर्स में दक्षता हासिल करेंगे, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास भी विकसित करेंगे।

हार्दिक शुभकामनाएं
करेंट अफेयर्स टीम
VisionIAS

"आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं।"

- महात्मा गांधी

1.1. डिजिटल उपनिवेशवाद (Digital Colonialism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने **डिजिटल उपनिवेशवाद** को लेकर चिंता व्यक्त की है कि किसी देश की **संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा** बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि **विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता** से है।

डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में

- यह बिग टेक कंपनियों के **डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व** को संदर्भित करता है। ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना उनका **डेटा एकत्रित** करती हैं, उसका **विश्लेषण** करती हैं तथा उस पर अपना **स्वामित्व** रखती हैं। इससे **राज्य एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता** को खतरा उत्पन्न होता है।

डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रवर्तक

- **बढ़े हुए आर्थिक लाभ:** उपयोगकर्ता विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक लाभ को बढ़ाता है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त:** व्यवहारों की भविष्यवाणी में सुधार करता है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति:** बिग डेटा के माध्यम से AI को उच्च उत्पादकता के लिए गति देता है।
- **डेटा का विनिमय मूल्य:** उपयोगकर्ताओं/संगठनों को डेटा साझा करके आय सृजित करने की सुविधा देता है।

डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ

- **आर्थिक प्रभुत्व:** गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर आदि का **तकनीकी एकाधिकार।**
- **साम्राज्यवादी नियंत्रण: स्वामित्व प्रणालियां और प्रतिबंधात्मक लाइसेंसिंग** (उदाहरण के लिए, **ऐप स्टोर नीतियां** (ऐप्पल/ गूगल) यह तय करने के लिए एकतरफा निर्णय लेती हैं)
- **निगरानी पूंजीवाद: बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण राजनीतिक/आर्थिक परिणामों** को आकार देता है (उदाहरण के लिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका)।
- **तकनीकी आधिपत्य:** अमेज़न (AWS), माइक्रोसॉफ्ट (Azure), और गूगल क्लाउड **दुनिया भर में क्लाउड सेवाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित** करते हैं।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदम का झुकाव अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ताक़तवर/ प्रमुख संस्कृतियों के मूल्यों से मेल खाए।
- **'परोपकार' का विमर्श:** बिग टेक कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी **लाभ-संचालित प्रोजेक्ट्स को परोपकार के रूप में प्रस्तुत** करती हैं (उदाहरण के लिए, फ्री बेसिक्स)।

डिजिटल उपनिवेशवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **उत्तरी गोलार्ध-दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती असमानता:** डेटा मोनेटाइजेशन कार्यों से प्रेरित तीव्र डिजिटलीकरण ने **पहले से मौजूद गंभीर असमानताओं** को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश बिग टेक कंपनियां विकसित देशों (समृद्ध उत्तर) में अवस्थित हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** कमजोर डिजिटल अवसंरचना महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में सुभेद्यताओं और विदेशी हस्तक्षेप के खतरे को बढ़ाती है।
- **गोपनीयता और डिजिटल अधिकार:** विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से गोपनीयता एवं डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन का खतरा रहता है।
- **स्थानीय व्यवसाय के समक्ष अस्तित्व का खतरा:** विज्ञापनों, खुदरा और सेवाओं में वैश्विक प्रभुत्व स्थानीय उद्यमों को कमज़ोर करता है।
- **आर्थिक नुकसान:** डिजिटल टेक की दिग्गज कंपनियां अपने मुनाफे को कम टैक्स या जीरो टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं। इससे भारत जैसे देशों में कर संग्रहण घटता है।
- **विनियमन में कठिनाई: साइबरस्पेस** की सीमा-पार प्रकृति के कारण मौजूदा कानूनी साधन उसे प्रभावी ढंग से **विनियमित करने में असमर्थ** हैं।
- **नेटवर्क प्रभाव:** जब कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके यूज़र लगातार बढ़ते रहते हैं और वे उसी में फँस जाते हैं। इस वजह से नए स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को मौका नहीं मिलता।

डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए कुछ उपाय

- **भारत:**
  - **DPDP अधिनियम, 2023:** व्यक्तिगत **डेटा संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क** स्थापित करता है। इसमें भारतीय सेवाओं के लिए विदेश में प्रसंस्करण भी शामिल है।
  - **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:** इसे **अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकता** है और उपभोक्ताओं का संरक्षण करता है।
  - **वैश्विक समर्थन:** भारत ने G-20, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता के लिए आवाज उठाई; G-20 **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** के लिए एक **टास्क फोर्स** का गठन किया।
  - **अन्य प्रयास: ONDC-** ई-कॉमर्स एकाधिकार के एक विकल्प के रूप में; **इंडिया स्टैक-** यह भारत का अपना आधारभूत **DPI** है।
- **अन्य देश:**
  - **यूरोपीय संघ: डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** लागू किए गए हैं।
  - **चीन:** दूरसंचार, AI, क्लाउड और निगरानी का विस्तार करने के लिए **BRI के अंतर्गत डिजिटल सिल्क रोड**।
  - **रूस: सॉवरेन इंटरनेट कानून (2019)** ने रूस में इंटरनेट के केंद्रीकृत राज्य प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है।

आगे की राह

- **डिजिटल संप्रभुता:** राज्यों को सभी **डिजिटल संपत्तियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण** रखना चाहिए।
- **डेटा स्थानीयकरण:** डेटा का **संग्रहण, स्थानांतरण और प्रॉसेसिंग** केवल राष्ट्रीय सीमाओं एवं कानूनी अधिकार क्षेत्रों के भीतर ही होने चाहिए।
- **गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क:** डेटा निर्माण, संरक्षण, साझाकरण और अवसंरचना के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क्स तैयार करने चाहिए।
- **सीमा-पार प्रवाह:** विकास, **सार्वजनिक हित और एकीकरण के बीच संतुलन** बना रहना चाहिए।
- **डेटा लाइफ साइकिल में सुधार:** डेटा के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा के सृजन से लेकर उसे नष्ट करने/ पुनः उपयोग तक समेकित प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- **समावेशी डिजिटल भविष्य:** डिजिटल खाई को पाटना, समावेशिता सुनिश्चित करना और नैतिकता को बनाए रखना।

निष्कर्ष

डिजिटल उपनिवेशवाद इंटरनेट को भू-राजनीतिक गुटों ("स्प्लिंटरनेट") में विभाजित कर देता है। डिजिटल एकजुटता और संप्रभुता की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग और संतुलित शासन आवश्यक है।

1.2. ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन (Online Content Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MoI&B) ने अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मंत्रालय ने यह प्रतिबंध IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 के तहत लगाया है।
- **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद (1965)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अश्लीलता के मद्देनजर **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध** लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन करने की आवश्यकता क्यों है?

- **सामाजिक पहुंच:** भारत में 950 मिलियन से अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, ऐसे में अविनियमित कंटेंट समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर सकता है।
- **हिंसा:** 2010 के एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि लगभग 90 प्रतिशत पोर्नोग्राफी में आक्रामकता दिखाई गई थी।
- **सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा:**
  - **बच्चे:** कम उम्र में अश्लील कंटेंट देखने से समझ विकृत हो जाती है।
  - **महिलाएं:** वस्तुकरण और असमानता को बढ़ावा देती हैं।
  - **अल्पसंख्यक:** हेट स्पीच सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है।
- **नैतिक अनिवार्यता:** अशोभनीय कंटेंट का अनियंत्रित प्रसार सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, पारिवारिक संस्थाओं आदि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए- **2021 की "बुली बाई" ऐप घटना**।
  - **दार्शनिक आधार:**
    - **जे. एस. मिल का हानि सिद्धांत:** यदि हानिकारक हो तो स्वतंत्रता सीमित कर देनी चाहिए।
    - **मनुष्य एक साधन के रूप में:** मनुष्यों को वस्तु के रूप में नहीं देखा जा सकता।
    - **असमान प्रभाव:** कम आय और कम साक्षरता वाले समूह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

अश्लील कंटेंट के विनियमन के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**
  - **धारा 67 एवं धारा 67A:** ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण पर नियंत्रण रखते हैं।
  - **धारा 69A:** यह केंद्र सरकार को विशिष्ट आधारों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है।
  - **धारा 79:** यह मध्यवर्तियों को "सुरक्षा कवच" प्रदान करती है। हालांकि, यदि वे अवैध कंटेंट हटाने में विफल रहते हैं, तो यह सुरक्षा वापस ली जा सकती है।
- **IT नियम 2021:** ये डिजिटल न्यूज मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के अधीन रखते हैं।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 294:** यह संहिता 'अश्लील' शब्द को परिभाषित करती है और ऐसे कंटेंट के प्रसार को अपराध घोषित करती है।
- **पॉक्सो अधिनियम:** बाल पोर्नोग्राफ़ी के वितरण/बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
- **महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:** यह महिलाओं के अश्लील चित्रण वाले कंटेंट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है।

कंटेंट को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियां

- **विनियामकीय चुनौतियां:**
  - **विनियामकीय ओवरलैप:** सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन न होने से तालमेल की कमी रहती है।
  - **परिभाषाओं में व्यक्तिपरकता:**अश्लीलता की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है और इससे सरकार द्वारा मनमाने कदम उठाए जा सकते हैं।
- **तकनीक संबंधी चुनौतियां:**
  - **एन्क्रिप्शन** बिना किसी जांच के अवैध सामग्री के प्रसार की अनुमति देता हैं।
  - **एल्गोरिदम**: फीडबैक लूप अधिक अश्लील सामग्री को बढ़ावा देते हैं।
  - **VPN:** प्रतिबंधों को दरकिनार करके प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँच की अनुमति देते हैं।
- **रचनात्मक स्वतंत्रता:** सख्त प्रतिबंध **रचनात्मकता पर अंकुश** लगाते हैं और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण: फिल्म फायर (समलैंगिकता) पर प्रतिबंध।

आगे की राह

- **बहु-हितधारक परामर्श:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स आदि के साथ परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** OTT प्लेटफॉर्म्स स्वचालित प्रोफनिटी फ़िल्टर (अभद्र भाषा फ़िल्टर), यूजर्स-रिपोर्ट आधारित कंटेंट स्कैनर और AI-संचालित कंटेंट विश्लेषण जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- **स्व-विनियमन को मजबूत करना:** कंटेंट मानक तैयार करने और लागू करने के लिए उद्योग-आधारित स्व-विनियामकीय संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए। इससे सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों/ कार्यों से सीखना:** यूरोपीय संघ का ऑडियो-विज़ुअल मीडिया सर्विसेज़ डायरेक्टिव पारंपरिक प्रसारण मानकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित करता है, जबकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के माध्यम से मजबूत गोपनीयता सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

1.3. राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 (National Cooperative Policy 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 की शुरुआत की।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- **दूसरी नीति** : पहली बार 2002 में बनाई गई थी।
- **विजन** : "सहकार से समृद्धि" के तहत सहकारिता को **विकसित भारत 2047** के लक्ष्य की प्राप्ति में मुख्य साधन बनाना।
- **उद्देश्य** : वर्तमान में सहकारिता से बाहर या निष्क्रिय 50 करोड़ लोगों को इससे जोड़ना।
- **मिशन स्तंभ** : छह रणनीतिक स्तंभ (इंफोग्राफिक)।
- **अन्य मुख्य प्रावधान** :
  - **विधायी सुधार** : पारदर्शिता, स्वायत्तता और सुगमता हेतु राज्यों द्वारा कानूनों में संशोधन।
  - **वित्तीय सशक्तिकरण** : सहकारी संस्थाओं पर कर में कमी, कॉरपोरेट जैसी प्रोत्साहन योजनाएं।
  - **व्यावसायिक परिवेश** : प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में मॉडल सहकारी ग्राम; **"भारत ब्रांड"** के तहत ब्रांडिंग।

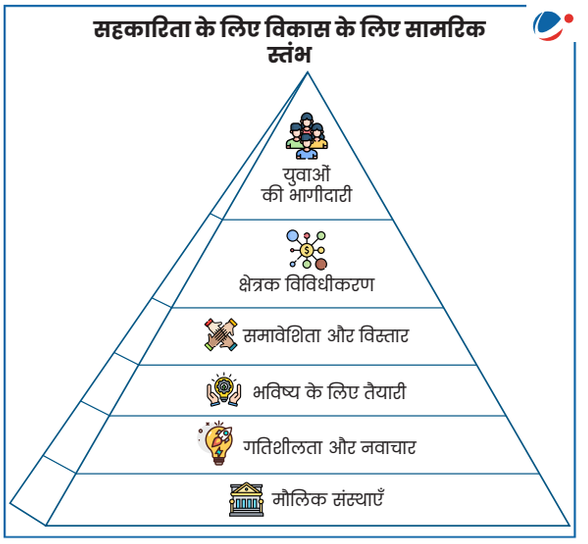

- **भविष्य के लिए तैयार रहना**: राष्ट्रीय सहकारी स्टैक को **एग्री-स्टैक और डेटाबेस** से जोड़ना।
- **नए क्षेत्रक** : नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, तकनीक।
- **समावेशिता** : महिलाओं, युवाओं, एससी/एसटी की भागीदारी बढ़ाना।
- **लक्ष्य** : 2034 तक जीडीपी में योगदान को तीन गुना करना; 30% अधिक सहकारी समितियां।

- **क्रियान्वयन** : सहकारिता मंत्रालय की इम्प्लीमेंटेशन सेल द्वारा।
- **निगरानी** : केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा।

भारत में सहकारिता

- **उत्पत्ति :** 1904 का सहकारी ऋण समिति अधिनियम।
- **परिभाषा :** स्वैच्छिक, स्वायत्त संस्था, संयुक्त स्वामित्व वाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण में, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।
- **स्थिति :** 8 लाख से अधिक समितियां, **2 लाख ऋण समितियां (जैसे PACS), 6 लाख गैर-ऋण समितियां (जैसे हाउसिंग, उपभोक्ता),** 30 करोड़ से अधिक सदस्य।
  - **प्रमुख क्षेत्रक :** हाउसिंग, डेयरी, PACS।
- **संवैधानिक मान्यता (97वां संविधान संशोधन, 2011)** :
  - **मूल अधिकार :** अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारिता शामिल।
  - **नीति निदेशक तत्व** : अनुच्छेद 43B (सहकारिता को बढ़ावा)।
  - **नया भाग IXB :** अनुच्छेद 243ZH–243ZT।
- **शासन संरचना** :
  - **बहु-राज्य सहकारी:** संघ सूची, MSCS अधिनियम 2002।
  - **राज्य सहकारी:** राज्य सूची, राज्य कानून।

सहकारिता का महत्व

- **ग्रामीण उत्थान** : ⅓ ग्रामीण जनसंख्या जुड़ी हुई है।
- **किसानों की आय में वृद्धि** : सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ना (जैसे-अमूल)।
- **सामाजिक प्रभाव** :
  - **महिला सशक्तिकरण :** SEWA बैंक -सूक्ष्म वित्त, रोजगार, समानता सुनिश्चित करने में।
  - **संधारणीयता :** ULCCS, केरल (हरित पहल)।
- **सामुदायिक जुड़ाव** : सामाजिक पूंजी निर्माण।
- **मूल्य**:
  - **समानता :** एक व्यक्ति–एक वोट।
  - **नेतृत्व :** लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से नेतृत्व विकास (जैसे महाराष्ट्र)।

सहकारिता की चुनौतियां

- **सीमित क्षमता :** ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में अवसंरचना, प्रशिक्षण, विशेषज्ञता की कमी।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप :** पारदर्शिता व दक्षता में कमी।
- **जटिल विनियमन** : नौकरशाही सहकारिता की प्रगति को अवरुद्ध करती है।
- **डिजिटल डिवाइड :** केवल 45% सदस्य डिजिटल रूप से दक्ष।
- **क्षेत्रीय असमानता :** शीर्ष 5 राज्यों में देश की 57% सहकारी समितियां हैं।
- **अन्य समस्याएं :** कुशल जनशक्ति की कमी, सहयोग अधिक नहीं होना, सीमित सदस्य/संसाधन।

निष्कर्ष

सहकारी संस्थाओं को निजी साझेदारी, बेहतर अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत करना चाहिए। समावेशिता बढ़ानी चाहिए, कमजोर इकाइयों का एकीकरण करना और CGI व RTI के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.4. PRI के वित्त स्रोत (PRI Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था (PRI) के अंतर्गत धन के वितरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्तीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेषकर **3F {कार्य (Functions), वित्त (Funds) और कर्मी (Functionaries)}** के कमजोर हस्तांतरण पर।

PRI के राजस्व के स्रोत

- केंद्र/राज्य सरकार से **कर और अनुदान।**

- अनुच्छेद 243-H के तहत स्वयं द्वारा वसूले गए कर, शुल्क, टोल, फीस।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) को लागू करने हेतु मिलने वाले फंड।

PRI की वित्तीय समस्याएं

- **घटते आवंटन**: उत्तरोत्तर बजटों में PRI निधि में कमी, विकेंद्रीकरण का कमजोर होना।
- **बंधे (TIED) बनाम बिना-बंधे (Untied) अनुदान**: 15वें वित्त आयोग ने 60% बंधे और 40% बिना बंधे अनुदान की सिफारिश की, जिससे अनुदान का कम उपयोग हुआ।
- **चुनाव में विलंब**: कानूनी/प्रशासनिक बाधाएं (जैसे तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण का मामला) धन उपयोग रोकती हैं।
- **जिला योजना समिति का कमजोर संचालन** : समन्वय की कमी के कारण योजना निर्माण में बिखराव व फंड का पूरा उपयोग नहीं।
- **राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन में अनियमितता** : केवल 9 राज्यों ने ही छठा SFC गठित किया; इससे फंड ट्रांसफर में देरी होती है।
- **GPDP अपलोड में कमी** : ई-ग्राम स्वराज पर अनुपालन कमजोर, जिससे 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि अटकती है।
- **अपने स्रोतों से कम राजस्व (OSR)** : पंचायतों का अपना राजस्व स्रोत मात्र 1.1%, जिससे स्वायत्तता प्रभावित होती है।

PRI के लिए वित्तीय स्रोत का महत्व

- **ग्रामीण विकास** : योजनाओं को लागू करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढलने के लिए।
- **कृषि** : सहकारिता को बढ़ावा देने (जैसे अमूल), संधारणीयता को प्रोत्साहन देने।
- **SDGs** : स्थानीयकरण से 2030 के लक्ष्य पूरे करने में मदद।
- **स्वास्थ्य-देखभाल** : स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का रख-रखाव, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण; शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए।
- **शिक्षा** : विद्यालयों का निर्माण व रखरखाव हेतु; ड्रॉपआउट में कमी और गुणवत्ता सुधार करने के लिए।
- **महिला सशक्तिकरण** : 1/3 सीटें आरक्षित; अध्ययनों में स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा व कल्याण के बेहतर परिणाम दिखे।

PRI की वित्तीय सुधार हेतु पहलें

ऑडिट ऑनलाइन	खुद के राजस्व स्रोत (OSR) बढ़ाना	रैंकिंग प्रणाली	ई-ग्रामस्वराज
पंचायत खातों के डिजिटल ऑडिट के लिए	संपत्ति कर हेतु स्वामित्व (SVAMITVA); खनिज निधि साझा करना।	प्रदर्शन आधारित अनुदान।	पारदर्शिता हेतु GPDPs अपलोड।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **पुनः आवंटन लचीलापन :बंधे (TIED) अनुदान** को अन्य कार्यों में उपयोग की अनुमति; जरूरत आधारित फार्मूला (जैसे पिछड़ापन, क्षेत्रफल) के आधार पर समय पर **बिना-बंधे (Untied) अनुदान ट्रांसफर करना**।
- **चुनाव में निरंतरता**: नियमित समय पर चुनाव; देरी होने पर नामित प्रतिनिधियों को स्पष्ट अधिकार।
- **SFC का नियमित गठन** : राज्यों को समय पर SFC गठित करना, समान व सरल प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- **GPDP अपलोड सुनिश्चित करना** : पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देना ताकि GPDPs ब्लॉक/जिला योजनाओं के अनुरूप तैयार व प्रस्तुत हों।
- **पर्याप्त हस्तांतरण** : राज्यों को समयबद्ध हस्तांतरण रोडमैप बनाना होगा; स्थानीय कर्मचारियों (जैसे स्वास्थ्यकर्मी) के पदस्थापन का अधिकार हस्तांतरित करना।
  - पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) को 3F प्रगति पर **स्टेट ऑफ डिवोल्यूशन रिपोर्ट** तैयार करनी होगी।
- **खुद के राजस्व स्रोत को बढ़ाना** : वित्तीय/तकनीकी सहायता, अधिक अधिकार हस्तांतरित करना, और उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना।

1.5. अंतर्राज्यीय जल विवाद (Inter State Water Dispute : ISWD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रावी-ब्यास जल अधिकरण (1986) को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे के विवाद के निपटारे के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र ने पोलावरम बनकचेरला लिंक परियोजना और तेलंगाना–आंध्र प्रदेश जल विवाद मुद्दों पर तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया है।
- ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने महानदी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने पर सहमति जताई है।
- अंतर्राज्यीय विवाद औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं, जैसे – मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर के बीच कावेरी विवाद।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण

- **असमान पहुँच:**
  - **भौगोलिक स्थिति:** नदी के ऊपरी प्रवाह वाले राज्य लाभ की स्थिति में रहते हैं ,
  - **राज्य पुनर्गठन:** राज्य की सीमाएँ नदी घाटी को ध्यान में रखे बिना खींची गईं।

- **बढ़ती मांग:** जनसंख्या वृद्धि तथा, कृषि, शहरीकरण और अर्थव्यवस्था के विस्तार से।
- **विकास परियोजनाएँ:** बांध और परियोजनाएँ विवाद को जन्म देती हैं (जैसे – नर्मदा, कावेरी)।
- **खंडित शासन व्यवस्था:**
  - **संघ:** विवाद समाधान हेतु कमजोर संरचनाएँ।
  - **राज्य:** परस्पर विरोधी रणनीतियाँ, संकीर्ण सोच।
  - **अवैज्ञानिक:** नदी-घाटी आधारित प्रबंधन का अभाव।
  - **डेटा की कमी:** नदी प्रवाह/जल की मात्रा पर असमान और अधूरा डेटा संग्रह।
- **कानूनी और संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 262(1):** संसद विवाद निपटारे हेतु कानून बना सकती है।
  - **अनुच्छेद 262(2):** संसद द्वारा प्रावधान किए जाने पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त।
  - **अनुच्छेद 262 के तहत बनाए गए कानून:**
    - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956:** संघ सरकार राज्यों के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय नदियों को नियंत्रित करने हेतु बोर्ड गठित कर सकती है।
    - **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** राज्य के अनुरोध पर संघ अधिकरण (ट्रिब्यूनल) स्थापित कर सकता है।
  - **सातवीं अनुसूची:**
    - **संघ सूची (प्रविष्टि 56):** अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन।
    - **राज्य सूची (प्रविष्टि 17):** जल उपयोग, सिंचाई आदि (प्रविष्टि 56 की शर्तों के अधीन।

अंतर्राज्यीय जल विवाद के समाधान में चुनौतियां

- **विलंब:**
  - **अधिकरण के गठन में:** जैसे – कावेरी न्यायाधिकरण 1990 में दशकों बाद।
  - **निर्णय देने में**: नर्मदा – 9 वर्ष, कृष्णा – 4 वर्ष, गोदावरी – 10 वर्ष।
  - **अधिसूचना जारी होने/लागू होने में:** राजपत्र प्रकाशन में देरी (कृष्णा – 3 वर्ष, गोदावरी – 1 वर्ष) से अनिश्चितता।
  - **ISRWD अधिनियम, 1956:** न्यायाधिकरण का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के डिक्री के समान।
- **राजनीतिकरण:** विवादों का समाधान सामाजिक-पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी कर राजनीतिक दृष्टि से करना।
- **भागीदारी का अभाव:** स्थानीय समुदायों, राज्यों और हितधारकों को निर्णय प्रक्रिया से अक्सर बाहर रखा जाता है।
- **सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:** यद्यपि वह ऐसे मामलों में निर्णय नहीं दे सकता, लेकिन अधिकरण के फैसलों की व्याख्या करता है, जिससे विलंब होता है (जैसे – कावेरी 2007, बाद में अंतिम फैसला संशोधन के साथ)।

अन्य उपाय

- **ISRWD (संशोधन) विधेयक, 2019**
  - विवाद समाधान समिति का गठन।
  - एकल अधिकरण की स्थापना जिसमें कई पीठ हों।
  - समयबद्ध निर्णय और केंद्रीय नदी घाटी डाटाबैंक।
- **ड्राफ्ट नदी घाटी प्रबंधन विधेयक, 2018**
  - **उद्देश्य:** समानता, सहयोग, नदी बेसिन-आधारित प्रबंधन।
  - नदी बेसिन **मास्टर प्लान एवं प्राधिकरण।**
- **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना:** अतिरिक्त जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों की ओर नदी जल स्थानांतरित करके विवादों में कमी।

आगे की राह

- **सहकारी संघवाद:** संघ मध्यस्थ की भूमिका निभाए; नीति आयोग ISWD पर संवाद मंच आयोजित करे।
- **नीतिगत उपाय:** ISWD को अंतर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) के अधीन लाना; ISRWD अधिनियम, 1956 में संशोधन कर अधिकरण को प्रभावी बनाना।
- **विधायी कदम:** ISRWD संशोधन विधेयक एवं RBM विधेयक पर शीघ्र परामर्श और पारित करना।
- **डेटा प्रणाली:** राष्ट्रीय नदी डाटाबैंक; जल प्रवाह और जल उपयोग ट्रैकिंग हेतु AI का उपयोग।
- **हितधारक सहभागिता:** जल योजना/प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

1.6. भारत में राजनीति की लागत (Cost of Politics in India)

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी (WFD) के सहयोग से भारत के **"राजनीति की लागत"** पर एक केस स्टडी की, जिसमें चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **चुनाव में व्यय:** लोकसभा उम्मीदवार ₹5–10 करोड़ तक खर्च करते हैं, जो धनी/प्रतिस्पर्धी राज्यों (तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र) में अधिक है।

- **बढ़ते नियमित खर्च:** कार्यक्रमों, मतदाताओं के समर्थन और पार्टी गतिविधियों पर खर्च में वृद्धि।
- **सोशल मीडिया खर्च:** विशेषज्ञों, प्रभावशाली लोगों, विज्ञापन आदि पर धन खर्च होता है; जो रैलियों और लॉजिस्टिक्स से सस्ता है।
- **वोट खरीदना:** कैश वितरण में वृद्धि हुई है, जिसका सहारा अनिच्छुक उम्मीदवार को भी लेना पड़ता है।
- **राजनीति में व्यय के कारक:** जनसंपर्क, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, सरपरस्ती और नेटवर्क बनाए रखना।
- **फंडिंग के स्रोत:**
  - **प्रमुख:** व्यक्तिगत संपत्ति, परिवार और मित्र।
  - **अन्य:** ऋण, संपत्ति, क्राउडफंडिंग, बिजनेस ग्रुप्स।
  - पार्टियां स्वयं उम्मीदवार द्वारा फंडिंग की अपेक्षा करती हैं, जिससे समृद्ध उम्मीदवार या वंशवादी लाभान्वित होते हैं और वंचित वर्ग बाहर रह जाते हैं।

चुनावी खर्च के उच्च स्तर के प्रभाव

- **प्रशासन पर प्रभाव**
  - **व्यवसाय–राजनीति गठजोड़:** कॉरपोरेट फाइनेंसर सरकारी नीति को प्रभावित करते हैं (जैसे टैक्स छूट), जिससे असमानता बढ़ती है।
  - **फंड जुटाने को प्राथमिकता:** नेता शासन से अधिक फंड जुटाने/वसूलने पर ध्यान देते हैं।
    - **भ्रष्टाचार का जोखिम:** काले धन का प्रभुत्व चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है — भारत TI के 2024 भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वें स्थान पर है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव**
  - **विश्वास का क्षरण:** पारदर्शिता की कमी के कारण मतदाताओं का विश्वास और भागीदारी घटती है।
  - **शक्ति के साधनों पर कब्जा:** बड़ी पार्टियां अधिक धन होने के कारण वोट खरीदने और मीडिया तक पहुँच बनाने में सक्षम होती हैं, जिससे छोटी/क्षेत्रीय पार्टियाँ प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती हैं।
  - **वंचितों के लिए बाधा:** अधिक चुनावी खर्च के कारण महिलाएं, युवा और गैर-विशिष्ट लोग चुनाव नहीं लड़ पाते।

आगे की राह

- **खर्च सीमाएँ:** निर्वाचन आयोग की पर्यवेक्षण शक्ति को मजबूत करना चाहिए और न्यायिक बढ़ाना चाहिए, खर्च की अधिकतम सीमा लागू करने हेतु ब्रिटिश मॉडल लागू करना ।
- **संवैधानिक दर्जा:** राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से विनियमित करना चाहिए।
- **मत प्राप्ति के अनुसार सरकार द्वारा फंडिंग:** कॉरपोरेट के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, छोटे दलों को मदद मिलेगी (अनेक आयोगों द्वारा समर्थित)।
- **मतदाता जागरूकता:** चुनाव आयोग, मीडिया और नागरिक समाज द्वारा अभियानों के माध्यम से पैसे की ताकत सीमित किया जाना चाहिए।
- **रीयल-टाइम डोनेशन डिस्क्लोजर:** पारदर्शिता बढ़ाएं (जैसे, अमेरिकन मॉडल)।

निष्कर्ष

भारतीय चुनावी वित्त प्रणाली में **अत्यधिक खर्च, केन्द्रित संसाधन और काले धन की मौजूदगी लोकतंत्र और समानता के लिए खतरा** है। तुरंत सुधार करने और कॉरपोरेट चंदा पर कड़े कानून आवश्यक हैं।

1.7. मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कम करना (Lowering of Age for Voting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक स्तर पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, निकारागुआ जैसे कई देशों ने मताधिकार आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **यूनाइटेड किंगडम:** 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की योजना की घोषणा की।
- **भारत:** 2020 में एक संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तावित हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार आयु 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष करने का प्रस्ताव था।
  - यह एक गैर-सरकारी विधेयक था।

भारत में मताधिकार आयु से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 326)

- 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है।
- 61वें संविधान संशोधन (1988) द्वारा **मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** की गई।
- मतदान का अधिकार वैधानिक है, जिसे सामान्य क़ानून द्वारा बदला जा सकता है।

मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कम करने के पक्ष में तर्क	मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कम करने के विपक्ष में तर्क
सोचने-समझने की परिपक्वता: बहुतों का मानना है कि 16 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति स्वतंत्र रूप से राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं।	**परिपक्वता की कमी:** किशोरों में पर्याप्त ज्ञान का अभाव हो सकता है, जिससे वे किसी विचारधारा से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। **कम मतदान प्रतिशत:** 2024 में 18–19 वर्ष आयु वर्ग के 40% से भी कम लोगों ने मतदान किया।

- **पीढ़ीगत समानता:** 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को मतदान प्रक्रिया से बाहर रखने से बुज़ुर्ग मतदाताओं को लाभ होता है और भविष्य उन्मुख नीतियाँ बनाने की संभावनाएं सीमित होती हैं।
- **पार्टियों के घोषणा-पत्र का विस्तार:** इसमें शिक्षा, बाल अधिकार, लैंगिक न्याय पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा।
- **युवा भागीदारी बढ़ना:** कम आयु में मताधिकार देने से राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है और लोकतंत्र मजबूत होता है।
- **आयु सीमा को लेकर अन्य कानूनों से टकराव:** इससे अन्य कानूनों में वयस्क की आयु सीमाओं को घटाने की मांग उठ सकती है।
- **प्रशासनिक बोझ:** 16–17 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का पंजीकरण अतिरिक्त खर्च बढ़ाएगा और प्रशासनिक चुनौतियों पैदा करेगा।

निष्कर्ष

मताधिकार की आयु कम करने के पक्ष में उपलब्ध साक्ष्य का उपयोग करना चाहिए और इसमें किशोरों को शामिल करना चाहिए। स्कूलों में नागरिक संबंधी शिक्षा और निरंतर मतदाता पंजीकरण अभियान से बच्चों की अभिरुचि बढ़ेगी और इसमें युवाओं की भागीदारी भी बढ़ सकती है।

1.8. अन्य संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

1.8.1. संसद की कार्यवाही में व्यवधान (DISRUPTION OF PARLIAMENT)

17वीं लोकसभा की अवधि के दौरान **लोकसभा में 88%** और **राज्यसभा में 73%** बैठकें हुईं।

- 1950 के दशक में, संसद की **वार्षिक बैठकें 120-140 दिन** होती थीं; **अब केवल 60-70 दिन** होती हैं।

संसद की कार्यवाही में व्यवधान के कारण

- विपक्षी दल इसका उपयोग प्रचार और लोगों की नजर में आने के लिए करते हैं।
- दल-बदल विरोधी कानून सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए मजबूर करता है।
- लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले विवादास्पद राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों से व्यवधान उत्पन्न होते हैं।
- राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि बहस का समय कम होता है और गैर-सूचीबद्ध मुद्दों पर अधिक व्यवधान होते हैं।

संसद की कार्यवाही में व्यवधान से जुड़ी चिंताएं

- **जवाबदेही तय नहीं होना**: सदन की बैठक में व्यवधान बहसों और सरकार से सवाल पूछने में बाधा डालते हैं।
- **उच्च लागत:** संसद चलाने में प्रति मिनट ₹2.5 लाख का खर्च आता है।
- **घटता विश्वास:** बार-बार रुकावटें संसद में जनता के विश्वास को कम करती हैं।

संसदीय व्यवधान को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय

- **विपक्ष के लिए समय निर्धारित करना**: यूके (UK) की तरह, बहस के लिए विशेष दिनों को निर्धारित करना।
- **मज़बूत आचार समितियाँ**: व्यवधानों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए।
- **वार्षिक कैलेंडर:** आंशिक बदलाव की अनुमति के साथ वार्षिक बैठकें उसी कैलेंडर के अनुसार हों।

1.8.2. उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को पद से हटाना (REMOVAL OF JUDGES IN HIGHER JUDICIARY)

लोकसभा के 145 सांसदों ने अनुच्छेद 124, 217, 218 के तहत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

- राज्यसभा के सभापति को भी 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

न्यायाधीशों को हटाने संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 124(4):** साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना।
- **अनुच्छेद 124(5):** संसद **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968** द्वारा प्रक्रिया को विनियमित करती है।
- **अनुच्छेद 217(1)(b):** राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया से हटाना जिस प्रक्रिया से अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- **अनुच्छेद 218:** अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के प्रावधानों को उच्च न्यायालयों तक बढ़ाता है।
- हटाने की प्रक्रिया में कदम

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रियाएं

शुरुआत	लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव स्पीकर/सभापति को प्रस्तुत किया जाता है।
समिति गठन और जांच	यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो **तीन-सदस्यीय समिति (सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद)** जांच करती है। यदि न्यायाधीश को **कदाचार या अक्षमता का दोषी** पाया जाता है, तो **सदन प्रस्ताव पर विचार** करता है।
संसद की मंजूरी	प्रस्ताव को दोनों सदनों में विशेष बहुमत **(कुल सदस्यों का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत) से पारित होना चाहिए।**
राष्ट्रपति का आदेश	प्रस्ताव पारित होने के बाद, उसे **समान सत्र में** राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति **पदच्युति आदेश जारी** करता है।

ध्यान दें: संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है।

1.8.3. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (National Standards for Civil Service Training Institutes-NSCSTI)

हाल ही में, **केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (राज्य) मंत्री द्वारा NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क लॉन्च** किया गया।

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI) के बारे में

- **मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग** द्वारा इसे विकसित किया गया, ताकि प्रभावी सेवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण किया जा सके।
- **उद्देश्य:** केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत क्षमताएँ स्थापित करना, प्रबंधन उपकरणों को बढ़ाना और स्पष्ट प्रक्रियाओं के साथ क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना।

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI)

उत्कृष्टता के आठ स्तंभ

- प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन और पाठ्यक्रम डिजाइन
- फैकल्टी विकास
- संसाधन और प्रशिक्षण लक्ष्य
- प्रशिक्षु समर्थन
- डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना
- सहयोग
- प्रशिक्षण मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन
- संचालन और प्रशासन

NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क

- यह हाइब्रिड और AI संचालित शिक्षण मॉडल पेश करता है।
- सभी सरकारी प्रशिक्षण स्तरों के लिए समावेशी डिज़ाइन।
- सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों को जोड़कर सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।

1.8.4. बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक 2025

संसद ने **बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक 2025** को पारित कर दिया।

बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक 2025 के बारे में

- इस विधेयक के माध्यम से शिपिंग डाक्यूमेंट्स के लिए कानूनी प्रावधानों को अपडेट किया गया है और सरल बनाया गया है।
- यह **इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, 1856** की जगह लेगा।
- 'बिल ऑफ लैडिंग' एक मालवाहक जहाज से शिपर (shipper) को दिया गया एक डॉक्यूमेंट है जो **वस्तुओं के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण देता** है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध
(International Relations)

2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) {India-United Kingdom (UK) Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने **व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **CETA के अलावा कुछ अन्य प्रमुख सहयोग:**
  - **भारत–यूके विज़न 2035** अपनाया गया है, जो आने वाले दशक में कई क्षेत्रकों में सहयोग का मार्गदर्शन करेगा।
  - रक्षा उत्पादों के सह-उत्पादन के लिए **रक्षा औद्योगिक रोडमैप** अपनाया गया।

CETA की मुख्य विशेषताएं

- **व्यापक स्तर पर प्रशुल्क की समाप्ति और बाजार तक पहुंच**
  - भारत के लगभग संपूर्ण व्यापार बास्केट को कवर करते हुए **99% से अधिक टैरिफ लाइनें समाप्त** हो जाएंगी।
    - भारत ने अपनी **89.5% टैरिफ लाइनें खोल** दी हैं, जो **यूके के 91% निर्यात** को कवर करती हैं।
  - **संवेदनशील क्षेत्रों (**दुग्ध उत्पाद, अनाज, मिलेट्स, सोना, आभूषण) को संरक्षित किया है।
  - हानिकारक आयात वृद्धि को रोकने के लिए द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय किए गए।
- **सेवाएं:** भारतीय IT, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए व्यापक पहुँच।
- **परस्पर मान्यता और पेशेवर गतिशीलता**
  - एक वर्ष के भीतर **नर्सिंग, लेखाशास्त्र, और वास्तुकला** जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप मान्यता देंगे।
  - यू.के. भारतीय पेशेवरों और निवेशकों को **90 दिनों से लेकर 3 वर्ष तक के प्रवास** की अनुमति देता है।
  - **डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन** भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को UK में **तीन वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट प्रदान** करता है।
  - निर्यातक उत्पाद की उत्पत्ति का स्व-प्रमाणन कर सकते हैं; एक हज़ार पाउंड से कम के निर्यात के लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी; उत्पाद-विशिष्ट उत्पत्ति के नियमों (PSRs) को भारत की मौजूदा सप्लाई चेन के अनुरूप बनाया गया है आदि।

भारत-यूके विज़न 2035 (रणनीतिक साझेदारी रोडमैप)

- **2035 तक रणनीतिक विज़न:** साझेदारियां भारत-UK संबंधों को बदल देंगी, रणनीतिक लक्ष्यों, नवाचार और वास्तविक लाभों पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
- **साझेदारी फ्रेमवर्क:** छह स्तंभों (व्यापार - प्रौद्योगिकी - रक्षा - जलवायु - शिक्षा - लोगों से लोगों के बीच संबंध) पर सहयोग।
- **विकास और व्यापार:** व्यापार की मात्रा बढ़ाना, द्विपक्षीय निवेश संधि को पूरा करना, पूंजी बाजार संबंधों में सुधार करना, हरित निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार और स्टार्टअप्स का समर्थन करना।
- **प्रौद्योगिकी नवाचार:** AI/ मशीन लर्निंग 5G/6G दूरसंचार सहयोग को जोड़ती है। महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर कार्य।
- **रक्षा और सुरक्षा:** 10-वर्षीय रक्षा रोडमैप, संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी, हिंद-प्रशांत सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, आतंकवाद-रोधी और साइबर प्रयास, संयुक्त प्रशिक्षण।
- **जलवायु और ऊर्जा:** जलवायु वित्त में वृद्धि, अपतटीय पवन ऊर्जा का विस्तार, ग्रीन हाइड्रोजन का विकास, परमाणु ऊर्जा सहयोग, स्वच्छ परिवहन, पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन।
- **शिक्षा और कौशल साझेदारी:** भारत में UK के परिसर, संयुक्त डिग्रियाँ, हरित कौशल कार्यक्रम, अधिक युवा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।

भारत के लिए CETA का महत्व

- **निर्यात वृद्धि:** वस्त्र, आभूषण, मशीनरी के निर्यात में 20–40% तक बढ़ोतरी की संभावना।
- **भौगोलिक संकेत (GI) संरक्षण: फेणी, ताड़ी, नासिक वाइन जैसे GI उत्पादों** को सुरक्षा मिली।
- **बाज़ार तक पहुँच:** ब्रिटेन के 37.5 बिलियन डॉलर के कृषि बाज़ार तक पहुँच; कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के 95% से अधिक पर शुल्क (ड्यूटी) नहीं।
- **श्रमिक लाभ:** श्रमिक अधिकार सुनिश्चित; न्यायाधिकरण और प्रवर्तन प्रणाली मजबूत; महिलाओं को भेदभाव-रहित अवसर और **लैंगिक समानता** से लाभ।
- **MSME और क्षेत्रीय विकास:** व्यापार वृद्धि से तिरुप्पुर (वस्त्र), कोलकाता (चमड़ा), सूरत–भरूच (रसायन) जैसे हब को मदद।

भारत-UK संबंधों का महत्व

- **आर्थिक सहयोग:** द्विपक्षीय व्यापार 56 बिलियन डॉलर; 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य।
  - ➡ UK भारत में 6th सबसे बड़ा निवेशक है, सितंबर 2024 तक 35 बिलियन डॉलर की इक्विटी निवेश।
- **भूराजनीतिक:** UN, UNSC, G20, कॉमनवेल्थ, इंडो-पैसिफिक में सहयोग; UK भारत की UNSC स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **रक्षा सहयोग:** नियमित सैन्य अभ्यास जैसे-कोकण (नौसैनिक), कोबरा वॉरियर (वायुसेना), अजेया वॉरियर (थलसेना)।
- **भारतीय प्रवासी:** UK में **18.64 लाख भारतीय** (2021 जनगणना)।
- **शिक्षा सहयोग:** UK विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल रहे हैं; साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का गुड़गांव कैंपस नई शिक्षा नीति के तहत पहला है। **लगभग 1.7 लाख भारतीय छात्र UK** में पढ़ते हैं।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** संयुक्त रूप से **कोविड-19 वैक्सीन** (AstraZeneca और सीरम इंस्टीट्यूट) पर शोध; **भारत-UK समझौता स्वास्थ्यकर्मी भर्ती और प्रशिक्षण** में सहयोग करता है।

भारत–UK संबंधों में चिंताएं

- **विदेश नीति में मतभेद:** रूस–यूक्रेन संघर्ष पर अलग-अलग दृष्टिकोण।
- **UK की घरेलू राजनीति:** कश्मीर और भारत के आंतरिक मुद्दों पर ब्रिटेन में होने वाली बहस से तनाव पैदा होता है, जिससे प्रवासी भारतीयों के रिश्तों पर भी असर पड़ता है।
- **खालिस्तान अलगाववाद:** UK में खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों को लेकर भारत चिंतित है, जो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा मानी जाती हैं।
- **प्रत्यर्पण में बाधाएँ:** कानूनी विलंब के कारण विजय माल्या जैसे भगोड़े UK में ही रहते हैं, जिससे आपसी विश्वास प्रभावित होता है।

निष्कर्ष

भारत-UK विज़न 2035 के तहत CETA व्यापार, तकनीक, रक्षा, जलवायु और शिक्षा संबंधों को बढ़ाने वाला एक अहम पड़ाव है। UK (P5, G7, Five Eyes सदस्य) और भारत (सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था) दोनों एक रणनीतिक मोड़ पर खड़े हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी साझा क्षमताओं का लाभ उठाकर, दोनों देश साझेदारी को ऊँचाई तक ले जाने और चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में अग्रसर हैं।

2.2. भारत-मालदीव संबंध (India-Maldives Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर** प्रधान मंत्री ने मालदीव की यात्रा की।

यात्रा के मुख्य परिणाम:

- मालदीव को **4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट** की सुविधा तथा **ऋणों के वार्षिक भुगतान को कम** करने के लिए एक समझौता किया गया।
- सहमत संदर्भ शर्तों के साथ **भारत–मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (IMFTA)** पर वार्ता शुरू की गई।
- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण** के बीच मालदीव में **UPI** लॉन्च करने पर सहमति बनी।
- **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि; मौसम विज्ञान; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; भारतीय फार्माकोपिया** आदि क्षेत्रकों के संबंध में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

सहयोग के क्षेत्र

भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से **नृजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संबंध** रहे हैं। भारत मालदीव को 1965 में स्वतंत्रता मिलने के बाद उसे मान्यता देने और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था।

- **सामरिक स्थिति और निकटता:** मालदीव **पश्चिमी हिंद महासागर (अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य) और पूर्वी हिंद महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य)** के बीच एक 'टोल गेट' की तरह अवस्थित है।
  - ➡ भारत के पश्चिमी तट और हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों से इसकी निकटता मालदीव को भारत के लिए रणनीतिक महत्व प्रदान करती है।

- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** भारत को मालदीव के लिए एक **"समग्र सुरक्षा प्रदाता"** के रूप में देखा जाता है। यह भारत की **"पड़ोसी प्रथम"** और **विज़न महासागर/ MAHASAGAR का केंद्र बिंदु** है।
- **रक्षा सहयोग और सुरक्षा: 2016 के डिफेंस एक्शन प्लान** से दोनों के बीच रक्षा साझेदारी और मजबूत हुई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे **कुवेरिन और एकाथा** का आयोजन किया जाता है।
  - मालदीव **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव** का संस्थापक सदस्य भी है।
- **आर्थिक एकीकरण:** 2023 में भारत–मालदीव का द्विपक्षीय व्यापार **548.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो गया। भारत, **मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बनकर उभरा है।
- **मानवतावादी कूटनीति और "प्रथम सहायता प्रदाता":** इसमें **1988 के तख्तापलट प्रयास, 2004 की सुनामी, 2014 का माले जल संकट और कोविड-19 महामारी** के दौरान तुरंत सहायता देना शामिल है।
- **लोगों के बीच (P2P) व्यापक संबंध:** मालदीव के पर्यटन के लिए भारत अब सबसे बड़ा बाजार बन गया है। केवल 2023 में ही **2.09 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक** मालदीव गए थे

द्विपक्षीय संबंधों में उत्पन्न हालिया मुद्दे

- **आंतरिक राजनीति:** मालदीव का राजनीतिक परिवेश मुख्य रूप से *भारत-समर्थक व चीन-समर्थक* गुटों में बंटा हुआ है।
- **राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के नेतृत्व में रणनीतिक बदलाव:"इंडिया आउट कैंपेन"** के राष्ट्रवादी अभियान के बाद निर्वाचित होने के कारण **हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण रद्द करना पड़ा, भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी** जैसी घटनाएं हुईं।
  - मालदीव ने अपनी नीति को **"इंडिया फर्स्ट"** से बदलकर **"मालदीव फर्स्ट"** किया, जिसका उद्देश्य **मालदीव की विदेश नीति को विविधता** देना है।
- **चीन का प्रभाव:** मालदीव 2014 में **BRI** में शामिल हुआ और चीन ने **चाइना–मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज** जैसी कई अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया हैं।
- **आर्थिक अस्थिरता:** विश्व बैंक के अनुसार उच्च राजकोषीय घाटे और जीडीपी की धीमी संवृद्धि दर के कारण, मालदीव का सार्वजनिक ऋण 2027 तक **जीडीपी का 135.7%** होने का अनुमान है।
- **कट्टरपंथ:** साल 2023 में अमेरिका ने मालदीव में मौजूद ISIS और अलकायदा के वित्तीय सहयोगियों एवं कार्यकर्ताओं को चिन्हित (नामित) किया था।

निष्कर्ष

भारत और मालदीव सुरक्षा और विकास को प्रभावित करने वाली हिंद महासागर की चुनौतियों को साझा करते हैं; उन्हें अपने और क्षेत्र के लाभ के लिए निकट सहयोग करना चाहिए।

2.3. ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजना (China's Hydropower Project on the Brahmaputra River)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन ने **तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (भारत में ब्रह्मपुत्र) नदी पर मेडोग (मोतुओ) मेगा डैम परियोजना** का निर्माण शुरू किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- बिजली के अलावा इसका उद्देश्य **तिब्बत का औद्योगीकरण करना है**।
- चीन इस परियोजना को एक **नवीकरणीय ऊर्जा पहल और तिब्बत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन** के रूप में प्रस्तुत करता है, जो **2060 तक कार्बन तटस्थता** के उसके लक्ष्य का समर्थन करती है।

मेडोग हाइड्रोपावर परियोजना के बारे में

- **विस्तार और क्षमता:** यह थ्री गॉर्जेस बांध से **तीन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न** करेगा।
- **अवस्थिति: अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ग्रेट बेंड** पर।
- **परियोजना का डिजाइन:** यह **पांच क्रमिक (कैस्केड) हाइड्रो पावर प्लांट्स वाला रन-ऑफ-द-रिवर बांध है जो नदी के जल प्रवाह के आधे हिस्से तक** को मोड़ देगा।

परियोजना से जुड़ी गंभीर चिंताएं

- **भू-राजनीतिक चिंताएं:** नदी के प्रवाह में बाधा से **पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, खाद्य सुरक्षा और जलविद्युत परियोजनाएं** प्रभावित होंगी। **उदाहरण**- सियांग नदी आपदा (2000)।
  - दोनों देशों के बीच तनाव के समय इसे एक संभावित **वॉटर बॉम्ब** के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **जल संसाधन पर प्रतिस्पर्धा:** ब्रह्मपुत्र बेसिन में **भारत–चीन–बांग्लादेश** के बीच जल संसाधन को लेकर प्रतिस्पर्धा है, जो कि **बांध और जल के प्रवाह को मोड़ने वाली परियोजनाओं** से प्रेरित है। इससे मानव सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए आवश्यक **तलछट प्रवाह में बाधा** उत्पन्न हो सकती है। **मछलियों की लगभग 218 प्रजातियों (जैसे हिल्सा और महसीर) के समक्ष खतरा** उत्पन्न हो सकता है। इससे **20 लाख लोगों की आजीविका** खतरे में पड़ सकती है।

- **आपदा के प्रति सुभेद्यता:** यह **परियोजना भूकंप क्षेत्र V में स्थित** है, जो **भूकंप और भूस्खलन** के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। दिसंबर 2024 में तिब्बत में आए **7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने बड़े बांधों के टूटने के संभावित खतरे को उजागर** किया था।

भारत और चीन के बीच मौजूदा नदी जल सहयोग तंत्र

- **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (2006):** हर वर्ष बाढ़ के मौसम से जुड़े आंकड़ों, आपातकालीन प्रोटोकॉल और सीमा-पार नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है।
- **ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना:** एक समझौते (MoU) के तहत **जून से अक्टूबर** तक तिब्बत के तीन स्टेशनों से आंकड़े साझा किए जाते हैं। यह समझौता **2020 में समाप्त** हो गया और इसके नवीनीकरण पर वार्ता चल रही है।
- **सतलज नदी पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना:** एक स्टेशन से जून-अक्टूबर के आंकड़ों के लिए समझौता ज्ञापन; 2020 में समाप्त, नवीनीकरण लंबित है।
- **व्यापक समझौता ज्ञापन (2013):** इसके तहत **ब्रह्मपुत्र और सतलज** के आंकड़े साझा करने की अवधि **15 मई से बढ़ाकर 15 अक्टूबर** कर दी गई और यह जल संबंधी सहयोग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है।

आगे की राह

- **भारत की संभावित प्रतिक्रिया:**
  - **रणनीतिक कदम:** नीति आयोग ने **2017 में सियांग क्षेत्र** में इस तरह की **बहुउद्देशीय परियोजना** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
  - **पारदर्शिता की मांग:**भारत ने चीन से बांध के संबंध में **पारदर्शिता: तकनीकी, पर्यावरणीय, भूकंपीय योजनाओं का पूर्ण प्रकटीकरण** आदि की मांग की है; तथा समाधान न होने तक परियोजना निलंबन का दबाव बनाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय गठबंधन:** निचले प्रवाह वाले देशों को एकजुट करना चाहिए, ताकि वे **1997 के संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय** के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी जल बंटवारे के समझौते की मांग कर सकें।
- **सीमा-पार सहयोग:** भारत को **साझा नदियों पर अपने अधिकार** सुरक्षित रखने के लिए **चीन-कज़ाखस्तान जैसे समझौतों का समर्थन करना चाहिए**।
- **जल सुरक्षा ढांचा: नील बेसिन और मेकांग मॉडल** का उपयोग करते हुए, **आँकड़ों की पारदर्शिता, विवाद समाधान और आपदा तत्परता सुनिश्चित** करने के लिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा के लिए **"साउथ एशिया वाटर नाटो"** जैसे समूह के गठन का प्रयास किया जाना चाहिए।

2.4. भारत-अफ्रीका संबंध (India-Africa Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने **घाना और नामीबिया** जैसे अफ्रीकी देशों की यात्रा पूरी की तथा उन्होंने दोहराया कि **"अफ्रीका के लक्ष्य ही भारत की प्राथमिकता हैं।"**

अन्य संबंधित तथ्य

- घाना के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान **"ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना"** से सम्मानित किया।
- दोनों पक्षों ने संबंधों को और मजबूत बनाते हुए इन्हें **व्यापक साझेदारी** तक ले जाने पर सहमति बनाई।
- भारत की अफ्रीका नीति पुराने संबंधों पर आधारित है, लेकिन यह वर्तमान जरूरतों पर भी केंद्रित है। यह नीति **परामर्श आधारित और मांग-प्रधान दृष्टिकोण** अपनाती है।

भारत के लिए अफ्रीका का रणनीतिक महत्त्व

- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक:** दोनों ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग करने तथा शांति व सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
  - **उदाहरण:** अफ्रीकी संघ को G-20 की सदस्यता मिलना और एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)।
- **रक्षा क्षेत्र:** भारत और अफ्रीकी देश **इंडियन ओशन कमीशन (IOC) मिलन (MILAN), कटलैस एक्सप्रेस (Cutlass Express)** जैसे **बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों** में जुड़े हुए हैं।
  - हाल ही में **भारतीय नौसेना** ने **अफ्रीका-इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट (AIKEYME) कार्यक्रम शुरू किया**।
- **आर्थिक:** अफ्रीका **युवा बाज़ार और भारत के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज** (कोबाल्ट, मैंगनीज़) प्रदान करता है।
  - अफ्रीका के पास **वैश्विक कोबाल्ट और मैंगनीज़ का लगभग आधा हिस्सा** है।
  - भारत **अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।**
- **व्यापार:** भारत से अफ्रीका को मुख्य रूप से **खनिज ईंधन, खाद्य उत्पाद, दवाइयां** आदि निर्यात किए जाते हैं। अफ्रीका से भारत **कच्चा तेल, हीरा, तांबा** आदि का आयात करता है।
- **बाज़ार तक पहुंच:** भारत ने अपनी **टैरिफ** योजना के जरिए **अल्प विकसित देशों (LDCs) को शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुंच** प्रदान की है।
- **भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति:** भारत कई अफ्रीकी देशों को तकनीकी सहयोग, छात्रवृत्तियां और **ऑनलाइन शिक्षा एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं** प्रदान करता हैं।
- **प्रौद्योगिकी: डिजिटल कनेक्टिविटी** भारत अफ्रीकी देशों के साथ **मॉरीशस में लॉन्च की गई UPI और RuPay जैसी डिजिटल तकनीक साझा करता** है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी संभावनाएं हैं; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर परियोजनाओं में मदद करता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में मौजूद चुनौतियां

- भारत द्वारा वित्त-पोषित कई परियोजनाएं **प्रक्रियागत बाधाओं, धन वितरण की समस्याओं तथा दूर-दराज के अफ्रीकी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स** संबंधी चुनौतियों के कारण देर से पूरी हो रही हैं।
- अफ्रीकी देशों को अब तक **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।
- भारत को अफ्रीका में **चीन के तेज़ और बड़े निवेशों से प्रतिस्पर्धा का सामना** करना पड़ रहा है।
- अफ्रीका के कुछ हिस्सों में **राजनीतिक अशांति तथा संघर्ष एवं आतंकवाद, भारतीय कामगारों व निवेशों के समक्ष सुरक्षा संबंधी चिंताएं** पैदा करते हैं।

निष्कर्ष

अफ्रीका भारत की विदेश नीति का केंद्र बना हुआ है। भारत क्षमता निर्माण, स्थानीय स्वामित्व और नैतिक कूटनीति के माध्यम से स्थायी दक्षिण-दक्षिण सहयोग का लक्ष्य रखता है।

2.5. भारत-लैटिन अमेरिकी-कैरेबियाई देशों के मध्य संबंध (India Latin American and Caribbean Countries Ties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील** की राजकीय यात्रा की। साथ ही, ब्राजील के **रियो आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** में भाग लिया।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रधान मंत्री को **त्रिनिदाद और टोबैगो के "ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक"** सम्मान से सम्मानित किया गया।
- **त्रिनिदाद और टोबैगो** में **प्रवासी समुदाय की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड देने** की घोषणा की है।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC)-भारत संबंधों का महत्त्व

- **रणनीतिक:**
  - **रक्षा सहयोग:** भारत और ब्राजील ने **संयुक्त रक्षा समिति** और **2+2 वार्ता के माध्यम से संबंधों को मज़बूत किया है**।
  - **महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा: KABIL ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक्स** के अधिग्रहण के लिए वहां की कंपनी **कैमयेन (CAMYEN)** के साथ समझौता किया है। **लिथियम ट्रायंगल के पास दुनिया के 75% से अधिक लिथियम के भंडार** मौजूद हैं।
  - **खाद्य सुरक्षा: लैटिन अमेरिका विशेष रूप से खाद्य तेल और दालों** का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। **अर्जेंटीना** भारत के लिए **सोयाबीन तेल** के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:**
  - **व्यापार और निवेश:**
    - 2023-24 में इस क्षेत्र के साथ भारत का **कुल व्यापार 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया था। भारतीय कंपनियों ने **आई.टी., फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खनन, विनिर्माण और कृषि-रसायन में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का निवेश किया है।
    - भारत का MERCOSUR के साथ एक **अधिमान्य व्यापार समझौता** है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:**
    - भारत **वेनेजुएला, मेक्सिको और ब्राजील** से अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग **30% आयात करता है।**
    - भारत ने सौर और जलवायु परियोजनाओं के लिए **कैरिकॉम/ CARICOM** को **140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट** दिया है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग**
  - भारत का **अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ G-20 में तथा ब्राजील के साथ BRICS, IBSA एवं G-4 जैसे समूहों में मजबूत सहयोग है।**
  - **भारत CELAC, कैरिकॉम और सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (SICA)** के साथ सक्रिय भागीदारी और बैठकें करता है।

मर्कोसुर (MERCOSUR) के बारे में

- **परिचय:** यह लैटिन अमेरिका का एक **दक्षिणी साझा बाजार** है। MERCOSUR' स्पेनिश भाषा के **'Mercado Común del Sur'** का संक्षिप्त रूप है।
- **स्थापना: 1991** में हुई थी। इसका उद्देश्य **वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही** सुनिश्चित करना था।
- **सदस्य देश:** अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। (**वेनेजुएला** की सदस्यता फिलहाल निलंबित है)
- **एसोसिएट सदस्य:** चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पनामा, पेरू और सूरीनाम।
- **मुख्यालय:** मोंटेवीडियो (उरुग्वे)।

चुनौतियां

- चीन ने लैटिन अमेरिका के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और 2000 के बाद से दोनों के मध्य व्यापार में 35 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **मर्कोसुर** के भीतर **आंतरिक मतभेद** हैं। जैसे- **ब्राजील और उरुग्वे** द्विपक्षीय समझौते करना चाहते हैं, वहीं **अर्जेंटीना** इससे **बाहर निकलने** की धमकी देता है।

- भौगोलिक दूरी की सीमा के **कारण परिवहन लागत अधिक** है।
- लैटिन अमेरिका को अक्सर भारत की विदेश नीति के **तीन मुख्य दायरों के सबसे आखिरी हिस्से** में रखा जाता है।
- **अन्य कारण:** भाषा संबंधी बाधा, प्रभावशाली प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) का अभाव आदि।

आगे की राह

- **राजनीतिक संवाद को प्राथमिकता देना** और लैटिन अमेरिका को विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए।
- **आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए** टैरिफ (शुल्क) कम करने; विनियमों को सरल बनाने और **मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना** चाहिए।
- **कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए** सीधे समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग और एयर फ्रेट कॉरिडोर्स विकसित करने चाहिए।
- **तकनीकी सहयोग का विस्तार** जा सकता है।
- व्यापार मिशनों, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और निवेश प्रोत्साहनों के माध्यम से **निजी क्षेत्र को सक्रिय करना** चाहिए।

निष्कर्ष

भारत व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करते हुए तथा लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियों को हल करते हुए, लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को **एक सक्रिय एवं बहुआयामी रणनीति** से मजबूत बना सकता है।

2.5.1. भारत-ब्राजील (India-Brazil)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **"ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस"** भी प्रदान किया गया।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते

- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग** पर समझौता।
- डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर **डिजिटल तकनीकों के आदान-प्रदान** पर समझौता ज्ञापन।
- **गोपनीय जानकारी के आदान-प्रदान और उनकी सुरक्षा** को लेकर समझौता।
- **नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और बौद्धिक संपदा पर समझौता** ज्ञापन किया गया।
- व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर नज़र रखने के लिए **मंत्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना** की भी घोषणा की गई।

अगले दशक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र: रक्षा व सुरक्षा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन, आदि।

भारत–ब्राज़ील संबंधों के बारे में

- **द्विपक्षीय सहयोग:** 2006 से रणनीतिक साझेदारी।
- **वैश्विक सहयोग:** दोनों देश बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS, BASIC, G-20, G-4, IBSA और बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे UN, WTO, UNESCO, WIPO में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- **व्यापार:** 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 12.20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा और भारत को इसमें व्यापार अधिशेष रहा।
- **रक्षा सहयोग:** 2006 के समझौते से संयुक्त रक्षा समिति का गठन किया गया।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** ब्राज़ील ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की सह-स्थापना की और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) समझौते की पुष्टि की।

2.6. ब्रिक्स रियो डी जनेरियो घोषणा-पत्र (BRICS RIO DE Janeiro Declaration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स नेताओं ने **"अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना** शीर्षक से **रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए।

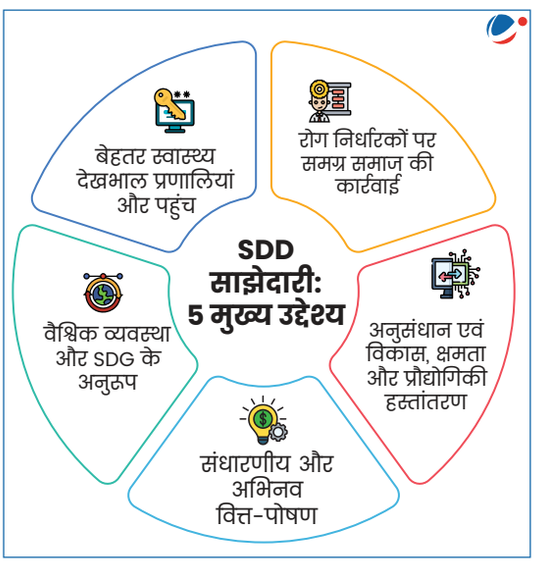

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु

- **भागीदारी:** इसमें **11 पूर्ण सदस्य देश** और 10 साझेदार देश तथा आठ आमंत्रित राष्ट्रों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  - **ब्रिक्स के नए सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत** किया गया, साथ ही बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को **ब्रिक्स साझेदार** देशों के रूप में शामिल किया गया।
- **सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों के उन्मूलन हेतु साझेदारी की शुरुआत:** इसका उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना, संसाधन जुटाना और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में एकीकृत तरीके से SDDs को खत्म करने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
- **ब्रिक्स नेताओं का 'जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क:** यह अगले पांच वर्षों के लिए एक ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो ब्रिक्स की क्षमता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में स्थानांतरित कर सके।

- **ब्रिक्स नेताओं का 'AI के ग्लोबल गवर्नेंस पर घोषणा-पत्र':** इसके प्रमुख सिद्धांतों में डिजिटल संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र-आधारित बहुपक्षवाद, जिम्मेदारीपूर्ण विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय संधारणीयता और भरोसेमंद/ नैतिक AI शामिल हैं।

ब्रिक्स नेताओं का 'जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा-पत्र'

- **जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य:** विकसित देशों से 2035 तक विकासशील देशों को **प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** प्रदान करने, तथा **2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक** लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया गया है।
- **नए वित्तीय साधन:** यह मिश्रित वित्त, गारंटी, बीमा कवरेज, प्रासंगिक थीमेटिक बॉण्ड, विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण तथा विनियामकीय व्यवस्था का समर्थन करता है।
- **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड (TFFF):** यह TFFF को उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक वित्त पोषण जुटाने की एक नई व्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। इस फंड की शुरुआत **संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28** में हुई थी।
  - इस **फंड में सरकारी निवेश और निजी पूंजी, दोनों को जोड़ा जाएगा**, जिससे हर साल लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
  - भुगतान को **प्रत्येक देश के संरक्षित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन क्षेत्र के अनुपात में आवंटित** किया जाएगा।

ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ सहयोग

रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा के लिए ब्रिक्स के सामूहिक संकल्प को रेखांकित करता है।

- **ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत बनाना:** घोषणा-पत्र **वैश्विक निर्णयों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र के नेताओं के पारदर्शी चयन और ब्राज़ील व भारत का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुधारों**
- **बहुध्रुवीयता और ग्लोबल साउथ की भूमिका:** घोषणा-पत्र भू-राजनीतिक तनावों, आर्थिक मंदी, तकनीकी परिवर्तन और संरक्षणवाद के बीच ग्लोबल साउथ की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- **ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (BWIs) में सुधार:** घोषणा-पत्र में शासी संरचना में सुधार करने, योग्यता-आधारित और समावेशी चयन प्रक्रियाओं को अपनाने तथा अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है।
- **व्यापार प्रणाली:** यह एकतरफा टैरिफ्स में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करता है, साथ ही इसमें विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अपने केंद्र में रखते हुए खुले, पारदर्शी, निष्पक्ष, सर्वसम्मति-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समर्थन को दोहराया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग:** घोषणा-पत्र में निवेश जोखिम को कम करने के लिए **ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2030** और **ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी** पायलट पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष

रियो घोषणा-पत्र, ब्रिक्स को वैश्विक मुद्दों से निपटने और **समानता, सहयोग और साझा समृद्धि** पर आधारित एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, जो वैश्विक शासन के भविष्य को आकार देगा।

2.7. AUKUS के तहत गीलोंग ट्रीटी (Geelong Treaty Under AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑस्ट्रेलिया और UK ने **AUKUS के पिलर-1** के तहत अगले 50 वर्षों के रक्षा सहयोग के लिए **गीलोंग ट्रीटी** हस्ताक्षर किए है।

गीलोंग ट्रीटी के बारे में

- इसे **न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलेबरेशन ट्रीटी** के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य यूरो-अटलांटिक और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- **उद्देश्य: SSN-AUKUS** पनडुब्बियों के **डिजाइन, निर्माण, परिसंचालन, रखरखाव और डिस्पोजल पर व्यापक सहयोग** बढ़ाना तथा **मजबूत त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखलाओं** के विकास को बढ़ावा देना।
- यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार के दायित्वों और त्रिपक्षीय **AUKUS नौसैनिक परमाणु प्रणोदन समझौता** के अनुरूप है।

AUKUS के बारे में

- यह **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच **2021** में शुरू किया गया एक सुरक्षा समझौता है।
- **इसके निम्नलिखित दो पिलर हैं:-**
  - **पिलर 1:** इस पिलर के तहत ऑस्ट्रेलिया को उसकी **पहली SSN सब-मरीन (परमाणु संचालित अटैक सबमरीन)** भी मिलेगी।
  - **पिलर 2:** इसमें ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध, मॉडलिंग, सिमुलेशन जैसी **8 एडवांस सैन्य क्षमताओं का संयुक्त विकास** शामिल हैं।
- इसके तहत **2030 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां बेचेगा**। **यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से नई पनडुब्बियों का निर्माण** करेंगे, जो **2040 के दशक की शुरुआत में सेवा** में शामिल की जाएंगी।

AUKUS का सामरिक महत्त्व

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली को मजबूत करता है**; इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और उपस्थिति को बढ़ाता है**।
- ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को हथियारों की बिक्री और तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से **अमेरिकी रक्षा उद्योग को बढ़ावा** देता है।

AUKUS के समक्ष अवसर और चुनौतियां क्या-क्या हैं?

AUKUS के समक्ष अवसर	AUKUS से जुड़ी चिंताएं
AUKUS देशों के बीच आपसी विश्वास का स्तर बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए- **फ़ाइव आइज़ एलायंस**।	अमेरिका **AUKUS की समीक्षा** कर रहा है; उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया रक्षा खर्च बढ़ाएगा ताकि बोझ साझा किया जा सके।
यह **QUAD को पूरक बनाता** है क्योंकि QUAD सॉफ्ट पावर पर ध्यान देता है, जबकि AUKUS इंडो-पैसिफिक में हार्ड पावर पर।	AUKUS, **QUAD की प्रासंगिकता को कमजोर** कर सकता है; भारत की अनिच्छा को अक्सर QUAD की सैन्य क्षमता की सीमा माना जाता है।
चीन की चुनौती के बीच **अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा को भागीदार देशों को सशक्त बनाकर** आगे बढ़ा रहा है।	पर्यवेक्षकों का तर्क है कि AUKUS पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाला समूह है क्योंकि **इसमें एशियाई देशों की भागीदारी नहीं** है, जबकि QUAD में एशियाई देशों का भी प्रतिनिधित्व है।
UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामंजस्य, उनकी **रक्षा रणनीतियों को मजबूत** करता है।	**आपूर्ति समस्या:** अमेरिका की पनडुब्बी उत्पादन क्षमता (1.13 प्रति वर्ष) AUKUS की ज़रूरत से कम है।
परमाणु पनडुब्बियाँ पारंपरिक पनडुब्बियों से **तेज़ (~20 नॉट्स) और लंबे समय तक चलने** वाली होती हैं।	AUKUS समझौता प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ और परमाणु प्रसार को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

भारत के पास अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ अपने विशेष संबंध विकसित करने का एक खास अवसर है। यह भारत की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करेगा और साथ ही, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में इसके योगदान को भी बढ़ाएगा।

2.8. गिरमिटिया समुदाय (Girmitiya Community)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की हालिया त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत सरकार गिरमिटिया समुदाय का एक डेटाबेस तैयार करने तथा नियमित अंतराल पर विश्व गिरमिटिया सम्मेलनों का आयोजन करने की दिशा में कार्य कर रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय मूल के प्रवासियों की छठी पीढ़ी को भी **OCI कार्ड** की सुविधाएँ देने की घोषणा की गई।
- त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत की **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** प्रणाली को अपनाया है।

गिरमिटिया के बारे में

- गिरमिटिया भारतीय मजदूर थे जो 19वीं शताब्दी में **ब्रिटिश दासता उन्मूलन अधिनियम 1833** के कारण श्रमिकों की कमी के बाद पलायन कर गए थे।
  - **"गिरमिट"** शब्दावली वास्तव में अंग्रेजी शब्द **"एग्रीमेंट"** का अपभ्रंश उच्चारण है।
  - इन्हें गन्ना और चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया था। इनमें से अधिकतर श्रमिक प्रवास वाले देश में स्थायी रूप से बस गए।
- **प्रमुख गंतव्य देश:** मॉरीशस, फिजी, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियन देश (विशेषकर त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका)।
- **जहां से प्रवास कर गए:** अधिकतर श्रमिक तत्कालीन पूर्वी संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) और बिहार के निवासी थे।
  - **प्रवास के कारण:** गरीबी, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी घरेलू आर्थिक मजबूरियों के साथ-साथ उपनिवेशों में आय के बेहतर स्रोत और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद।
  - हालांकि, उपनिवेशों में, इनको **गरीबी, मजदूरी, भोजन और स्वच्छ पानी की कमी का सामना** करना पड़ा।
  - इसी दौरान **मद्रास, नागापट्टम और थोंडी से तमिल श्रमिकों को सीलोन, बर्मा और मलेशिया** भेजा गया।

भारत के लिए गिरमिटिया समुदाय का महत्त्व

- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा सूरीनाम जैसे देशों में वे बहुसंख्यक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रीति-रिवाज स्थानीय संस्कृति के साथ गहन रूप से एकीकृत हो गए।
  - **पर्व-त्योहार:** फिजी में दिवाली और रामलीला का आयोजन तथा त्रिनिदाद और टोबैगो का होसे उत्सव इसके जीवंत उदाहरण हैं।
  - **लोक संगीत:** उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोकगीत आज भी फिजी और सूरीनाम में लोकप्रिय हैं।
  - **वाद्ययंत्र:** ढोलक, हारमोनियम, धनताल और दण्डताल जैसे पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का उपयोग आज भी प्रचलित है।
  - **भाषाएं:** हिंदी, भोजपुरी और अवधी जैसी भाषाएँ आज भी संवाद का माध्यम हैं।

- **राजनीतिक महत्व:**
  - **संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों में सॉफ्ट पावर कूटनीति** के रूप में।
  - गिरमिटिया देशों में भारतीय मूल के लोग शासन के सर्वोच्च पदों तक पहुँचे हैं, जैसे मॉरीशस तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री।
- **आर्थिक महत्व:** प्रवासी समुदाय भारत के लिए परोपकारी कार्यों, सूचनाओं के आदान-प्रदान, नवाचार में निवेश और विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु समर्थन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, **वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मॉरीशस का योगदान 17% रहा।**

निष्कर्ष

भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में गिरमिटिया इतिहास को सम्मिलित करने का नया प्रस्ताव अत्यंत सराहनीय कदम है। यह कदम न केवल उनकी अनूठी **संस्कृति, कला और संघर्षपूर्ण इतिहास को संरक्षण** प्रदान करेगा, बल्कि भारत के व्यापक सांस्कृतिक धरोहर में इस समुदाय के अमूल्य योगदान को भी रेखांकित करेगा।

2.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.9.1. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (Kaladan Multimodal Transit Transport Project: KMTTP)

केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री के अनुसार KMTTP 2027 तक चालू होगा।

- इस प्रोजेक्ट को **भारत** और **म्यांमार** ने मिलकर तय किया है। यह प्रोजेक्ट भारत के **पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार होते हुए भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER)** तक सामान पहुंचाने के लिए एक **मल्टी-मॉडल** परिवहन सुविधा प्रदान करेगा।

KMTTP के बारे में

- इस पर **2008 में हस्ताक्षर** किए गए थे।
- **नोडल मंत्रालय:** विदेश मंत्रालय।
- **प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट (PDC):** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)।
- **पारगमन घटक :**
  - **जलमार्ग घटक:** कलादान नदी पर तथा **सित्तवे बंदरगाह (राखिन, म्यांमार) से म्यांमार में पलेत्वा** तक।
  - **सड़क घटक:** पलेत्वा से लेकर **मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर जोरिनपुई** तक।

भारत के लिए KMTTP का महत्त्व

- यह प्रोजेक्ट इस अलगाव को कम करेगा। "चिकन्स नेक" कॉरिडोर पर निर्भरता कम करते हुए **पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक अलगाव को समाप्त** करता है।
- पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क के लिए **यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (AEP) के अनुरूप है।**
- **कोलकाता से आइज़ोल (मिजोरम)** तक सामान पहुंचाने में लगने वाला **खर्च और समय 50% से भी ज्यादा कम** हो जाएगा।
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक **व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित** करता है, जिससे व्यापार और निर्यात उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (NER) के लिए अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना:** यह **मोरेह (मणिपुर, भारत) को म्यांमार होते हुए माए सॉट (थाईलैंड)** से जोड़ता है।
- **प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वॉटर ट्रांजिट एंड ट्रेड (PIWT&T):** यह **भारत और बांग्लादेश** के बीच एक समझौता है। इसके तहत एक **देश के आंतरिक जलमार्ग पोत दूसरे देश के तय जलमार्गों** पर चल सकते हैं।
- **अन्य: बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN)** मोटर यान समझौता; **बांग्लादेश के चटग्राम और मोंगला बंदरगाहों** के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) आदि।

2.9.2. US ने UNESCO से बाहर निकलने का फैसला किया (US Decides to Pull Out of UNESCO)

इस संस्था से बाहर होने की घोषणा यह कहते हुए की गई कि यह संस्था तथाकथित **"उत्तेजक" और विभाजनकारी मुद्दों का समर्थन** करती है। अमेरिका ने इस संस्था पर 'इजरायल विरोधी रुख' अपनाने का भी आरोप लगाया है।

- यह **तीसरी बार** है, जब अमेरिका UNESCO से अलग हो रहा है तथा वर्तमान राष्ट्रपति के नेतृत्व में यह **दूसरी बार** है।
- अमेरिका ने अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों, जैसे WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) से बाहर निकलने के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही, **फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के लिए धनराशि में भी भारी कमी** की है।

अमेरिका के हटने के प्रभाव

- **बजटीय प्रभाव:** अमेरिका यूनेस्को के कुल बजट में लगभग **8% का योगदान** देता है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** अन्य शक्तियों, **विशेष रूप से चीन** द्वारा प्रभाव बढ़ाने की संभावना बन सकती है।
- **बहुपक्षवाद पर प्रभाव:** किसी संयुक्त राष्ट्र संस्था से बाहर निकलना **बहुपक्षीय संस्थाओं पर विश्वास कमजोर** कर सकता है।

यूनेस्को/ UNESCO) के बारे में

- यह **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है।
- **उद्देश्य:** शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति एवं सुरक्षा में योगदान देना।
- इसका मुख्यालय **पेरिस** में स्थित है।
- इसके **194 सदस्य देश** और **12 एसोसिएट सदस्य** हैं।
- **प्रमुख रिपोर्ट्स और पहलें:**
  - वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट;
  - विश्व में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास की प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट;
  - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल;
  - ह्यूमन एंड बायोस्फियर (MAB) कार्यक्रम

2.9.3. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (Group of FriendS: GOF)

भारत ने **"ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF)" की बैठक** में **'संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों' के खिलाफ** किए गए अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF)' क्या है?

- यह **भारत के नेतृत्व** में गठित एक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ होने वाली **सभी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करने में मदद करना** है।
- इसे **2022 में शुरू** किया गया।
- यह समूह **'यूनाइटेड नेशन अलायन्स ऑफ सिविलाइजेशन' (UNAOC)** की एक प्रमुख शक्ति है और उसकी रणनीतिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.9.4. पैक्ट फॉर फ्यूचर (Pact for Future)

भारत ने **संयुक्त राष्ट्र (UN) संवाद** के दौरान **'पैक्ट फॉर फ्यूचर'** के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

'पैक्ट फॉर फ्यूचर' के बारे में

- इसे **2024 में "समिट ऑफ़ द फ्यूचर"** में अपनाया गया।
- **इसमें शामिल हैं:**
  - **ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट**: यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के लिए **पहला व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क** है, और
  - **डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशन्स।**
- **मुख्य विशेषता: मानवाधिकार, लैंगिक समानता और सतत विकास पर विशिष्ट प्रतिबद्धताएं है।**
- **प्रतिबद्धताओं के प्रमुख क्षेत्र है:**
  - सतत विकास और विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन,
  - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा,
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी; इनोवेशन और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग,
  - युवा और अगली पीढ़ियां, और
  - ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव।

2.9.5. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

यूक्रेन 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' की स्थापना करने वाली **रोम संविधि** का **125वां पक्षकार राष्ट्र** बन गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय' के बारे में

- यह **पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** है, जो ऐसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजन करता है जिन पर नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे **गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा** हुआ होता है।
- इसकी स्थापना **रोम संविधि** के तहत हुई थी, जिसे **1998 में अपनाया** गया और **2002 में लागू** किया गया।
- **भारत रोम संविधि का पक्षकार देश नहीं** है।
- **मुख्यालय:** हेग (नीदरलैंड)।

2.9.6. E3 देश (E3 Countries)

हाल ही में **अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध** के बीच, **E3 देशों** ने ईरान को स्नैपबैक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है।

- स्नैपबैक प्रतिबंध (2015 के **संयुक्त व्यापक कार्य योजना**के तहत ऐसे प्रावधान है, जिनके अनुसार अगर ईरान अपने परमाणु समझौतों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लगाया जा सकता है।

E3 देश कौन हैं?

- **E3** एक **अनौपचारिक सुरक्षा सहयोग** है। इसमें **UK, जर्मनी और फ्रांस** शामिल हैं।
- E3 की पहली बैठक **2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले** के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य इराक के लिए एक **त्रिपक्षीय रणनीति तैयार करना**, और ईरान से उत्पन्न हो रहे **परमाणु खतरे को रोकना** है।

2.9.7. ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2025 (Global Peace Index, 2025)

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) का 19वां संस्करण जारी किया गया।

ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के बारे में:

- इसमें **163 देशों** को शामिल किया गया है।

- यह **3 क्षेत्रों में 23 संकेतकों का उपयोग करता है:**
  - समाज में सुरक्षा और संरक्षा का स्तर;
  - देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों की स्थिति; तथा
  - सैन्यीकरण की मात्रा।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - दुनिया में शांति का औसत स्तर पहले से और ज्यादा खराब हुआ है।
  - **दक्षिण एशिया**, दुनिया का **दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र** रहा और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।
  - **रैंकिंग:** आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत को 115वां स्थान मिला है। रूस (163वां स्थान) सबसे कम शांतिपूर्ण देश है।

2.9.8. लाल सागर (Red Sea)

लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर नए हमले हुए हैं, और यमन के **हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को डुबोने का दावा** किया है।

लाल सागर के बारे में

- **यह हिंद महासागर** के उत्तर-पश्चिम में मौजूद एक सीमांत सागर है।
- यह **बाब अल मन्देब** जलडमरूमध्य के माध्यम से **अदन की खाड़ी से** और **स्वेज नहर** के माध्यम से **भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।**
- **तटीय देश:**
  - पश्चिम में: **मिस्र, सूडान और इरीट्रिया,**
  - उत्तर-पूर्व में: **इजरायल और जॉर्डन-अकाबा की खाड़ी के माध्यम से,** तथा
  - पूर्व में: **सऊदी अरब और यमन**।
- **उत्तरी भाग में विभाजन:** यह उत्तरी भाग में दो भागों में विभाजित हो जाता है, **स्वेज की खाड़ी** (उत्तर-पश्चिम) और **अकाबा की खाड़ी** (उत्तर-पूर्व)।
- इसमें **विश्व का सबसे अधिक खारा समुद्री जल पाया जाता है।**
- लाल सागर क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती **है** तथा इसमें **नदियों के माध्यम से जल भी नहीं** पहुँचता है।

2.9.9. न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia)

फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की है।

- इस समझौते के अनुसार, न्यू कैलेडोनिया को **फ्रांसीसी गणराज्य** के भीतर **"ए स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया"** का दर्जा मिलेगा इससे इस क्षेत्र को **अधिक स्वायत्तता** मिलेगी, लेकिन **पूर्ण स्वतंत्रता नहीं** मिलेगी।

न्यू कैलेडोनिया के बारे में

- यह प्रशांत महासागर में एक **फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र** है।
- 1840 के दशक के दौरान, इन द्वीपवासियों को **गुलाम बनाया गया;** 1853 में फ्रांस ने इस **द्वीप को अपने अधीन** कर लिया।
- **वर्तमान स्थिति:** इस द्वीप के **देशज कनक (Kanak) समुदाय** और **यूरोपीय निवासियों के बीच** स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर गहरा मतभेद है।

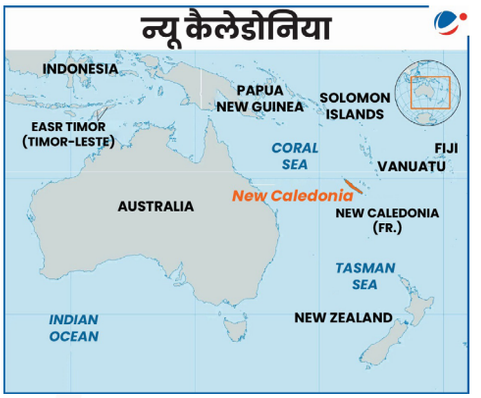

2.9.10. M23 विद्रोही (M23 Rebels)

हाल ही में, **रवांडा समर्थित M23 विद्रोही समूह** और **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** ने पूर्वी कांगो में स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्धता जताई।

M23 विद्रोहियों के बारे में

- **M23** को **'मार्च 23 मूवमेंट'** भी कहा जाता है। **यह मुख्य रूप से तुत्सी नृजातीय समुदाय का सशस्त्र विद्रोही समूह** है।
- यह समूह खनिज संसाधन समृद्ध **पूर्वी DRC** में **कांगो सेना** के खिलाफ लड़ रहा है।
- इसका नाम **CNDP (तुत्सी नेतृत्व वाली) और कांगो सरकार के बीच 2009 में** हुए समझौते के नाम पर रखा गया है।
- CNDP के पूर्व सदस्यों ने 2009 के समझौते के क्रियान्वयन में **विफलता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा**, और **संसाधनों के समान वितरण** के मुद्दों को लेकर वर्ष 2012 में **M23 मूवमेंट** की शुरुआत की।

2.9.11. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 (Henley Passport Index 2025)

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग **85 (2024)** से सुधरकर **77 (2025)** हो गई है।

- भारतीय नागरिक अब पहले से **वीजा प्राप्त किए बिना 59 देशों की यात्रा** कर सकते हैं।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

- यह दुनिया के सभी पासपोर्ट्स की एक **प्रामाणिक और मूल रैंकिंग** है, जो यह दर्शाती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक **कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के** यात्रा कर सकता है।
- यह रैंकिंग **अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA)** के विशेष डेटा पर आधारित होती है।
- **सिंगापुर इस सूचकांक में शीर्ष स्थान** पर है।

3.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना {Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025–26 की घोषणा के अनुरूप, PMDDKY को छह वर्षों की अवधि के लिए मंज़ूरी दी गई है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **बजटीय आवंटन:** छह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपये।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **कार्यान्वित तथा तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से निगरानी की जाती है - राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण निकाय**, राज्य स्तरीय नोडल समितियां, तथा **नीति आयोग की समीक्षा के साथ जिला धन धान्य समितियां।**
- **सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना और योजनाओं में समन्वय: केंद्रीय, राज्य** योजनाओं और स्थानीय साझेदारियों को समेकित करता है।
- **प्रगति ट्रैकिंग** : 117 **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI)** के आधार पर निगरानी की जाएगी।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली।
- **जिलों का चयन एवं मानदंड: नीति आयोग कम फसल उत्पादकता, सामान्य फसल-गहनता, ऋण पहुंच, भौगोलिक प्रतिनिधित्व** के आधार पर 100 जिलों को अंतिम रूप देगा ।

PMDDKY का महत्व

- **उच्च उत्पादकता वाले बीज**, जैव-उर्वरक और सीड ड्रिल जैसे मशीनीकृत उपकरणों तक पहुंच प्रदान करता है।
- विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियाँ ।**
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** और नाबार्ड (NABARD) के माध्यम से **सब्सिडी और ऋण की सुविधा।**
- **ग्राम एवं ब्लॉक स्तर पर गोदामों** और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उच्च मूल्य वाली फसलों में **विविधीकरण को बढ़ावा देना , e-NAM आदि जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से किसानों को खरीदारों से सीधे जोड़ा जाएगा।**
- **जैविक खेती**, जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना।
- **इसमें कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** , कृषि विश्वविद्यालयों की कार्यशालाएं, विदेशी प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

3.2. भारत में सार्वजनिक ऋण (Public Debt in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी **द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2025** में भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते सार्वजनिक ऋण को रेखांकित किया है।

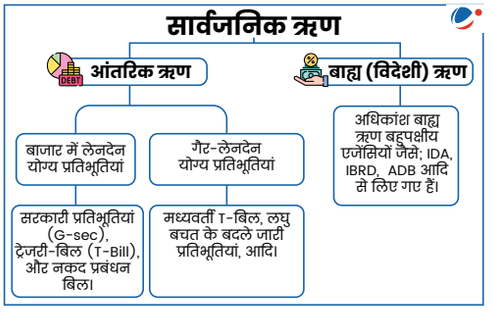

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत की वास्तविक GDP संवृद्धि दर, **2025-26 में 6.5%** रहने का अनुमान है।
- **मुद्रास्फीति संबंधी रुझान:** मध्य पूर्व में तनाव **से आयातित मुद्रास्फीति की चिंताओं के साथ मई 2025 में** CPI आधारित मुद्रास्फीति दर 2.8% थी जो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है।
- **बढ़ता सार्वजनिक ऋण: 2024 में** भारत का सार्वजनिक ऋण **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का 80% से अधिक रहा है जो अन्य **उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs)** की तुलना में काफ़ी अधिक है।

भारत में सार्वजनिक ऋण के बारे में

- **सार्वजनिक ऋण** को 'राष्ट्रीय ऋण' भी कहते हैं। यह **सरकार** तथा **सार्वजनिक क्षेत्रक की अन्य संस्थाओं** द्वारा निजी क्षेत्र और विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण की कुल संचित राशि है।
  - भारत के कुल सार्वजनिक ऋण 18,174,284 करोड़ रुपये में से **96.59% आंतरिक** और **3.41% बाह्य ऋण** है।
- **उच्च सार्वजनिक ऋण का प्रभाव** : ब्याज भुगतान की राशि बढ़ जाती है, सार्वजनिक व्यय के लिए वित्तीय संसाधन कम पड़ जाते हैं, मुद्रास्फीति दर बढ़ सकती है, निजी निवेश कम हो सकता है और आर्थिक संवृद्धि कम हो सकती है और आने वाली पीढ़ी पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।

भारत में सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का विधिक फ्रेमवर्क

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** इसके तहत 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को GDP के 40% और **कुल सार्वजनिक ऋण** को **GDP के 60%** तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2024-25 तक **सकल घरेलू उत्पाद का 10%** ।
- **RBI अधिनियम, 1934**: RBI को केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का दायित्व दिया गया है।

भारत में उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण

- **लगातार राजकोषीय घाटा, सब्सिडी** , वेतन और पेंशन भुगतान आदि के कारण उच्च राजस्व व्यय, बाह्य **ऋण वृद्धि** (2024 में 668.8 बिलियन डॉलर से 2025 तक 10% बढ़कर 736.3 बिलियन डॉलर), **महामारी के दौरान व्यय।**

सार्वजनिक ऋण को प्रबंधित और कम करने के लिए आगे की राह

- 31 मार्च, 2031 तक ऋण-GDP अनुपात को **50±1 %** तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।
- **बांड स्विचिंग के माध्यम से सक्रिय ऋण प्रबंधन:** छोटी अवधि के सॉवरेन बांडों को लंबी अवधि के बांडों से प्रतिस्थापित करना।
- **सब्सिडी युक्तिकरण और कर सुधार।**
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना।

3.3. भारत में लोगों की रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास (Employability and Skilling in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI)** को मंज़ूरी दी है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** केंद्रीय बजट **2024-25 में घोषित।**
- **नोडल मंत्रालय** : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता में वृद्धि, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना।
- **लक्ष्य** : 3.5 करोड़ नौकरियाँ (पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों सहित)
- **भाग A- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन:**
  - **पात्रता:** पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी जो EPFO में पंजीकृत हैं; 1,00,000 रुपये तक वेतन वाले।
  - **लाभ:** एक महीने की EPF पारिश्रमिक (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किस्तों में भुगतान किया जाता है: 6 महीने के बाद और 12 महीने के बाद।
- **भाग B- नियोक्ताओं को सहायता** :
  - **नियोक्ता पात्रता** : EPFO- पंजीकृत प्रतिष्ठान।
  - **अतिरिक्त नियुक्ति के लिए लाभ** : प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए वित्तीय सहायता-कम से कम 6 महीने नौकरी पर रहने की स्थिति में ।
  - **नियोक्ताओं को प्रोत्साहन** : 2 साल के लिए; प्रति कर्मचारी 1,000 रुपये-3,000 रुपये; विनिर्माण क्षेत्रक को अतिरिक्त 2 साल का समर्थन।

भारत में रोजगार और कौशल विकास के बारे में

- **रोज़गार प्राप्ति क्षमता (Employability)**: 2024 में **50% से अधिक स्नातक** (**पुरुषों में 53.47%** और **महिलाओं में 46.53%**) रोज़गार प्राप्ति कौशल रखते हैं, जो एक दशक पहले 33% था। इस तरह 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। (भारत कौशल रिपोर्ट 2025)।

भारत में रोज़गार-प्राप्ति क्षमता और कौशल विकास के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियां

- **शिक्षा व्यवस्था और उद्योग जगत की मांग में असंगति।**
- **ऑटोमेशन का ख़तरा:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है।
- **सॉफ्ट स्किल के विकास पर कम ध्यान देना।**

रोज़गार प्राप्ति क्षमता बढ़ाने और कौशल विकास के लिए प्रमुख पहलें

- **स्किल इंडिया मिशन (SIM):** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 का गठन।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) प्लेटफॉर्म:** इसे कौशल, शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया।
- **इंडिया स्किल्स एक्सीलरेटर** : यह केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय **(MSDE)** द्वारा **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** के सहयोग से शुरू किया गया है।

3.4. फ्यूचर ऑफ वर्क (The Future of Work)

सुर्ख़ियों में क्यों?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा हाल ही में **12,000 कर्मचारियों की छंटनी** की घोषणा ने **'फ्यूचर ऑफ वर्क'** पर विमर्श बढ़ा दिया है।

छंटनी (Layoffs) के बारे में

- छँटनी का मतलब है कि एक नियोक्ता द्वारा अलग-अलग कारणों (जैसे कोयले, बिजली या कच्चे माल की कमी या प्राकृतिक आपदा आदि) से अपने कर्मचारियों की सूची में शामिल **किसी कर्मचारी का रोज़गार जारी रखने में विफलता या इनकार करना है।**
- कई **बहुराष्ट्रीय निगमों ने** इस वर्ष दुनिया भर में **1,05,000** से अधिक पदों पर छंटनी की है ।
- **छंटनी से संबंधित कानूनी प्रावधान** : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, चार श्रम संहिताएँ।

'फ्यूचर ऑफ वर्क' के बारे में

- **'फ्यूचर ऑफ वर्क'** वास्तव में उस बदलाव को दर्शाता है, जिसमें तकनीकी, आर्थिक और जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण कार्य करने, संगठित होने और कार्य अनुभव का तरीका बदल रहा है।
- **फ्यूचर ऑफ वर्क के प्रमुख चालक** : आर्थिक अनिश्चितता, कौशल अंतराल, जनसांख्यिकीय बदलाव (वृद्धावस्था, नया कार्यबल), रोजगार सृजन, भू-आर्थिक विखंडन (रूस-यूक्रेन युद्ध आदि), हरित संक्रमण, तकनीकी व्यवधान (एआई आदि)।

फ्यूचर ऑफ वर्क को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

- पारंपरिक और मैन्युअल रोजगार की जगह उच्च-कौशल, ज्ञान-आधारित और सेवा-आधारित कार्यों की प्रमुखता बढ़ रही है**, एआई द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली नौकरियां, उत्पादकता में वृद्धि , नौकरी में वृद्धि।**
- **कार्यबल एवं कौशल प्रभाव**: **री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग**, कौशल में बदलाव।
- **सामाजिक प्रभाव:** वेतन और अवसर अंतर, **लैंगिक असमानता, जनजातीय विकास.**

'फ्यूचर ऑफ वर्क' के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **कौशल विकास, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग**
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** ।
  - **फ्यूचरस्किल्स प्राइम** नैसकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल कौशल पहल है।
- **नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए**: AI फॉर इंडिया 2030 पहल।
  - **राष्ट्रीय इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स मिशन (NM-ICPS)**
- **स्वास्थ्य और कल्याण के लिए** : राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

3.5. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना {Research Development And Innovation (RDI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये की निधि वाली '**अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI)** योजना को मंज़ूरी दी।

RDI योजना के बारे में

- **नोडल विभाग:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- **योजना का मुख्य उद्देश्य**
  - **निजी क्षेत्र की** आत्मनिर्भरता के लिए **उभरते क्षेत्रों** और अन्य ज़रूरी क्षेत्रकों में अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) को **बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना।**
  - **टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (TRL)** के उच्चतर स्तर पर रूपांतरणकारी परियोजनाओं को वित्त-पोषण प्रदान करना।
  - **प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन** करना
  - **डीप-टेक फंड ऑफ़ फंड्स** की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।
- **वित्तपोषण और वित्तीय सहायता**
  - **कुल बजट** : ₹1 लाख करोड़
  - **वित्तपोषण के तरीके** : कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण, इक्विटी निवेश, विशेष रूप से स्टार्टअप के मामले में, डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स में योगदान।

प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (Technology Readiness Levels - TRL)

- **प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (TRLs) एक 9-बिंदु पैमाना है, जिसे सबसे पहले नासा (NASA) ने विकसित किया था।**
- **इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई तकनीक कितनी परिपक्व (तैयार) है — विचार के चरण (TRL-1) से लेकर बाजार में उपयोग हेतु तैयार (TRL-9) तक।**

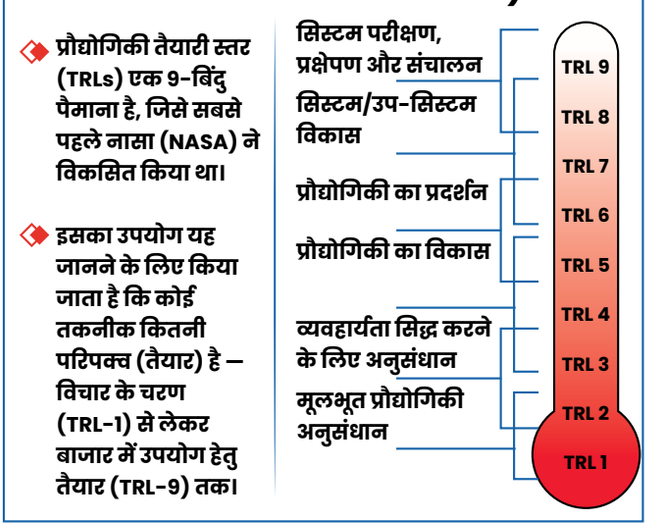

- **क्या शामिल नहीं है**: अनुदान (Grants) और अल्पकालिक ऋण
- **कवरेज**
  - TRLs 4 और उससे ऊपर की रूपांतरणकारी RDI परियोजनाओं के लिए आकलन की गई परियोजना लागत के 50% तक का वित्तपोषण किया जा सकता है।
  - अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह (EGoS) अन्य योजनाओं को मंज़ूरी दे सकता है।

- **कार्यान्वयन संरचना**
  - ANRF का गवर्निंग बोर्ड भी RDI योजना को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  - **दूसरे स्तर के फंड प्रबंधक:** इसमें वैकल्पिक निवेश निधि (AIFs), विकास वित्त संस्थान (DFIs), IIT रिसर्च पार्क्स आदि शामिल हो सकते हैं।

योजना का महत्व

- अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को मान्यता देना
- निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उत्प्रेरक
- व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना
- आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसर सृजित करना और रोजगार सुरक्षित रखना

भारत में अनुसंधान और विकास संबंधी चुनौतियां

- **R&D में कम निवेश और R&D में विविधता का अभाव:** पिछले दो दशकों में भारत का R&D व्यय GDP के केवल 0.6–0.7% के बराबर रहा है।
- **राज्यों में R&D में कम निवेश:** 2020-21 के दौरान, राज्यों ने राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय का केवल 6.7% हिस्सा ही खर्च किया।
- **सीमित सहयोग:** भारत में **"ट्रिपल हेलिक्स" मॉडल** (जो अमेरिका में देखा जाता है) अभी भी अविकसित अवस्था में है।
- निधियों का अपर्याप्त उपयोग, वैज्ञानिक प्रतिभा की अपर्याप्त पहचान

आगे की राह

- **R&D में वित्तपोषण बढ़ाना और उसमें विविधता लाना**: राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लक्ष्यों के अनुरूप 2030 तक सकल R&D व्यय (GERD) को बढ़ाकर GDP के 2% तक करना चाहिए।
- राज्य-विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) ज़रूरतों की पहचान
- CSIR नवाचार हब जैसे अनुसंधान क्लस्टर मॉडल को मजबूत करना।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना: सैटेलाइट बनाने में ISRO-उद्योग साझेदारी जैसे मॉडल को अपनाना चाहिए।
- संसाधन का प्रभावी तरीके से उपयोग: आउटपुट-आधारित वित्तपोषण अपनाएं।
- वैज्ञानिक प्रतिभा को पहचानना और बनाए रखना: प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF) जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए और विश्व भर में भारत की प्रतिभाओं को देश में वापस लाने के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) , राष्ट्रीय एआई मिशन , अटल नवाचार मिशन (AIM), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM)

3.6. भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)** 2025 में बढ़कर **67** हो गया, जो 2021 से अब तक 24.3% की वृद्धि दर्शाता है।।

वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में:

- **FI-Index** देश भर में वित्तीय समावेशन का मापन करता है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सूचकांक में हुई वृद्धि इसके तीनों उप-सूचकांकों-**पहुँच (Access)**, **उपयोग (Usage)** और **गुणवत्ता (Quality)** में हुई प्रगति को दर्शाती है।
- **प्रमुख चालक** :
  - **सरकारी पहल –** PMJDY, NSFI (2019-24), आधार KYC, डिजिटल इंडिया।
  - **प्रौद्योगिकी –** धोखाधड़ी का पता लगाने और ग्राहक सेवा के लिए UPI, JAM ट्रिनिटी, AI/ML उपकरण।
  - **संस्थाएं –** MFIs (विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी), SHGs (13.4 मिलियन+), बैंक सखी, PSLI
- **महत्व** : सतत विकास लक्ष्य, उद्यमशीलता, लचीलापन, डिजिटल नवाचार और ग्रामीण विकास का समर्थन करता है।
- **चुनौतियाँ** : निष्क्रिय बैंक एकाउंट्स, लैंगिक असमानताएं, कमजोर बुनियादी ढांचा, कम डिवाइस पहुंच, वित्तीय निरक्षरता, ऋण संबंधी बाधाएं, डिजिटल विभाजन।
- **आगे की राह** : कम बैंकिंग सेवाओं और बिना बैंकिंग सेवा वाले वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, तकनीक आधारित वित्तीय प्रणाली (RIAs, सीबीडीसी) विकसित करना, ONDC और OCEN को बढ़ावा देना, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, लक्षित पीपीपी-आधारित नीतियों को अपनाना।

3.7. डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत में **डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई। यह मिशन **2015 में शुरू** हुआ था।

डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में

- **नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**)।
- **उद्देश्य:** भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज** और **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था** में बदलना। इसका लक्ष्य तीन क्षेत्रों पर आधारित है—डिजिटल अवसंरचना, मांग आधारित शासन और सेवाएँ —जिसे ब्रॉडबैंड हाईवे, ई-क्रांति, नौकरियों के लिए आईटी और ई-गवर्नेंस सहित नौ स्तंभों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- **उपलब्धियां** : भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है, इंटरनेट का उपयोग 285% बढ़ा है, भारत रीयल-टाइम पेमेंट्स में विश्व में अग्रणी है (2023 में 49% वैश्विक डिजिटल लेनदेन भारत में दर्ज किया गया) और BHASHINI (30+ भाषाएँ) जैसे समावेशी उपायों को लॉन्च किया है।
- **चुनौतियाँ** : कम डिजिटल साक्षरता (38% परिवार), खराब ग्रामीण इंटरनेट और पुराने ब्रॉडबैंड मानदंड, बढ़ते साइबर जोखिम (2025 में ₹220 मिलियन औसत उल्लंघन लागत), और स्वास्थ्य सेवा डिजिटलीकरण में अंतराल।
- **आगे की राह:** भारतनेट को तेजी से आगे बढ़ाना, ब्रॉडबैंड की गुणवत्ता में सुधार करना, ई-सेवाओं का विस्तार करना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को एकीकृत करना।

3.8. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में पिछले पांच वर्षों में बौद्धिक संपदा (**IP**) फाइलिंग में **44%** की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक संकेतकों (GI) में **380%** की बढ़ोतरी है।

- **वैश्विक स्थिति** : भारत ने वित्त वर्ष 24 में 1,03,057 पेटेंट प्रदान किए; ट्रेडमार्क फाइलिंग में 4वें स्थान पर (2023); और वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 9वें (2020) से 6वें (2023) स्थान पर पहुंच गया।
- **तेजी के कारण:** सरलीकृत आईपी कानून, कार्यालयों का आधुनिकीकरण, और लोकार्नो वर्गीकरण को अपनाना, SPRIHA जैसी जागरूकता योजनाएं, शुल्क रियायतें, डिजिटल और ए.आई. पहल।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अवलोकन:** बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं; **IPRM व्यवस्था के तहत 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं:** (i) पेटेंट, (ii) ट्रेडमार्क, (iii) औद्योगिक डिजाइन, (iv) कॉपीराइट, (v) भौगोलिक संकेतक, (vi) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, (vii) व्यापार रहस्य, और (viii) पादप किस्में। डीपीआईआईटी के अंतर्गत सीजीपीडीटीएम द्वारा प्रशासित।
- **महत्व:** एफडीआई, स्टार्टअप, प्रतिस्पर्धात्मकता और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- **चुनौतियाँ:** कम अनुसंधान एवं विकास व्यय, पेटेंट विवाद और एवरग्रीनिंग, अनिवार्य लाइसेंसिंग की चिंताएँ, कमजोर **IP** वित्त-पोषण, "लंबित पेटेंट" पर अस्पष्टता, देरी और खराब प्रवर्तन।
- **आगे की राह:** राष्ट्रीय IPR नीति की समीक्षा, राज्यों की भूमिका को मजबूत करना, IPR न्यायालयों की स्थापना, IP फंड का निर्माण और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund)

RBI ने संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर विनियमित संस्थाओं द्वारा AIF योजना की कुल राशि के 20% तक निवेश करने की सीमा तय कर दी है।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में

- सेबी (2012) द्वारा विनियमित यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है, जो निजी रूप से निवेश जुटाती है। साथ ही, ये अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार, निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित करता है।
- **श्रेणियाँ:**
  - **श्रेणी I:** स्टार्ट-अप, SME, इन्फ्रा, सामाजिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों (जैसे, वीसी, एंजेल फंड) में निवेश करें।
  - **श्रेणी II:** वे अपने दैनिक परिचालन खर्चों को पूरा करने के अलावा किसी अन्य प्रकार के ऋण या ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का उपयोग नहीं करते (जैसे, पीई, ऋण, रियल एस्टेट फंड)।
  - **श्रेणी III:** लीवरेज का उपयोग करें, जिसमें डेरिवेटिव्स (जैसे, हेज फंड, PIPE) शामिल हैं।

3.9.2. डिजिटल भुगतान सूचकांक {Digital Payments Index (DPI)}

पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) के बारे में

- डिजिटल अपनाने में हुई प्रगति को मापने के लिए आरबीआई द्वारा अर्ध-वार्षिक रूप से प्रकाशित। मानदंड: सक्षमकर्ता, बुनियादी ढाँचा (माँग और आपूर्ति), प्रदर्शन, उपभोक्ता-केंद्रितता।

3.9.3. वित्तीय स्थिति सूचकांक (Financial Conditions Index: FCI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन में दैनिक आधार पर बाजार के रुझानों पर नज़र रखने के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) की शुरुआत का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) के बारे में

- यह **2012 के बाद से** ऐतिहासिक औसत के संदर्भ में **अ**पेक्षाकृत कठिन या आसान **वित्तीय बाजार स्थितियों के स्तर** का आकलन करता है। इसमें चुने हुए संकेतक पांच बाजार खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं: **मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार** और इक्विटी बाजार।

3.9.4. ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 (GLOBAL FINDEX 2025)

हाल ही में विश्व बैंक की **'ग्लोबल फाइंडेक्स 2025'** रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत में लगभग **90%** लोग खाताधारक। लगभग 16% निष्क्रिय खाते (अन्य LMI में 4% की तुलना में)। दोनों लिंगों के बीच निष्क्रिय खातों में कमी आई (2021-24)। बाधाएँ: डिवाइस की लागत, खराब नेटवर्क।

3.9.5. स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins)

यू.एस. कांग्रेस ने स्टेबलकॉइन्स को **विनियमित करने** के लिए 'जीनियस एक्ट' पारित किया।

- स्टेबलकॉइन एक प्रकार की **क्रिप्टोकरेंसी** है, जिसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए- **टेथर (USDT),** जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है।

स्टेबलकॉइन का उपयोग क्यों बढ़ा है?

- क्रिप्टो परिसंपत्तियों (मुद्रा/वस्तु) से जुड़ा हुआ है; बिटकॉइन जैसे अस्थिर सिक्कों की तुलना में स्थिर मूल्य।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन

- क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ अनियमित लेकिन कर-योग्य (**वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (**VDA) पर 30%, वित्त अधिनियम 2022)। VDA में क्रिप्टो, NFT शामिल हैं; 2023 में, VDAs को **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** के दायरे में भी ला दिया गया था।

3.9.6. क्रॉपिक (CROPIC)

यह पहल वित्तीय सक्षमता बढ़ाने के लिए कृषि में डिजिटल नवाचारों का हिस्सा है।

- **क्रॉपिक (फसलों के रियल टाइम अवलोकन और फोटो का संग्रह) पहल के बारे में**
- **यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के अंतर्गत **कृषि मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया **एक मोबाइल ऐप** है।
  - **फसल चक्र के दौरान 4-5 बार फसलों की जियो-टैग की** गई तस्वीरें लेना।
- इसमें फोटो का विश्लेषण करने और उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु AI-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा और इसे वेब-आधारित एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकेगा। PMFBY के अंतर्गत नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से किया जाएगा।

3.9.7. OECD-FAO ने 'एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034' जारी किया (Agricultural Outlook 2025-2034 Released BY OECD-FAO)

- **जारीकर्ता: OECD और FAO द्वारा।**
- यह आउटलुक **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि आधारित उत्पादों (मछली सहित) तथा उनके बाजारों के लिए दस साल की संभावनाओं** का व्यापक आकलन प्रदान करता है।
- **इस आउटलुक के अनुसार वैश्विक बाजार रुझानों (2024) पर एक नजर**
  - **जैव ईंधन:** इसकी मांग में **प्रतिवर्ष 0.9% की वृद्धि** होने का अनुमान है, जिसका नेतृत्व **भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया** कर रहे हैं।
  - **कपास:** वैश्विक स्तर पर कपास के उपयोग में वृद्धि हुई है। साथ ही, **भारत चीन को पछाड़कर कपास का शीर्ष उत्पादक बनने की ओर अग्रसर है।**

3.9.8. अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम, 2025 अधिसूचित

ये नियम **अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002** के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

नियमों के बारे में

- नियम अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों (यूरेनियम, थोरियम) के अन्वेषण और खनन को विनियमित करते हैं, और केवल निर्धारित सांद्रता स्तरों से ऊपर ही लागू होते हैं। नियमों के तहत सरकार द्वारा नामित संस्थाओं को ही **अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टे** दिए जा सकते हैं, जबकि विदेशी संस्थाओं को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **यूरेनियम**
  - **प्रमुख रिजर्व: झारखंड**, **आंध्र प्रदेश**, मेघालय, **राजस्थान** आदि।
  - भारत में अधिकांश यूरेनियम भंडार छोटे और निम्न श्रेणी के हैं।
- **थोरियम**
  - भारत के पास यूरेनियम का सीमित भंडार है, लेकिन थोरियम का प्रचुर भंडार है। मोनाज़ाइट में **8-10% थोरियम होता है।**
  - **केरल** और **उड़ीसा** के समुद्रतटीय रेत में मोनाजाइट के प्रचुर भंडार हैं।

3.9.9. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centre: GCC)

वित्त मंत्री ने **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)** की स्थापना को बढ़ावा देने और अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए उद्योग एवं सरकार से मिलकर काम करने का आग्रह किया है।

GCC के बारे में

- ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (GIC) के रूप में भी जाना जाता है, जीसीसी वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र होते हैं जो मूल कंपनी की संरचना के भीतर आईटी, अनुसंधान एवं विकास, और ग्राहक सहायता प्रदान करती हैं।
- **भारत में स्थिति**: भारत में 1,800 से GCCs हैं (वैश्विक हिस्सेदारी का 50%)। इनका GVA में योगदान 68 बिलियन डॉलर है।
- **चुनौतियाँ:** कुशल कार्यबल की कमी (टियर II-III शहर), बुनियादी ढांचे में अंतराल, आदि।

3.9.10. दूरसंचार विभाग (DoT) ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP)-2025 (DoT Releases Draft National Telecom Policy (NTP)-2025}

NTP-2025 का उद्देश्य **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** में हुई प्रगति को आगे बढ़ाना है।

- यह अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों जैसे **5G/6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा उभरती चुनौतियों का समाधान करता है।**

NTP-2025 के बारे में

- **विजन:** भारत को सार्वभौमिक, सुरक्षित और टिकाऊ कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलना।
- **उद्देश्य:**
  - **कनेक्टिविटी:** नेटवर्क का विस्तार करें, गुणवत्ता में सुधार करें, समावेशन सुनिश्चित करें।
  - **नवप्रवर्तन:** अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप और उद्योग-शैक्षिक जगत-सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करना।
  - **घरेलू विनिर्माण:** डिजाइन-आधारित विकास, कौशल और निवेश को बढ़ावा देना।
  - **सुरक्षा** : लचीला, विश्वसनीय दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
  - **जीवन/व्यवसाय में आसानी:** पहुंच को सरल बनाएं और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दें।
  - **स्थिरता:** हरित तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाएं।

3.9.11. एल्युमीनियम और तांबा (Aluminium and Copper)

केंद्र सरकार ने हाल ही में एल्युमीनियम और कॉपर विजन दस्तावेजों का अनावरण किया।

विज़न दस्तावेज़ के बारे में

- एल्युमीनियम एवं कॉपर विजन दस्तावेज बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करते हैं।
- **तांबे का विजन:** 2047 तक देश में तांबे की मांग में **छह गुना वृद्धि** का अनुमान है। साथ ही, 2030 तक **5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता** जोड़ने की योजना है।
- **एल्युमीनियम विजन:** 2047 तक उत्पादन में छह गुना वृद्धि; बॉक्साइट क्षमता को 150 MTPA तक बढ़ाना।
- **उत्पादन क्षेत्र**
  - **एल्युमीनियम/बॉक्साइट:** भारत के भंडार मुख्यतः ओडिशा (41%), छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हैं; ओडिशा उत्पादन में अग्रणी (73%) है। विश्व स्तर पर, चीन (58%) शीर्ष उत्पादक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत का स्थान है।
  - **तांबा:** भारत के भंडार—राजस्थान (52%), मध्य प्रदेश, झारखंड; उत्पादन में मध्य प्रदेश (57%), राजस्थान (43%) सबसे आगे। वैश्विक स्तर पर, चिली (19%) सबसे आगे है, उसके बाद पेरू और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
मासिक
समसामयिकी रिवीजन
कक्षाएं 2026
GS प्रीलिम्स और मेन्स
हिन्दी माध्यम 30 AUG | 2 PM
English Medium 23 AUG | 2 PM
अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

Live/Online Classes are available

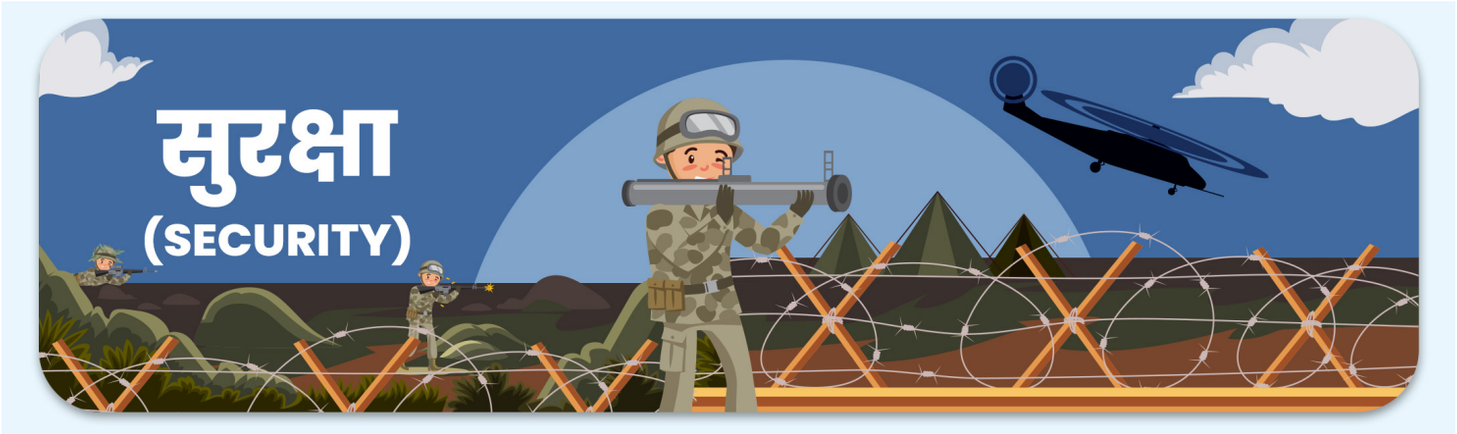

4.1. क्वांटम साइबर रेडीनेस (Quantum Cyber Readiness)

सुर्ख़ियों में क्यों?

MeitY, CERT-In और SISA ने **"ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस"** शीर्षक से एक श्वेत-पत्र जारी किया है।

क्वांटम साइबर खतरे

- **हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लैटर (HNDL) अटैक**: वर्तमान में एन्क्रिप्टेड डेटा इकट्ठा और संग्रहित करते हैं, ताकि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर संचालित होने पर उसे डिक्रिप्ट किया जा सके।
- **सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन**: क्वांटम कंप्यूटिंग, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क संचार को तोड़ सकती है।
- **हस्ताक्षर प्रतिरूपण** : क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से अटैकेर्स नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिससे वे **मैलवेयर** फैला सकते हैं और **लक्षित फिशिंग अटैक** कर सकते हैं।
- **नए "ज़ीरो-डे" का खतरा**: अज्ञात एल्गोरिदम वर्तमान क्रिप्टोग्राफी को तोड़ रहे हैं और क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी को अपनाने के समक्ष भी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

भारत की क्वांटम साइबर सुरक्षा पहल

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023): 2000 किलोमीटर तक क्वांटम-सुरक्षित संचार प्रणाली स्थापित करना है।
- **DRDO की परियोजनाएँ**:: QTRC की स्थापना की गई; 1 किलोमीटर फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक पर क्वांटम एंटेंगलमेंट-आधारित सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया।
- **सी-डॉट:** क्वांटम-की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD), पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) का विकास।
- **इसरो:** 300 मीटर से अधिक फ्री-स्पेस क्वांटम-की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।

आगे की राह

श्वेत-पत्र द्वारा अनुशंसित क्वांटम साइबर रेडीनेस का रोडमैप

क्षेत्र	सिफारिशें
मूल्यांकन और रणनीतिक योजना	**क्वांटम बिल ऑफ मैटेरियल्स (QBOM):** जोखिम प्राथमिकता, खरीद, उन्नयन और क्वांटम तत्परता के लिए अनुपालन का समर्थन करता है। **AI-समर्थित जोखिम मूल्यांकन:**: क्रिप्टोग्राफिक पैटर्न का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है।
प्रौद्योगिकी तत्परता	**PQC परीक्षण:** उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल करने से पहले कार्यान्वयन को मान्य करें। **हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी** : क्लासिकल और क्वांटम-प्रतिरोधी, दोनों प्रकार के एल्गोरिद्म को उपयोग में लाया जा सकता है।
संगठनों में चरणबद्ध रूप से लागू करना	सुरक्षित विकास, कुंजी प्रबंधन और साइनिंग प्रक्रियाओं के लिए वर्कफ़्लो में PQC को एम्बेड करें। अनुमोदित एल्गोरिदम, टूलसेट को अनिवार्य बनाने और मानकों को लागू करने के लिए ICT नीतियों को अपडेट करना
लचीलापन, निगरानी और भविष्य की सुरक्षा	QKD: क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित एक अतिरिक्त सुरक्षा मॉडल प्रदान करता है। **ML-DSA** और **SLH-DSA**: उच्च कम्प्यूटेशनल मांगों के बावजूद सरकारी, वित्त, कानूनी दस्तावेजों के लिए मजबूत सिग्नेचर।

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. ऑपरेशन महादेव (Operation Mahadev)

ऑपरेशन महादेव के बारे में

- यह भारतीय सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक **संयुक्त आतंकवाद विरोधी मिशन** है।

4.2.2. ऑपरेशन- मेड मैक्स (Operation- MED MAX)

ऑपरेशन-मेड मैक्स के बारे में

- यह ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा **दवाओं के अवैध व्यापार पर रोक** लगाने के लिए शुरू किया गया था।।
- चार महाद्वीपों में फैले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़, जो एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करता था। यह तकनीक और अवैध व्यापार के गठजोड़ को उजागर करता है।

4.2.3. प्रोजेक्ट 17A (Project 17A)

INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 17A के स्टील्थ फ्रिगेट्स में दूसरा युद्धपोत है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

प्रोजेक्ट 17A

- यह परियोजना शिवालिक क्लास (प्रोजेक्ट 17) फ्रिगेट्स का अगला चरण है, जो पहले से सेवा में सक्रिय हैं।
  - **फ्रिगेट** एक **बहु-भूमिका वाला युद्धपोत** होता है। इसका उपयोग समुद्र में अन्य युद्धपोतों या हवाई खतरों से बेड़े (जैसे विमान वाहक, विध्वंसक आदि) की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
- **प्रोजेक्ट 17A के जहाजों** की विशेषताएं- **बेहतर स्टील्थ** और **अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस**, जो प्रोजेक्ट 17 क्लास की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नति है।

4.2.4. एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (Extended Range Anti-Submarine Rocket)

भारत ने **स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट प्रणाली का परीक्षण** किया है।

ERASR के बारे में

- ERASR एक पूर्णतया **स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है** जिसका उपयोग **पनडुब्बियों से लड़ने के लिए किया जाता है तथा इसे** भारतीय नौसेना के जहाजों से दागा जाता है।
- इसमें **ट्विन-रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन** होता है **और** इसमें स्वदेशी रूप से विकसित **इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग किया गया है।**

4.2.5. अस्त्र मिसाइल (Astra Missile)

लड़ाकू विमान से **'अस्त्र'** मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

अस्त्र मिसाइल के बारे में

- यह **स्वदेशी "बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल" (BVRAAM)** है **जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है।**
- इस मिसाइल को **अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक विमानों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।**
- यह मिसाइल **सभी मौसम में दिन और रात में काम करने में सक्षम है।**

4.2.6. प्रलय मिसाइल (Pralay missile)

DRDO ने ओडिशा तट पर **प्रलय मिसाइल** के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए।

प्रलय मिसाइल के बारे में

- **प्रलय** एक **सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल** है, जो **हाइपरसोनिक गति (मैक 5 से ऊपर)** से उड़ान भर सकती है।
- **क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल्स** ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कम ऊंचाई पर बैलिस्टिक मार्ग अपनाती हैं। ये उड़ान के दौरान जरूरत पड़ने पर दिशा और मार्ग बदल सकती हैं।

4.2.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र	**भारत और सिंगापुर** के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, **'अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025'** का **14वां संस्करण।**
भारत NCX (Bharat NCX)	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास। **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS)** द्वारा **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) गांधीनगर, गुजरात** के सहयोग से आयोजित किया गया।
सिंबेक्स अभ्यास	**शुरुआत:** यह **'लायन किंग अभ्यास'** के नाम से 1994 में शुरू हुआ था। यह **भारतीय नौसेना** और **सिंगापुर नौसेना** के बीच **हर साल** आयोजित होने वाला अभ्यास है।
टैलिसमैन सेबर अभ्यास	2025 का अभ्यास सिडनी में शुरू होगा जिसमें भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस के **19 देश भाग लेंगे।** **प्रमुख प्रतिभागी:** फ्रांस, जर्मनी, **भारत,** आदि।
जा-माता/जा माटा (Jaa Mata)	यह **जापान** और **भारत तटरक्षक बल** के बीच एक **संयुक्त समुद्री अभ्यास है।**

5.1. अर्बन रेसिलिएंस (Urban Resilience)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक की रिपोर्ट **"टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉपरस सिटीज़ इन इंडिया" में तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों** पर प्रकाश डाला गया है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- भारत की शहरी आबादी 480 मिलियन (2020) से बढ़कर **1.1 बिलियन (2070) हो जाने का अनुमान है, तथा 2030 तक शहरों में 70% से अधिक नई नौकरियां** पैदा होने की उम्मीद है।

अर्बन रेसिलिएंस क्या है?

- इसका तात्पर्य आपदाओं का सामना करने, परिवर्तन के प्रति अनुकूल तथा भविष्य की संधारणीयता के लिए रूपांतरण करने की क्षमता से है।

संवेदनशील भारतीय शहरों के संबंध में रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य बिंदु:

- **शहरी बाढ़:** प्लुवियल (वर्षा जनित बाढ़) का जोखिम 2070 तक 3.6 से 7 गुना बढ़ सकता है, तथा **2030 तक नुकसान 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।**
- **तटीय बाढ़:** 40% जनसंख्या तटों के निकट रहती है; क्षति **2.4 अरब डॉलर (2010) से बढ़कर 75 अरब डॉलर (2050) हो जाने का अनुमान है।**
- **शहरी ऊष्मा द्वीप:** तापमान जनित समस्याओं में वृद्धि, शहरों में 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रहना; चेन्नई को 2050 तक GDP के 3.2% की हानि हो सकती है।
- **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव:** शहरों की ऊष्मा (गर्मी) और वायु प्रवाह संबंधी परिवर्तित विशेषताएं ज्यादा गर्मी को रोककर रखती हैं। इस कारण शहर, गाँवों और कस्बों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं।
- **अवसंरचना संबंधी क्रमिक विफलता:** बाढ़ के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, आर्थिक नुकसान होता है, तथा शहर ठप हो जाते हैं।

शहरों की आपदा-रोधी क्षमता सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियाँ:

- **गवर्नेंस में समन्वय का अभाव:** कई एजेंसियों के मध्य दायित्व के बंटवारे से समन्वय के साथ कार्रवाई करना कठिन हो जाता है।
- **मास्टर प्लान का अभाव:** 52% शहरों में मास्टर प्लान का अभाव; शहरी स्थानीय निकायों में शहरी योजनाकारों की कमी।
- **सीमित वित्त:** शहरों का स्वयं का राजस्व सृजन बहुत कम (GDP का लगभग 1%)।
- **जर्जर अवसंरचना:** जल निकासी, सीवरेज प्रणालियां अपर्याप्त हैं।
- **निजी क्षेत्रक की भूमिका:** शहरी अवसंरचना के वित्त-पोषण में केवल 5% का योगदान देता है।

अर्बन रेसिलिएंस से संबंधित सरकारी पहल

- **सरकारी योजनाएं:** स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी आदि।
- **जलवायु स्मार्ट शहर आकलन फ्रेमवर्क:** शहरी नियोजन, हरित आवरण आदि जैसे संकेतक।
- **सी-फ्लड:** 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- **शहरी मोबिलिटी:** RRTS, शहरों में चलने योग्य सड़कों को बढ़ावा देना आदि।
- **आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI):** इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस को बढ़ावा देना।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **बाढ़ और अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु प्रोग्राम:** सतत विकास के लिए **शहर-स्तरीय जलवायु-कार्य योजना।**

- **74वां संशोधन**: शहरी नियोजन संबंधी कार्य को वित्त पोषण संबंधी रणनीतियों के साथ निर्वाचित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना।
- **नगर निगम वित्त:** जलवायु परिवर्तन रोधी अवसंरचना के निर्माण के लिए 2050 तक **2.4 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।**
- **शासन में सुधार:** प्राधिकरण की भूमिकाएं स्पष्ट करें; कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी अपनाएं।
- **वैश्विक प्रतिबद्धताएं**: रेजिलिएंट, समावेशी शहरों पर **SDG-11**, **हैबिटेट III एजेंडा के अनुरूप।**
- **समावेशी विकास: टियर 2/3 शहरों**, उपग्रहीय नगरों, **सर्कुलर इकोनॉमी**, मिश्रित तथा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) आदि को मजबूत करना।

निष्कर्ष

आइए शहरीकरण को अवसर के रूप में देखें। अब वह समय नहीं रहा जब इसे चुनौती या बाधा माना जाता था। शहर केवल के विकास केंद्र नहीं हैं, बल्कि हमारे शहर गरीबी कम करने की क्षमता और ताकत रखते हैं। – प्रधान मंत्री मोदी

5.2 इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने पेट्रोल में **20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम** के तहत निर्धारित।
- यह **1.5% (2014) से बढ़कर 20% (2025) हो गया**।

इथेनॉल के बारे में

- **इथेनॉल (C_2H_5OH) एक नवीकरणीय ईंधन है**, जिसे फसलों से **किण्वन** या **पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।**
- **प्रकार:**
  - **प्रथम पीढ़ी:** खाद्य फसलों (अनाज, गन्ना, चुकंदर आदि) से।
  - **दूसरी पीढ़ी**: अवशेष/वुडी बायोमास से।
  - **तीसरी पीढ़ी**: शैवाल से।
  - **चौथी पीढ़ी**: इंजीनियर्ड पादपों और सूक्ष्म जीवों से।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में

- **शुरुआत:** पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए 2003 में शुरू किया गया।
- **इथेनॉल मिश्रण के बारे में**
  - इथेनॉल मिश्रण के तहत स्वच्छ ईंधन के लिए **पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है।**
  - **प्रकार**: E10 (10% इथेनॉल), E20, E85 ईंधन।
    - E20 ईंधन, E10 की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर राइडर अनुभव और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% की कटौती प्रदान करता है।
- **लक्ष्य: जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति** (2018, संशोधित 2022) के तहत 20% मिश्रण लक्ष्य को पहले ही 2025-26 तक हासिल करना तय किया गया।
  - **स्रोत: गन्ने का रस, चुकंदर, कसावा**, खराब/सड़े हुए अनाज, **अधिशेष खाद्यान्न**।
    - **उपलब्धि:** इथेनॉल उत्पादन 38 करोड़ लीटर (2014) से बढ़कर 660 करोड़ लीटर (2025)

इथेनॉल मिश्रण का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा –** सुरक्षित ऊर्जा और विकास
- **पर्यावरणीय संधारणीयता –** 698 लाख टन CO_2 में कमी
- **आर्थिक विकास –** जैव ईंधन उद्योग को बढ़ावा
- **फसल विविधीकरण –** मक्का और वैकल्पिक फसलों की खेती
- **आयात संबंधी बचत –** ₹21.36 लाख करोड़ की बचत
- **ग्रामीण विकास –** किसानों को ₹1.18 लाख करोड़

भारत में इथेनॉल मिश्रण की चुनौतियाँ

- **खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति**: **FAO (2023)** ने चेतावनी दी है कि जैव ईंधन के अधिक उत्पादन से खाद्य असुरक्षा और बिगड़ सकती है; इथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का अत्यधिक उपयोग करना जोखिम बढ़ाता है।
- **पर्यावरण:** अधिक पानी की खपत वाले गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जलभृतों पर दबाव पड़ता है।

- **प्रौद्योगिकी एवं लागत:** E20 के अनुकूल बनाने हेतु इंजन/ईंधन प्रणाली संबंधी महंगे परिवर्तन की आवश्यकता होती है; **पुराने वाहनों में इथेनॉल-संगत भागों का अभाव होता है**।
- **ईंधन दक्षता: इथेनॉल का कम ऊर्जा घनत्व माइलेज को कम करता है**; पुराने इंजनों के चलने में एवं उत्सर्जन संबंधी समस्याएं होती हैं; जल अवशोषण के कारण इंजन बंद होने का खतरा रहता है।
- **आपूर्ति:** चुनौतियों में **पूर्वोत्तर राज्यों में खराब उपलब्धता**, अंतर-राज्यीय प्रतिबंध, उच्च लॉजिस्टिक लागत/उत्सर्जन और अपर्याप्त भंडारण अवसंरचना शामिल हैं।

इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने वाली पहलें

- **पीएम जीवन**: 2G इथेनॉल परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **EISS:** समर्पित इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देता है।
- **GST में कटौती:** EBP के लिए इथेनॉल पर 5%, कच्चे तेल पर 18%।
- इथेनॉल के सुचारू परिवहन के लिए **उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन।**

निष्कर्ष

भारत का इथेनॉल मिश्रण ऊर्जा सुरक्षा, संधारणीयता और विकास सुनिश्चित करता है; अब ज़रूरत है कि बायोडीजल का चरणबद्ध रूप से विस्तार किया जाए ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान हो सके।

5.3. वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना {CSS-Integrated Development of Wildlife Habitats Scheme (CSS IDWH)}

सुर्खियों में क्यों?

घड़ियाल और स्लोथ भालू को CSS-IDWH के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की गई।

CSS-IDWH योजना के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालित करना
- **वित्तीय सहायता:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, जो
  - संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करते हैं
  - संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव का संरक्षण करते हैं
  - क्रिटिकली एनडेंजर्ड प्रजातियों (22) जैसे हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा नदी डॉल्फिन आदि और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए **पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करते हैं।**

घड़ियाल

- **पर्यावास:** गहरी, तेज बहाव वाली नदियाँ पसंद करते हैं।
- **प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्र: नेपाल** (राप्ती-नारायणी) और **भारत** (गिरवा, सोन, रामगंगा , गंडक , चंबल, महानदी)।
- **विशेषताएं:** मछली पकड़ने वाले दांत, लम्बी थूथन, नर के थूथन के सिरे पर घड़ा जैसे संरचना, नर और मादा घड़ियाल की शारीरिक बनावट में स्पष्ट अंतर वाला एकमात्र मगरमच्छ।
- **खतरे**: पर्यावास का क्षरण और मछली पकड़ने के जाल में फंसना और डूबना।
- **स्थिति**
  - **IUCN रेड लिस्ट: क्रिटिकली एनडेंजर्ड**
  - **CITES: परिशिष्ट I.**
  - **WPA, 1972:** अनुसूची I.
- **संरक्षण प्रयास**: प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल (1975), घड़ियाल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण और प्रबंधन योजना।

घड़ियाल

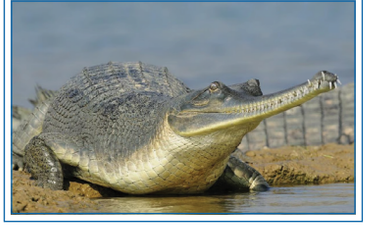

स्लॉथ बेयर

- **पर्यावास:** वन एवं घास के मैदान।
- **प्राकृतिक पर्यावास वाले क्षेत्र: भारत, नेपाल और श्रीलंका** .
- **विशेषताएं:** लंबे पंजे, शरीर काले फर से ढका होता है, लंबी थूथन, दीमक खाने वाला, रात्रिचर और आक्रामक **।**
- **खतरे**: **पर्यावास को नुकसान**
- **स्थिति**
  - **IUCN**: वल्नरेबल
  - **CITES**: परिशिष्ट I.
  - **WPA, 1972** : अनुसूची I.
- **संरक्षण प्रयास: दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य** (कर्नाटक)।

स्लॉथ बेयर

5.4. वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

CITES के 50 वर्ष पूरे हुए।

CITES के बारे में

- **उत्पत्ति: 1963 में IUCN बैठक में** संकल्पित; **1975 से लागू**
- **उद्देश्य:** स्वैच्छिक समझौता जिससे यह सुनिश्चित हो कि वन्य प्रजातियों के व्यापार से अस्तित्व को खतरा न हो; लाइसेंसिंग के माध्यम से व्यापार को विनियमित किया जाए।
- **सचिवालय: जिनेवा** स्थित **UNEP** द्वारा प्रशासित; IUCN तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **पक्षकार:** 185 देश, भारत ने 1976 में अनुसमर्थन किया, राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से लागू किया
- **CoP:** निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय; CoP3 नई दिल्ली में आयोजित (1981)।
- **CITES ट्रेड डाटाबेस:** CITES सचिवालय की ओर से व्यापार संबंधी निगरानी के लिए **UNEP-WCMC** द्वारा प्रबंधित।

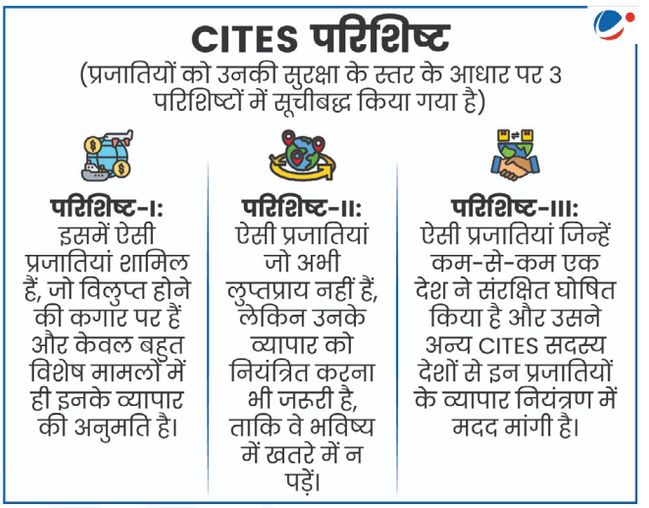

सीआईटीईएस की प्रमुख पहल

- **परिशिष्टों के माध्यम से 40,000 से अधिक प्रजातियों की रक्षा करता है।**
- **माइक (MIKE) कार्यक्रम** हाथियों के अवैध शिकार पर नज़र रखता है।
  - MIKE साइट्स के उदाहरण- चिरांग-रिपू हाथी रिजर्व और दिहिंग-पटकाई हाथी रिजर्व
- **रणनीतिक विजन 2021-2030:** जैव विविधता, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप।
- **CITES ट्री स्पीशीज प्रोग्राम (CTSP):** वृक्ष प्रजातियों के संधारणीय और वैधानिक व्यापार का समर्थन करना।
- **वन्यजीव अपराध से निपटने पर अंतर्राष्ट्रीय संघ (ICCWC), 2010**: वैश्विक स्तर पर वन्यजीव अपराध से मुकाबला करता है।

निष्कर्ष

CITES विकासशील रणनीतियों, MIKE प्रोग्राम और ICCWC और सदस्य-संचालित कानूनी फ्रेमवर्क के माध्यम से जैव विविधता की सुरक्षा करता है।

5.5. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific Ring of Fire)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के निकट 8.8 तीव्रता के भूकंप के चलते भूकंपीय रूप से सक्रिय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से सुनामी लहरें उत्पन्न हुईं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पृथ्वी के धरातल से कम गहराई में (उथला) घटित व्युत्क्रम भ्रंश** के कारण भूकंप पृथ्वी की सतह के पास तब आता है जब **संपीड़न बलों के कारण पृथ्वी की भू-पर्पटी का एक खंड दूसरे खंड के ऊपर आ जाता है।**

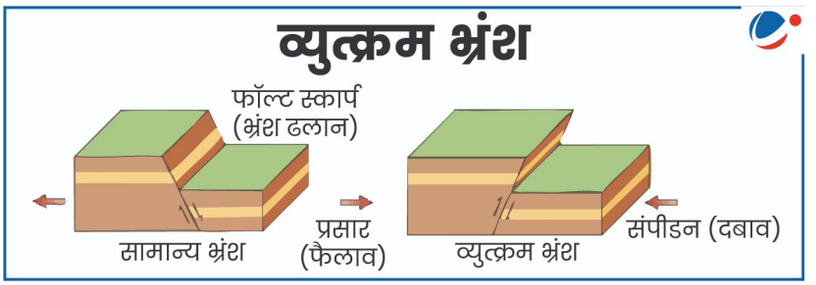

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में

- यह प्रशांत महासागर बेसिन की परिधि में घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ घटित होती हैं।
- **खाते:** सक्रिय ज्वालामुखियों का लगभग 75% , भूकंपों का लगभग 90%।
- **अवस्थिति और विस्तार: जहाँ** प्रशांत महासागर प्लेट, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, आदि की सीमाएं मिलती है।

परि-प्रशांत मेखला की विशेषताएँ:

- **भूगोल:** पर्वतों, द्वीप समूहों, महासागरीय गर्त (मारियाना ट्रेंच) के निर्माण।
- **भू-तापीय ऊर्जा का स्रोत:** दुनिया के 40% से अधिक।
- **खनिजों से समृद्ध**

- **कृषि संबंधी महत्व:** ज्वालामुखीय मिट्टी उपजाऊ होती है (चावल, कॉफी जैसी फसलों के लिए अच्छी)।

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार-बार भूकंप आने और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण

- **क्षेपण मंडल या सबडक्शन ज़ोन:** अभिसारी सीमाओं पर प्लेटें एक-दूसरे पर ओवरलैप हो जाती हैं; क्षेपण मंडल में जाने वाली प्लेट की चट्टानें मैग्मा बन जाती हैं, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि प्रेरित होती हैं। उदाहरण: ताउपो आर्क, न्यूजीलैंड।
- **रूपांतरित सीमाएं:** प्लेटें पार्श्विक रूप से गति करती हैं (सैन एंड्रियास), जिससे कम ज्वालामुखीय गतिविधि के साथ भूकंप आते हैं।
- **अपसारी सीमाएँ:**विवर्तनिक प्लेटें एक-दूसरे से दूर (अपसारी गति) जाती हैं, तो समुद्र नितल का विस्तार और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ, पूर्वी प्रशांत कटक।
- **हॉट स्पॉट:** मेंटल का दबाव चट्टानों को पिघला देती है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधियां प्रेरित होती हैं।

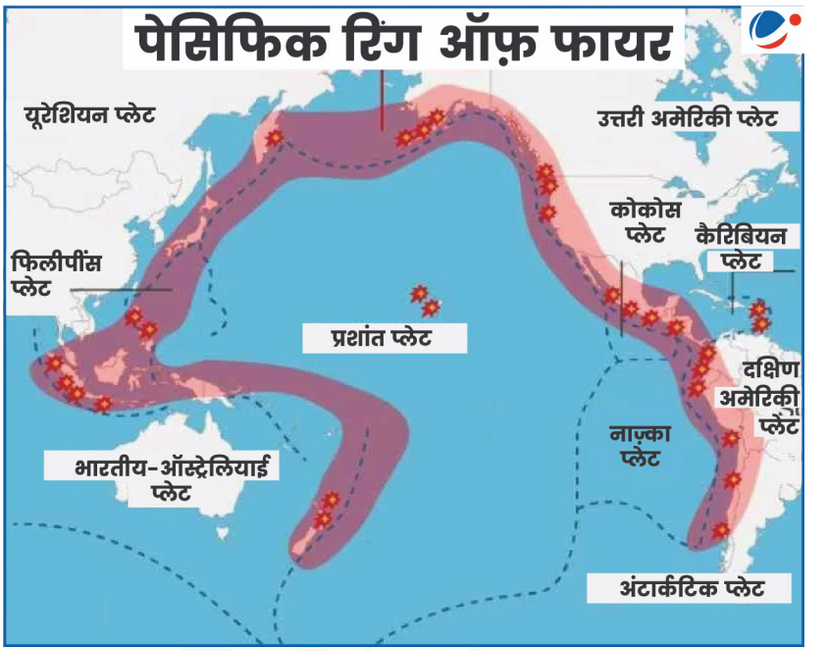

निष्कर्ष

रिंग ऑफ फायर बड़े भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म देता है, तथा प्रशांत महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है।

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 (Sustainable Development Goals Report 2025)

SDGR **वस्तुतः 2030 के सतत विकास एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करता है।**

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

लक्ष्य 1	8.9% लोग चरम गरीबी में रह रहे हैं।
लक्ष्य 2	11 में से 1 व्यक्ति को भुखमरी का सामना करना पड़ा था।
लक्ष्य 4	110 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं, 272 मिलियन अभी भी स्कूल से बाहर हैं।
लक्ष्य 5	प्रबंधन में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई से भी कम है।
लक्ष्य 8	बेरोजगारी 5.0% और 58% कामगार अनौपचारिक क्षेत्रक में
लक्ष्य 10	57% कार्यशील आयु के लोग कार्यरत थे।
लक्ष्य 11	3 बिलियन आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 1.12 बिलियन लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं।
लक्ष्य 13	2024 सबसे गर्म वर्ष रहा ।
लक्ष्य 16	50,000 संघर्ष जनित मृत्यु, 123.2 मिलियन विस्थापित।

5.6.2. नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025 {National Indicator Framework (NIF) Progress Report 2025}

राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा NIF**।

रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख प्रगति

SDG-2	**कृषि आय में** वृद्धि हुई।
SDG-6	**ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल की पहुंच** बढ़ी।
SDG-7	**नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में** वृद्धि हुई, क्षमता 64.04 से बढ़कर **156.31** वाट प्रति व्यक्ति हो गई।
SDG-8	**सामाजिक सुरक्षा कवरेज** 22% बढ़कर **64.3% हो गया।**
SDG-9	सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन में 36% की कमी आई।
SDG 10	घरेलू खर्च का **गिनी गुणांक कम हो गया।**
SDG-12	**संसाधित अपशिष्ट का प्रतिशत** 17.97% से बढ़कर 80.7% हो गया।
SDG-15	**वन आवरण** 21.34% (2015) से बढ़कर 21.76% (2023) हो गया।

5.6.3. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए मसौदा नियम जारी (Draft Rules For Carbon Credit Trading Scheme Issued)

परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025** का मसौदा जारी किया।

मसौदा नियमों के बारे में

- **GHG उत्सर्जन तीव्रता (GEI) को** प्रति इकाई के संबंध में प्रति टन उत्सर्जित CO2 के बराबर परिभाषित करता है और 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।

BEE उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करेगा

- **क्षेत्रक:** एल्यूमीनियम , लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोरसायन और वस्त्र।
- इसका अनुपालन न करने पर **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है।**

CCTS के बारे में

- कार्बन मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देता है।
- ECA 2022 **सरकार को योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।**
- **तंत्र:** अनुपालन (कम उत्सर्जन करने पर कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट) और स्वैच्छिक ऑफसेट परियोजनाएं ।
- **प्रशासक:** BEE
- **कार्बन ट्रेडिंग का विनियामक:** CERC
- **महत्व: भारतीय कार्बन बाजार का** समर्थन करता है; यह **UNFCCC सी और पेरिस समझौते** के अनुरूप है।

विश्व बैंक की **"स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025" रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु वित्त एवं कार्बन मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क** को आकार देने में **भारत की बढ़ती भूमिका** को सराहा गया है।

5.6.4. दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए (New Rules For Contaminated Site Management Notified)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025** अधिसूचित किए हैं।

नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य**: यह सुनिश्चित करना कि जिम्मेदार पक्ष मिट्टी, पानी, स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषित स्थलों सफाई करें।
- **कवरेज नहीं किए गए प्रदूषक:** 189 खतरनाक पदार्थ; रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्री तेल रिसाव, ठोस अपशिष्ट।
- **प्रतिक्रिया का स्तर** कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार भिन्न होता है।
- **प्रबंधन:** स्थानीय निकाय संदिग्ध स्थलों की रिपोर्ट देते हैं; SPCB मूल्यांकन करती हैं, प्रदूषकों की पहचान करती हैं, तथा सफाई योजनाओं को मंजूरी देती हैं; यदि भूमि बेची जाती है तो नए मालिक जिम्मेदार होते हैं।
- **वित्त-पोषण:** केंद्र/राज्य सरकारें प्रारंभिक लागत वहन करती हैं; प्रदूषणकर्ता 3 महीने के भीतर प्रतिपूर्ति करता है।
- अनुपालन न करने पर **दंड ; स्वैच्छिक सुधार की अनुमति, पुराने दूषित स्थलों के लिए कानूनी शून्यता को भरना।**

5.6.5. ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 जारी (Global Wetland Outlook 2025 Released)

रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा जारी।

मुख्य अंश

- **कवरेज:** अंतर्देशीय, तटीय, समुद्री आर्द्रभूमि 1,800 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है; 1970 से 22% की हानि हुई है।
- LICs/ LMICs, विशेष रूप से अफ्रीका, में **सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।**
- **रामसर लक्ष्य कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क** के अनुरूप हैं।
- **खतरे:** शहरीकरण, औद्योगिक और अवसंरचना का विकास।
- **सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज:** एशिया की **रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव ने** 140 से अधिक आर्द्रभूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति प्रदान की है; **सेशेल्स ने** पहला **ब्लू बॉण्ड जारी किया।**
- **आगे की राह:** राष्ट्रीय योजना, प्राकृतिक पूंजी लेखांकन, तथा ग्रीन बॉण्ड, ब्लू बॉण्ड जैसे अभिनव वित्तीय समाधानों में आर्द्रभूमि को एकीकृत करना।

5.6.6. उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल जिले की 'पर्यटक वहन क्षमता' का आकलन किया जाएगा (Uttarakhand To Assess 'Tourist Carrying Capacity' In Nainital District)

सर्वेक्षण में नैनीताल के पहाड़ी शहरों को **अनियंत्रित पर्यटन, वाहनों के आवागमन और जनसंख्या दबाव से** बचाने के लिए **दीर्घकालिक रणनीति बनाने की मांग की गई है।**

- **NGT (सितंबर 2024) ने** नैनीताल को **वहन क्षमता और पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर** वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है।
- **वहन क्षमता: जैविक** (वनस्पति, हाइड्रोलॉजी) और **अजैविक** (भू-भाग, जलवायु) कारकों पर निर्भर **एक क्षेत्र द्वारा एक निश्चित जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा** करने की क्षमता।
- **मूल्यांकन दृष्टिकोण: ग्रहीय सीमा एप्रोच** (पर्यावरणीय संकट) और **बायोकैपेसिटी ओवरशूट एप्रोच** (अर्थ ओवरशूट दिवस)।
- **महत्व: आर्थिक विकास को पारिस्थितिक सीमाओं के साथ संतुलित** करके सतत विकास का मार्गदर्शन करता है ।

प्रोएक्टिव विनियमन और सावधानी पूर्वक तैयार योजना संधारणीय पर्यटन को सक्षम बनाती है, अपरिवर्तनीय क्षति को रोकती है, तथा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए शासन मॉडल प्रदान करती है।

वहन क्षमता के आकलन हेतु एहतियाती सिद्धांत

- अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करना
- विकासात्मक गतिविधियों के समर्थकों पर बर्डन ऑफ प्रूफ
- संभावित रूप से हानिकारक कार्यों के विकल्प तलाशना
- निर्णय लेने में आमजन या हितधारकों की भागीदारी को बढ़ाना

5.6.7. ICJ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया (ICJ Delivers Decision On Tackling Climate Change)

यह प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र वानुअतु के नेतृत्व में और 130 से अधिक देशों द्वारा समर्थित, सुभेद्य लघु द्वीपीय देशों (SIDs) की रक्षा के लिए **जलवायु कार्रवाई के प्रति वैश्विक जिम्मेदारियों** से संबंधित मामला है ।

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा** (2023) ने **देशों के पर्यावरणीय दायित्वों** और **कानूनी परिणामों पर ICJ से सलाह मांगी है।**

मुख्य अंश

- **स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण एक मानवाधिकार है**
- **उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं**
- **गैर-अनुपालन के परिणाम: कानूनी जिम्मेदारी वहन करनी पड़ सकती है** और पुनरावृत्ति न होने की **गारंटी देने की आवश्यकता हो सकती है ।**

कुछ देश अनिवार्य उत्सर्जन कटौती का विरोध करते हैं, लेकिन ICJ की राय जलवायु जवाबदेही के लिए कानूनी दबाव को बढ़ाती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

पीस पैलेस (हेग, नीदरलैंड)

उत्पत्ति: इसकी स्थापना **1945 में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक निकाय** के रूप में की गई थी।

मुख्य कार्य:
देशों के बीच **विवादों का निपटारा** करना;
अन्य अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा इसे भेजे गए कानूनी प्रश्नों पर **सलाहकारी राय प्रदान** करना आदि।

सीमाएं: केवल तभी मामलों की सुनवाई कर सकता है, जब **देशों द्वारा अनुरोध** किया गया हो।

संरचना:
इसमें **संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल** के लिए कुल **15 न्यायाधीश** चुने जाते हैं।
न्यायाधीश **स्वतंत्र रूप** से कार्य करते हैं, न कि अपने देश के प्रतिनिधियों के रूप में।

प्रासंगिकता: **"विश्व न्यायालय"** के रूप में लोकप्रिय, **ICJ 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय** है।

5.6.8. ADEETIE योजना शुरू की गई (ADEETIE Scheme Launched)

ADEETIE के बारे में

- **पात्रता:उद्यम ID वाले MSMEs** ≥10% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी।
- **कार्यान्वयन:** BEE
- **योजना अवधि:** 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-28)।
- **लक्षित क्षेत्रक: 14 ऊर्जा-गहन** क्षेत्रक।
- **लागू करने की प्रक्रिया:** चरणबद्ध कार्यान्वयन।
- **घटक:** ब्याज अनुदान (3-5%), तकनीकी सहायता, एनर्जी ऑडिट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय प्रोत्साहन।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बारे में

कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001

उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था की **ऊर्जा तीव्रता को कम** करना।

BEE द्वारा MSMEs में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- BEE-SME कार्यक्रम: इसका उद्देश्य MSMEs में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है।
- MSMEs की ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- MSMEs में ऊर्जा दक्षता पर सरलीकृत डिजिटल व्यावहारिक जानकारी (सिद्धी/SIDHIEE) पोर्टल।

5.6.9. बाढ़ की बदलती प्रकृति (Changing Nature of Floods)

IIT दिल्ली और रुड़की के अध्ययन से 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों पर **नदी बाढ़ पैटर्न में बदलाव (1970-2010) का पता चलता है।**

अध्ययन की मुख्य बातें

- **बाढ़ की तीव्रता में गिरावट: 74% स्टेशनों पर** बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई; यह **पश्चिमी/मध्य गंगा** (17%/दशक), **नर्मदा**, **मराठवाड़ा में उल्लेखनीय है**।
- **मानसून-पूर्व बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि: मालाबार तट**
- **बाढ़ आने के समय में बदलाव: ऊपरी गंगा (देर से), मध्य भारत (पहले), दक्षिणी भारत (बाद में)।**

5.6.10. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी-फ्लड (C-FLOOD) नामक 'एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली' का उद्घाटन किया (C-Flood, A Unified Inundation Forecasting System Inaugurated)

सी-फ्लड: आपदा प्रबंधन के लिए **गांव स्तर** तक **2-दिवसीय बाढ़ पूर्वानुमान और जलप्लावन मानचित्र** प्रदान करने वाला **एकीकृत वेब-आधारित मंच।**

- **कवर:** 40 मिलियन हेक्टेयर (12%) बाढ़-प्रवण क्षेत्र; **वर्तमान में महानदी, गोदावरी, तापी बेसिन।**
- **उपयोग:** 2-डी हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग; NDEM पोर्टल के साथ एकीकृत।
- **विकासकर्ता:** सी-डैक, CWC, CWC, DoWR, NRSC ।
- **कार्यान्वयन: NSM (2015)** के तहत, भारत को सुपरकंप्यूटिंग क्षमताओं में सशक्त बनाने के उद्देश्य से, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा।**
- सभी भारतीय नदी घाटियों को योजनाबद्ध रूप से कवर करना; जल स्तर के पूर्वानुमान के साथ तैयारी में सहायता और प्राधिकारियों के लिए निर्णय-समर्थन।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन प्रतिक्रिया पोर्टल (NDEM) से जोड़ा जाएगा।**

5.6.11. रिक्लेम फ्रेमवर्क (Reclaim Framework)

रिक्लेम फ्रेमवर्क (इन्फोग्राफिक्स देखें): खदान बंद होने और पुनः उपयोग के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता के लिए **कोयला मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया।

- **विकासकर्ता:** कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस संस्थान।
- **फोकस:** भूदृश्यों और आजीविका पर प्रभाव को कम करना, लैंगिक समावेशिता सुनिश्चित करना, कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करना और पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाना।

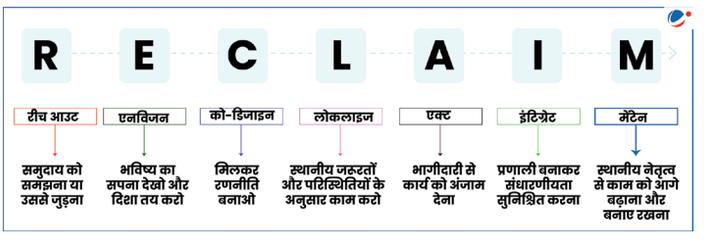

5.6.12. वेदर डेरिवेटिव्स (Weather Derivatives)

NCDEX-IMD साझेदारी के माध्यम से **वर्षा आधारित उत्पादों का उपयोग करते हुए पहला वेदर डेरिवेटिव्स** लॉन्च करेगा।

- **उद्देश्य: किसानों को अनियमित वर्षा,** हीटवेव्स और बेमौसम मौसम से बचाव में मदद करना।
- इसमें **ऐतिहासिक और रियल टाइम IMD डेटा का उपयोग किया जाएगा**; **स्थान-विशिष्ट और मौसमी आधारित अनुबंध**।
- **वेदर डेरिवेटिव्स के बारे में:** वित्तीय डेरिवेटिव के विपरीत, ये **मौसम संबंधी मापदंडों** और **मौसम सूचकांक पर आधारित होते हैं**; **1990 के दशक से वैश्विक स्तर पर इनका कारोबार किया जाता है**, जो भारत का पहला बड़ा कदम है।

5.6.13. मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है (Human-Made Dams Have Shifted Earth's Poles)

बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की घूर्णन धुरी 1835 ई. से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित हो चुकी है, जिससे ट्रू पोलर वैंडर (ध्रुवीय भ्रमण/TPW) को बढ़ावा मिला है।

- **TPW: पृथ्वी के घूर्णन संबंधी संतुलन को बनाए रखने के लिए** ठोस भूपर्पटी/मेंटल का तरल कोर के चारों ओर के ऊपर घूर्णन करना, जो पारंपरिक रूप से हिमनदों के पिघलने, टेक्टोनिक्स और महासागरीय विस्थापन द्वारा संचालित होता है।
- **बांधों की भूमिका: जलाशय द्रव्यमान को अंतर्देशीय पुनर्वितरित करते हैं**, **जिससे घूर्णन में परिवर्तन होता है**; इसका प्रभाव बांध के आकार और स्थान के साथ बदलता रहता है।
- **प्रभाव: उपग्रह नेविगेशन**, अंतरिक्ष टेलिस्कोप को प्रभावित करता है, तथा **पृथ्वी के दिनों को थोड़ा लंबा कर देता है।**

ट्रू पोलर वैंडर

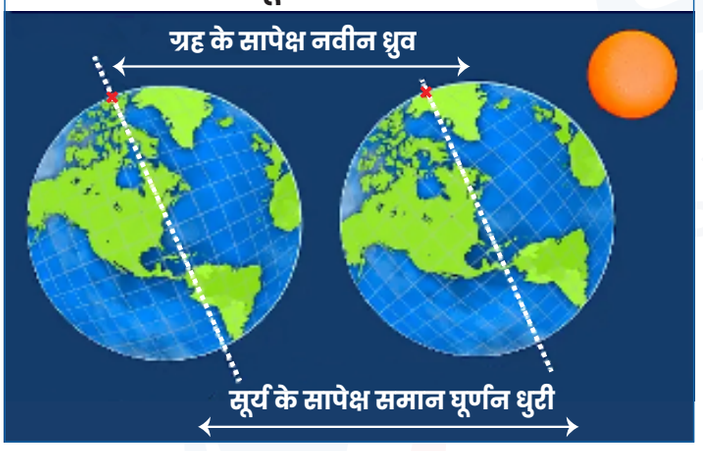

5.6.14. विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट {Winter Fog Experiment (WiFEX)}

WIFEX ने उत्तर भारत के घने शीतकालीन कोहरे पर 10 वर्षों का समर्पित अनुसंधान पूरा कर लिया है।

WIFEX के बारे में

- **विश्व के दीर्घकालिक ओपन-फ़ील्ड एक्सपेरिमेंट्स विशेष रूप से** कोहरे पर केन्द्रित।
- **संस्थान:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान।**
- **उद्देश्य:** बेहतर नाउ-कास्टिंग पूर्वानुमान (अगले 6 घंटे) विकसित करना तथा शीतकालीन कोहरे का पूर्वानुमान लगाना।

5.6.15. करियाचल्ली द्वीप (Kariyachalli Island)

तीव्र अपरदन और बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण यह निर्जन द्वीप काफी हद तक डूब गया है।

करियाचल्ली द्वीप के बारे में :

- **स्थान: तमिलनाडु में रामेश्वरम और तूतूकुड़ी के बीच मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र** में स्थित।
- **तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेज (TNSHORE) परियोजना के तहत कृत्रिम मॉड्यूल** के माध्यम से द्वीप के चारों ओर की चट्टानों को बहाल, **समुद्री घास के पौधे लगाने और समुद्री जीवन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।**

5.6.16. चिनाब नदी (Chenab River)

वन सलाहकार समिति ने **चिनाब नदी पर सावलकोट HEP** के निर्माण के लिए **वन भूमि के उपयोग को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है**।

- सावलकोट HEP (छह रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाओं में से एक)
- **उद्देश्य: सिंधु नदी के जल का अधिकतम उपयोग करना।**

चिनाब नदी के बारे में

- **उत्पत्ति: बारा लाचा पास**
  - **दो जल धाराएं: चंद्रा और भग** मिलकर चिनाब बनती है।
- चिनाब घाटी **महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के मध्य मौजूद एक संरचनात्मक गर्त।**
- **सहायक नदियाँ:** मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मारुसुदर और लिद्दारी।
- वैदिक काल में इसे **चंद्रभागा, अश्किनी या इस्कमती के नाम से जाना जाता था।**

5.6.17. टोकारा द्वीप (Tokara Islands)

दक्षिणी जापान के टोकारा द्वीपसमूह में 1,000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए।

- जापान **दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है।** यह प्रशांत महासागर के **"रिंग ऑफ फायर"** के पश्चिमी किनारे पर चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है।

टोकारा द्वीप के बारे में

- यह जापान में क्यूशू के दक्षिण और अमामी द्वीप के उत्तर में स्थित **है।**
- जापान का सबसे लंबा गांव **'तोशिमा'** इसी द्वीप पर स्थित है।

5.6.18. बिट्रा द्वीप (Bitra Island)

लक्षद्वीप प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए **बिट्रा द्वीप के अधिग्रहण पर विचार** कर रहा है।

बिट्रा द्वीप के बारे में

- मानव बसावट वाला **सबसे छोटा द्वीप**, जिसका क्षेत्रफल **0.105 वर्ग किमी है।**
- **अवस्थिति:** अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास।
- **जलवायु:** **'Aw' अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना** के रूप में वर्गीकृत।
  - औसत वर्षा: लगभग **1600 मिमी प्रति वर्ष।**

लक्षद्वीप के बारे में

- **भारत का सबसे छोटा** केंद्र शासित प्रदेश।
- लक्षद्वीप **अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल द्वीपों से मिलकर** बना है।
- तीन मुख्य भौगोलिक विशेषताओं में **एटॉल, लैगून और रीफ** शामिल हैं।

सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

6.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के 5 वर्ष {Years of National Education Policy (NEP)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के **5 वर्ष** पूरे हुए।

NEP 2020 के बारे में

- भारत की तीसरी शिक्षा नीति (1968 के बाद, 1986), **कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित।**
- **सिद्धांत:** वैचारिक समझ पर ज़ोर, तकनीक का उपयोग, विनियामक फ्रेमवर्क, विविधता, समानता, समावेशन, अनुसंधान और निरंतर प्रगति समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रमुख लक्ष्य

- प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) दिलाना वर्ष 2025 तक।
- **पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर** तक **100% सकल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य हासिल करना** – वर्ष 2030 तक।
- शिक्षा पर **सार्वजनिक निवेश 6% (GDP का)** करना।
- **उच्चतर शिक्षा** (व्यावसायिक शिक्षा सहित) में **50% सकल नामांकन अनुपात (GER) – वर्ष 2035 तक।**
- सभी **उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs)** को बहुविषयक संस्थान बनाना – **वर्ष 2040 तक।**
- **कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का 2025** तक- स्कूल और उच्चतर शिक्षा के कम से कम **50% विद्यार्थियों** को **व्यावसायिक शिक्षा** का अनुभव दिलाना

प्रमुख उपलब्धियां

- **स्कूली शिक्षा**
  - प्राथमिक स्तर पर **GER लगभग**, 93%
  - **स्कूल ड्रॉपआउट दर में गिरावट** (प्राथमिक 1.9%, उच्च प्राथमिक 5.2%, माध्यमिक 14.1%)।
  - **डिजिटलीकरण:** कंप्यूटर वाले स्कूलों की संख्या 38.5% से बढ़कर 57.2% हो गई, इंटरनेट की पहुंच 22.3% से बढ़कर 53.9% हो गई।
- **उच्चतर शिक्षा**
  - **GER** 23.7% से बढ़कर 28.4% हो गया
  - **कुल उच्चतर शिक्षण संस्थानों में** 13.8% की वृद्धि हुई।
- **ग्रामीण स्कूलों**
  - **FLN निर्देश:** 15,728 ग्रामीण विद्यालयों में से 80% से अधिक को FLN निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।
  - 6-14 वर्ष के बच्चों में **नामांकन 95% है।**
  - 15-16 वर्ष के बच्चों का नामांकन न होने की दर 13.1% से घटकर 7.9% हो गयी।

प्रमुख सरकारी योजनाएं/ पहलें

- **पीएम श्री/ PM SHRI (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया):** इसका लक्ष्य 2022-2027 तक **14,500 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प** करना है।
- **निपुण भारत:** 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (FLN) सुनिश्चित करना।
- **ONOS: विद्वत्तापूर्ण शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच** प्रदान करती है।
- **CwSN) के लिए पहल:** पीएम ई-विद्या DTH चैनल; प्रशस्त (PRASHAST) नामक दिव्यांगता स्क्रीनिंग व्यवस्था आदि।
- **प्रेरणा (PRERNA):** आवासीय अनुभवात्मक शिक्षा IX – XII.
- **ULLAS या NILP:** 15+ वर्षों के लिए वयस्क साक्षरता।
- **विद्यांजलि:** स्वयंसेवी आधारित स्कूली कार्यक्र और CSR भागीदारी।
- **RVSK: साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने** के लिए स्कूली शिक्षा के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) पर **रियल टाइम आधारित डेटा** प्रदान करता है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण: 12.97 लाख निष्ठा** के तहत प्रशिक्षित ।
- **नवाचार:** 92,168 पेटेंट दायर किए गए, **उच्चतर शिक्षण संस्थानों का योगदान** 25% है।
- **समावेशिता: 7.58 लाख लड़कियां** आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय** परिसरों की स्थापना की गई।
- **साक्षरता:** लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक क्षेत्र बना।
- **बहुभाषावाद:** 12 भाषाओं में परीक्षाएं .
- **परख** 21.15 लाख छात्रों का सर्वेक्षण किया गया।

कार्यान्वयन में बाधाएँ

- **वित्तपोषण:** भारत में कुल शिक्षा व्यय **GDP के 3% के आस-पास बनाम NEP का लक्ष्य 6%** ; इनपुट-संचालित वित्तपोषण सीखने के परिणामों को सीमित करता है।
- **केंद्र-राज्य विभाजन: कुछ राज्यों (जैसे, केरल, पश्चिम बंगाल) ने** NEP को पूर्ण रूप से अपनाने की आवश्यकता वाले पीएम-श्री समझौता ज्ञापनों को अस्वीकार कर दिया।
- **संस्थागत विलंब** : HECI का गठन और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के गठन में देरी।
- **अति नियमन:** UGC/AICTE के अंतर्गत 50 से अधिक नियम शिक्षा और अनुसंधान पर बोझ डालते हैं।
- **प्रतिधारण दर** : उच्चतर माध्यमिक प्रतिधारण केवल 45.6% (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **अन्य मुद्दे: शिक्षकों को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है**, **त्रि-भाषा फार्मूले का विरोध** , प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रभावी शिक्षण अवधि की कमी (35 मिनट/दिन), और चार-वर्षीय स्नातक डिग्री को लागू करने में अवसंरचना और फैकल्टी की कमी के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

NEP 2020 को लागू करने संबंधी सुधारों के लिए आगे की राह

- **परिणाम-आधारित वित्तपोषण (OBF)**: भुगतान पूर्व-परिभाषित व सत्यापित परिणामों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाता हो, न कि इनपुट या गतिविधियों के आधार पर।
- **मजबूत समन्वय** : साझा **निगरानी और स्थानीय अनुकूलन।**
- **तकनीक-सक्षम शिक्षा:** शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र ट्यूशन के लिए एआई का उपयोग करें।
- **संरचित पीयर लर्निंग को एकीकृत करना:** FLN कौशल के लिए मिशन अंकुर जैसी पहल।
- **क्षमता निर्माण:** फैकल्टी विकास और नेतृत्व समर्थन।
- **विकेंद्रीकरण और लचीलापन:** संस्थानों को NEP को अपनाने की अनुमति दें, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

NEP 2020 ने समावेशिता, गुणवत्ता और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए वित्त-पोषण में वृद्धि, बेहतर गवर्नेंस व अवसंरचना और नीतिगत बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।

6.2. छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं (Rising Suicides Among Students)

सुर्ख़ियों में क्यों?

छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने **सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** वाद में कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स में **छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

छात्रों के बीच बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट

- **NCRB (2022)** : **7.6% आत्महत्या करने वाले छात्र थे।**
- **छात्र आत्महत्याएं (2012-2022)** : पुरुष **99%** और **महिला 92%** ।

अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

अमित कुमार बनाम भारत संघ (2025): विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के मामले को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया।

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018): मानसिक स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है (अनुच्छेद 21)।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संकट के पीछे के कारक

- **शैक्षणिक दबाव:** परीक्षा तनाव, असंतोष, असफलता।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** रैगिंग, धमकाना, उत्पीड़न।
- **मौन की संस्कृति:** खुली चर्चा का अभाव, कमजोर सुरक्षा उपाय।
- **विधायी और विनियामक शून्यता** : छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए फ्रेमवर्क का अभाव है।
- **पारिवारिक मुद्दे:** संघर्ष, उपेक्षा, वित्तीय तनाव, हानि, व्यसन, मानसिक बीमारी।
- **अन्य:** कम आत्मसम्मान, अलगाव, जाति/लिंग भेदभाव।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहल

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** अधिकार-आधारित देखभाल सुनिश्चित करता है; आत्महत्या को अपराध मुक्त करता है।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022): 2030 तक आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु दर को 10% तक कम** करना है।
- **टेली मानस:** टोल-फ्री राष्ट्रव्यापी टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवा।
- **मनोदर्पण :** इसकी शुरुआत **शिक्षा मंत्रालय** ने की है। इसका उद्देश्य छात्रों एवं शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी करना व उन्हें दूर करना है।
- **मालवीय मिशन:** एनईपी 2020 के तहत फैकल्टी को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और शीघ्र हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाना है।
- **कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश** : कोचिंग सेंटर्स में परामर्शदाताओं द्वारा काउंसलिंग को प्राथमिकता देना; बैचों में कोई अलगाव न रखना; रिकॉर्ड का रखरखाव करना आदि।

आगे की राह: सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- **एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति:** वार्षिक समीक्षा के साथ-साथ इसे लगातार अपडेट भी किया जाएगा।
- **परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक/सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करें : 100 या अधिक छात्रों** वाले संस्थान में।
- **अनिवार्य प्रशिक्षण:** मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिक चिकित्सा पर।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** सभी शैक्षणिक संस्थानों में।
- **माता-पिता की संवेदनशीलता:** शैक्षणिक दबाव डालने से बचना, सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक संकट के संकेतों को पहचानना।
- **पाठ्येतर गतिविधियाँ:** खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **कोचिंग हब:** मजबूत सुरक्षा, संरचित कैरियर परामर्श।
- **आवासीय शैक्षणिक संस्थान:** यह सुनिश्चित करें कि परिसर बदमाशी, नशीली दवाओं, उत्पीड़न से मुक्त हो।

निष्कर्ष

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए समग्र कार्रवाई की आवश्यकता है: सहकर्मी समर्थन, वित्त पोषण, जवाबदेही, सुरक्षित डिजिटल उपयोग, कलंक में कमी, शीघ्र हस्तक्षेप और सुलभ देखभाल।

6.3. सामाजिक विलगाव (Social Isolation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **'अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक: स्वस्थ समाजों के लिए मार्ग तैयार करना'** नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट **स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक विलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव** पर प्रकाश डालती है।

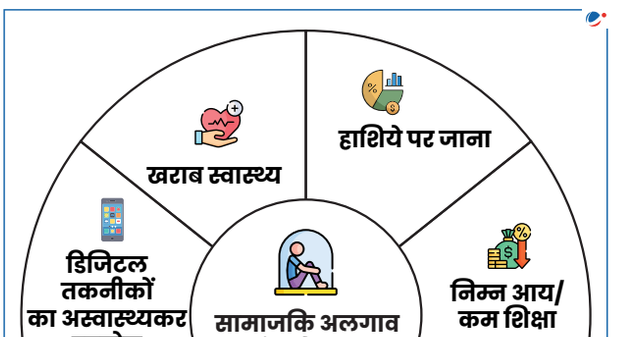

सामाजिक जुड़ाव और विलगाव क्या है?

- **सामाजिक जुड़ाव:** परिवार, मित्रों, साथियों, सहकर्मियों, पड़ोसियों के साथ बातचीत।
- **सामाजिक विलगाव:** रिश्तों की कमी/खराब गुणवत्ता।
  - **अकेलापन:** यह तब महसूस होता है, जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है।
  - **सामाजिक अलगाव:** जब किसी व्यक्ति के बहुत कम मित्र, रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग होते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **वियोग :** 6 में से 1 व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है (2014-23); युवा सबसे अधिक अकेले हैं; 3 में से 1 वृद्ध वयस्क, 4 में से 1 किशोर अलग-थलग है।
- **असमानताएँ : निम्न आय वाले देशों में 24% लोग सामाजिक रूप से विलगाव की स्थिति में है,** जबकि उच्च आय वाले देशों में 11% लोग सामाजिक रूप से विलगाव की स्थिति में है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :** 014-2019 के दौरान लगभग **871,000 मौतें** अकेलेपन से संबंधित थी,
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इसमें अवसाद, एंजायटी, डिमेंशिया आदि शामिल हैं।

सामाजिक संबंध सुधारने का रोडमैप

- **नीति:** राष्ट्रीय रणनीतियां (जैसे, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी)।
- **अनुसंधान:** वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना, चुनौतियां पेश करना।
- **हस्तक्षेप:** इंटरवेंशन एक्सलेरेटर शुरू किया जाना चाहिए, सामुदायिक अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **मापन:** वैश्विक सामाजिक संपर्क सूचकांक.
- **सहभागिता:** अभियान, कार्यक्रम, समूह गतिविधियां और सामाजिक निर्देश।

6.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.4.1. सामाजिक संगठनों की भूमिका (Role of Social Organisations)

लोक सभा अध्यक्ष ने देश और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया।

- **सामाजिक संगठन** का अर्थ है कि समाज में लोग और समूह किस तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कैसे आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये संगठन **औपचारिक** (जैसे धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, श्रमिक संघ आदि) या **अनौपचारिक** (जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी समूह आदि) हो सकते हैं।

राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका

सामाजिक संस्थाएं	राष्ट्र निर्माण में भूमिका
परिवार	मूल्यों, मानदंडों, नैतिक व्यवहार को प्रसारित करता है; सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देता है।
धार्मिक संस्था	नैतिक ढांचा प्रदान करना, करुणा, दान, सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक एकजुटता को मजबूत करना।
शैक्षिक संस्था	ज्ञान/कौशल प्रदान करना; अनुशासन और टीमवर्क की भावना विकसित करना; व्यक्तियों को जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना।
गैर सरकारी संगठनों	**नीतियों को दिशा देना (** जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन और RTI)। **जागरूकता एवं क्षमता निर्माण** (जैसे लिंग संबंधी मुद्दों पर सेवा)। **सेवा वितरण** (जैसे शिक्षा में प्रथम) **लोकतंत्र को मजबूत करना** (जैसे राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ ADR)।

सामाजिक संगठन मूल्यों, संस्कृति और शासन को आकार देते हैं, जिससे वे, संधारणीय, समावेशी व अनुकूलनशील समाजों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं।

6.4.2. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

CARA ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए।

- ये निर्देश **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARAs)** के लिए जारी किए गए हैं।

SARAs को दिए गए मुख्य निर्देश:

- पीएपी, गोद लिए गए बच्चों और जैविक माता-पिता के लिए **मनोसामाजिक सहायता ढांचे को मजबूत** किया जाए।
- जिला एवं राज्य स्तर पर **योग्य परामर्शदाताओं को नामित/पैनलबद्ध करना।**
- **विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAAs) या जिला बाल संरक्षण इकाइयां (DCPUs)** द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करना।

भारत में बाल दत्तक ग्रहण

- **नोडल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- **कानून: हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956** और **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।**
- **केंद्रीय एजेंसी** : CARA (जेजे अधिनियम के तहत) घरेलू और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा** : हेग कन्वेंशन (1993) नैतिक, पारदर्शी दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करता है, तस्करी को रोकता है।
- **राज्य की भूमिका** : SARAs, CWCs और DCPUs के माध्यम से जेजे अधिनियम को लागू करना।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

स्थिति: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।

कार्य: यह देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों की निगरानी करता है।

भूमिका: हेग कन्वेंशन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारत ने हेग कन्वेंशन की 2003 में अभिपुष्टि की थी।

6.4.3. "नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन" में काशी घोषणा-पत्र पारित हुआ (Kashi Declaration Adopted in Youth Spiritual Summit for Drug-Free India)

युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ने राष्ट्रीय युवा-नेतृत्व वाले नशा-विरोधी अभियान की नींव रखी है। यह शिखर सम्मेलन व्यापक **'मेरा युवा (MY) भारत फ्रेमवर्क' का हिस्सा है।**

- **मेरा भारत:** युवा विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; यह एक स्वायत्त निकाय है।

काशी घोषणा

- नशा मुक्ति के लिए 5 वर्षीय **रोडमैप।**
- **मादक द्रव्यों के सेवन को** सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक चुनौती के रूप में देखता है।
- **संस्थागत तंत्र:** संयुक्त राष्ट्रीय समिति, वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय समर्थन मंच।
- आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी प्रयासों का **एकीकरण।**

अन्य नशा-विरोधी पहल

- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985;
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1988;
- नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR), 2018-25;
- नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA), 2020 आदि।

भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग (2019 सर्वेक्षण)

- **14.6%** (आयु **10 और 75)** शराब का सेवन करते हैं।
- **कैनबिस और ओपिओइड्स** अगले सबसे आम हैं।

नशीले पदार्थों के उपयोग के पीछे प्रमुख कारक

- **सामाजिक कारक:** जैसे- साथियों का दबाव, पारिवारिक कलह और सामाजिक अलगाव।
- **आर्थिक कारक:** जैसे- बेरोजगारी और गरीबी।
- **मनोवैज्ञानिक कारक:** जैसे- एंग्जायटी और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।
- **शैक्षणिक/ कार्य संबंधी तनाव:** जैसे- शिक्षा और नौकरियों से संबंधित अधिक दबाव जोखिम को बढ़ाता है, खासकर युवाओं में।
- **उपलब्धता:** भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है।

6.4.4. तलाश पहल (Talash Initiative)

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर **तलाश (TALASH)** पहल शुरू की है। **NESTS** केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

तलाश (TALASH) पहल के बारे में

- यह एक **राष्ट्रीय कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास (शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास दोनों) को समर्थन देना है।
- **EMRS केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है। इसके तहत उन ब्लॉकों में **जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा** की सुविधा प्रदान की जाती है जहाँ **अनुसूचित जनजातियों (ST) की आबादी 50% से अधिक** होती है।
- यह एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:
  - **साइकोमेट्रिक मूल्यांकन**: यह **NCERT की 'तमन्ना' पहल से प्रेरित** है।
  - **कैरियर परामर्श,**
  - **जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल,**
  - शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग।

6.4.5. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI, 2025) रिपोर्ट जारी की गई {State of Food Security And Nutrition In The World (SOFI) 2025 Report Released}

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक भुखमरी** घटकर 8.2% रह जाएगी, लेकिन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में इसमें वृद्धि जारी रहेगी।
- वर्ष 2021 से **मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी** आई है।
- **खाद्य पदार्थों की कीमतें** बढ़ गईं, जिससे स्वस्थ आहार की लागत बढ़ गई; इसे वहन करने में असमर्थ वैश्विक जनसंख्या 2.76 बिलियन (2019) से घटकर 2.60 बिलियन (2024) हो गई।
- वैश्विक स्तर पर **महिलाओं में एनीमिया** और **वयस्क मोटापा** बढ़े जा रहे हैं।

SOFI 2025 के बारे में

के बारे में

SOFI रिपोर्ट **संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की एक संयुक्त पहल है।

उद्देश्य

यह **सतत विकास लक्ष्य-2 (SDG-2) के टार्गेट्स 2.1 और 2.2** के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। **SDG-2** का उद्देश्य सभी रूपों में **भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त** करना है।

भारत से संबंधित निष्कर्ष

- **भारत को छोड़कर, अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों** की संख्या में **वृद्धि** देखी जा रही है।
- **केरल** में मछुआरों और थोक विक्रेताओं द्वारा **मोबाइल फोन के उपयोग से मूल्य असमानता एवं अपव्यय में कमी** आई है।

सिफारिश

- **लक्षित राजकोषीय उपाय** और **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।**
- बाजारों को स्थिर करने के लिए **राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप** बनाया जाना चाहिए।
- कृषि बाजार सूचना प्रणालियों को मजबूत बनाना।

7.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह {NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) Satellite}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निसार उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

निसार उपग्रह के बारे में

- **संयुक्त इसरो-नासा,** L और S-बैंड **माइक्रोवेव इमेजिंग उपग्रह** ; पूर्णतया **पोलरिमेट्रिक एवं इंटरफेरोमेट्रिक।**
- **नासा का योगदान:** L-बैंड रडार, GPS, दूरसंचार, एंटीना (1.16 बिलियन डॉलर); **इसरो:** S-बैंड रडार, बस, GSLV-F16 ($90M)।
- **वजन :** 2,392 किलोग्राम
- **कक्षा:** सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा
- **मिशन जीवन:** 5 वर्ष.

NISAR मिशन के उद्देश्य

- **लकड़ी वाली बायोमास (पेड़ों, फसलों)** और उसमें होने वाले बदलाव को **मापना।**
- सक्रिय फसलों (active crops) के **क्षेत्र में होने वाले बदलाव को ट्रैक करना।**
- **आर्द्रभूमियों के क्षेत्र** में होने वाले बदलाव को समझना।
- **ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की हिम-चादरों (ice sheets)** की **मैपिंग करना,** समुद्री बर्फ और पहाड़ी ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- **भूमि सतह के विकृति (land surface deformation) की पहचान करना,** जो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, धँसाव और ऊँचाई में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। यह भूमिगत जलभृतों, हाइड्रोकार्बन भंडार आदि के बदलाव से भी संबंधित है।

तकनीकी विशेषताएं

- **SweepSAR: हर 12 दिन में** उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाइड-स्वैथ इमेजिंग के लिए ।
- **ड्यूल-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (L-बैंड और S-बैंड SAR):** वनस्पति, बर्फ, मिट्टी और छतरी की निगरानी के लिए।
- 12-मीटर **तैनात करने योग्य एंटीना** ; **वैश्विक पहुंच के लिए खुले ओपन-डेटा नीति**।

SAR के बारे में

- SAR एक सक्रिय सुदूर संवेदन तकनीक है जो पृथ्वी से ऊर्जा का एक पल्स (Pulse) भेजता है और उनके प्रतिबिंब को रिकॉर्ड करती है।
- ऑप्टिकल इमेजरी (निष्क्रिय) के विपरीत, SAR भूभाग, वनस्पति, बर्फ और मिट्टी की नमी के साथ अंतःक्रिया को कैप्चर करता है।

सिंथेटिक क्यों?

- उच्च **स्थानिक रिजोल्यूशन** के लिए अव्यावहारिक रूप से लम्बे एंटेना की आवश्यकता होती है।
- SAR एक छोटे एंटीना से **कई अधिग्रहणों को संयोजित कर एक बड़े एंटीना का अनुकरण करता है, जिससे** कुशलतापूर्वक **उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग प्राप्त होती है ।**

निष्कर्ष

भारत के लिए आपदा तैयारी, जलवायु लचीलापन, सतत विकास और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाता है।

7.2. ब्लैक होल विलय (Black Hole Merger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, गुरुत्वाकर्षण तरंग या गुरुत्वीय तरंग वेधशालाओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने **दो बेहद विशाल ब्लैक होल्स के विलय का पता लगाया है।**

अन्य संबंधित तथ्य:

- **ब्लैक होल:** ये दोनों ब्लैक होल्स आकर में सूर्य से क्रमशः 140 गुना और 100 बड़े हैं। यह **अब तक का सबसे बड़ा विलय था।**
- **घटना नाम:** इस नवीनतम खोज को **GW231123** नाम दिया गया है; यह घटना असल में **कई अरब साल पहले घटी** थी।

ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क

- **लिगो (USA):** सबसे बड़ी वेधशाला, हैनफोर्ड और लिविंगस्टन में दो डिटेक्टर।
  - DAE, DST और US NSF के सहयोग से महाराष्ट्र के हिंगोली में LIGO-India की योजना बनाई गई है।
- **विर्गो (इटली):** यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला (इटली और फ्रांस) द्वारा आयोजित।
- **कागरा, जापान:** कामिओका खदान के अंदर स्थित है ।

इस घटना का महत्व:

- **खगोल-भौतिकी और कॉस्मोलॉजिकल मॉडल को बेहतर करना:** इस खोज से ब्लैक होल के निर्माण, तारों के विकास और संभवतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वर्तमान मॉडल्स के बारे में मौजूदा समझ को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
- **ब्लैक होल के निर्माण की मौजूदा समझ को चुनौती: सबसे बड़े और सबसे तेज घूमने वाले ब्लैक होल का पता चला** , जो जटिल निर्माण इतिहास का संकेत देता है।
- **हाइड्रार्किकल मर्जर्स के बारे में बेहतर जानकारी:** एक प्रस्तावित सिद्धांत यह है कि ऐसे विशाल इंटरमीडिएट-मास ब्लैक होल्स (जैसे, GW231123 में देखे गए) छोटे ब्लैक होल्स के विलयों की श्रृंखला के माध्यम से बन सकते हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंगों को एक नए वैज्ञानिक साधन के रूप में उपयोग करना:** प्रकाश के लिए अदृश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन को सक्षम बनाती हैं; **जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने 1915 में अंतरिक्ष-समय में तरंगों के रूप में की थी।**

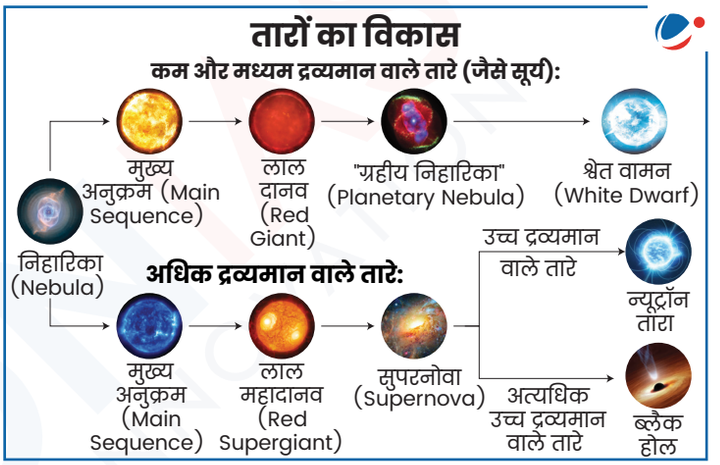

ब्लैक होल

- **ब्लैक होल:** अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता, यह एक छोटे से स्थान में संकुचित पदार्थ से निर्मित होता है।
- **पता लगाना:** दूरबीनों के लिए अदृश्य; निकटवर्ती तारों और गैस पर प्रभाव के माध्यम से अध्ययन किया गया।
- **निर्माण** : ज्यादातर ब्लैक होल्स सुपरनोवा विस्फोट में नष्ट होने वाले एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं; छोटे केन्द्रक न्यूट्रॉन तारे बन सकते हैं।
- **प्रकार:** स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल।

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.3.1. ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग (Bluetooth Mesh Networking)

ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने **ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप "बिटचैट" के बारे में जानकारी** दी।

- बिटचैट एक नया **पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप** है, जो बिना किसी **केंद्रीकृत सर्वर या फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन** को संभव बनाता है। बिटचैट **संचार को संभव** करने के लिए **ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग** का उपयोग करता है।

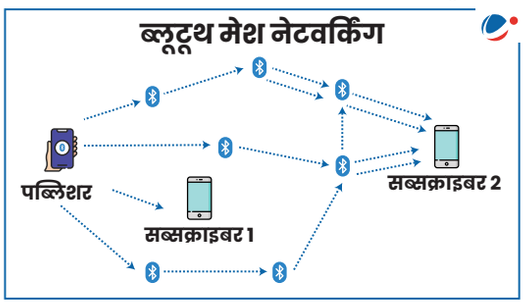

ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है?

- **ब्लूटूथ क्लस्टर** या **मेश नेटवर्क** पर निर्भर करता है
- **मेष नेटवर्क** या " **मल्टी-हॉप नेटवर्क** ", एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी है।
  - **डेटा किसी भी डिवाइस से** अन्य सभी डिवाइस तक जा सकता है, जिससे **अनेक-से-अनेक संचार संभव हो जाता है** ।
  - यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए तो भी नेटवर्क काम करता रहता है।

फायदे

- **कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं: मेसेज पूरी तरह से उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस पर संग्रहित** होते हैं और थोड़े समय के बाद डिलीट हो जाते हैं।
  - **उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को प्राथमिकता दें** .
- **पंजीकरण की आवश्यकता नहीं**
- कम बिजली की खपत, आदि.

प्रमुख सीमाएँ : उच्च विलंबता, जटिल नेटवर्क प्रबंधन, कम डेटा स्थानांतरण दर, आदि।

7.3.2. AI अलायंस नेटवर्क {AI Alliance Network (AIANET)}

डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (DIF) ने पाकिस्तान के **AI टेक्नोलॉजी सेंटर (AITeC)** के AIANET में शामिल होने के आवेदन पर आपत्ति जताई है।

- DIF एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है जिसका लक्ष्य डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना तथा विकास प्रक्रिया के लिए इंटरनेट और संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।

AIANET के बारे में

- **परिचय:** यह एक **अनौपचारिक और स्वैच्छिक नेटवर्क** तथा कम्युनिटी है, जो अपने सदस्यों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा सूचना और विशेषज्ञता साझा करने का मंच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना ताकि दीर्घकालिक सतत समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास** को बढ़ावा दिया जा सके।
- **सदस्य:** इसमें **17 सदस्य** हैं।
- **प्रशासन:** इसे **AI अलायंस रूस** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

7.3.3. WHO ने "3 बाय 35" पहल शुरू की (WHO Launches "3 By 35" Initiative)

इस पहल का उद्देश्य **2035 तक स्वास्थ्य कर (Health Tax)** के माध्यम से तम्बाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में **कम-से-कम 50% की वृद्धि** करना है।

- **सहयोगात्मक गठबंधन:** इसमें विकास साझेदार, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और राष्ट्रीय सरकारें शामिल होती हैं।

स्वास्थ्य कर क्या है?

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर** हानिकारक प्रभाव डालने वाले **उत्पादों पर लगाया गया कर**, जैसे तंबाकू, शराब आदि।
- मोटापे और गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए इसकी सिफारिश करता है ।

स्वास्थ्य कर की आवश्यकता क्यों है?

- **स्वास्थ्य प्रभाव** : गैर-संचारी रोग वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इससे 2012 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था।
- **आय:** 50% कर से पांच वर्षों में 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हो सकती है।
- **हिस्सेदारी:** असमान रूप से प्रभावित निम्न आय वर्ग की आबादी को संरक्षण प्रदान करता है।

भारत के उपाय

- **वातित पेय** पर 28% GST + 12% उपकर
- **उच्च वसायुक्त चीनी नमक (HFSS)** खाद्य पदार्थों पर 12% GST
- **एफएसएसएआई ने ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) की मात्रा** 2% तक सीमित कर दी है।

सफल वैश्विक केस स्टडीज

कोलंबिया (2016): कोलंबिया में सिगरेट पर कर बढ़ाने से **सिगरेट के उपभोग में 34% की गिरावट** आई है।

सऊदी अरब: शर्करा युक्त मिठाई और पेय पदार्थ (SSB) पर **50% कर** लगाने के परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर **SSBs के उपभोग में 19% की कमी** आई है।

7.3.4. टीकाकरण पर WHO/ UNICEF के आंकड़े (WHO/UNICEF Data on Immunization)

WHO/ UNICEF के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मुख्य निष्कर्ष

- **वैश्विक:** 2024 में 89% शिशुओं को डीटीपी टीके की ≥1 खुराक दी जाएगी।
- **भारत:** जीरो-डोज बच्चों की संख्या में 43% की कमी (1.6 मिलियन → 0.9 मिलियन)।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) भारत

- 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया, 1985 में यूआईपी के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया ।
- **कवरेज** : 12 बीमारियों के विरुद्ध:
  - **राष्ट्रव्यापी (9):** डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस और निमोनिया।
  - **क्षेत्र-विशिष्ट (3):** रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस।
- **पूर्ण टीकाकरण:** बच्चे को पहले वर्ष के भीतर सभी निर्धारित टीके लग जाते हैं।
- **उपलब्धियां:** पोलियो मुक्त भारत (2014), नवजात टिटनेस उन्मूलन (2015)।
- **प्रमुख पहल:** गहन मिशन इंद्रधनुष 5.0, यू-विन पोर्टल, खसरा और रूबेला कवरेज पर ध्यान।

7.3.5. फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक (Phenome India National Biobank)

CSIR-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया गया।

- भारत के **लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस को उन्नत करना।**
- **परिशुद्ध चिकित्सा** और **जैव चिकित्सा अनुसंधान को** बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय बायोबैंक के बारे में

- इसे **फेनोम इंडिया परियोजना** के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
  - यह **यूनाइटेड किंगडम बायोबैंक मॉडल** पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय विविधता के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
- **उद्देश्य: AI-संचालित डायग्नोस्टिक्स** और **जीन-गाइडेड चिकित्सा** का उपयोग करके जटिल रोगों पर शीघ्र निदान, लक्षित चिकित्सा और अनुसंधान का समर्थन करना ।
- **कवरेज: 10,000 व्यक्तियों** का व्यापक जीनोमिक, जीवनशैली युक्त और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा।

फेनोम इंडिया परियोजना

- इसे आधिकारिक तौर पर **फेनोम इंडिया-CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेजबेस (PI-CheCK)** कहा जाता है।
- 2023 में CSIR **द्वारा लॉन्च किया जाएगा ।**
- **उद्देश्य:** दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रक्षेप पथ पर नज़र रखना।

फेनोम क्या है?

- फेनोम किसी **कोशिका, ऊतक, अंग, जीव या प्रजाति में फेनोटाइप (दिखाई देने वाली विशेषताओं) का संपूर्ण समूह** होता है।
- **फेनोटाइप किसी जीव की दिखाई देने वाली विशेषताओं** को कहते हैं।
  - इनमें जीव की **शारीरिक की बनावट, रंग, कद, व्यवहार** आदि शामिल होते हैं।
  - किसी जीव का **फेनोटाइप उसके जीनोटाइप** के साथ-साथ उसके जींस पर पड़ने वाले **पर्यावरणीय प्रभावों** द्वारा निर्धारित होता है। **जीनोटाइप** जीव में मौजूद **जींस का समूह** होता है।

8.1. चोल गंगम झील (Chola Gangam Lake)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तमिलनाडु **चोल गंगम झील** को विकसित करने का फैसला किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- घोषणा **राजेंद्र चोल प्रथम** की जयंती मनाने हेतु आयोजित **आदि तिरुवथिराई महोत्सव** के दौरान की गई।
- आदि तिरुवथिराई महोत्सव **राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान** और गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण के 1,000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया।
  - इसमें 63 **नयनमार** (चोल संरक्षित संत-कवि) और **शैव सिद्धांत दर्शन** का सम्मान किया जाता है।

चोल गंगम झील के बारे में

- यह भारत की **सबसे बड़ी प्राचीन मानव-निर्मित झील** है।
- **स्थान: अरियालुर जिले** में गंगईकोंडा चोलपुरम के नजदीक।
- **निर्माण: राजराज प्रथम** के सुपुत्र **राजेंद्र चोल प्रथम** (**1014 से 1044 ईस्वी**) ने करवाया था।
  - **तिरुवलंगडु ताम्रपत्रों** के अनुसार, राजेंद्र चोल प्रथम ने गांगेय क्षेत्र अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में **गंगईकोंडा चोलपुरम** को अपनी राजधानी बनाया।
  - इसी कारण उसने **'गंगईकोंडा चोल'** की उपाधि धारण की।
- **चोल प्रशासन:**
  - **प्रारंभिक चोल:** संगम काल; करिकाल चोल ने पुहार की स्थापना की।
  - **साम्राज्यवादी चोल:** 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल एक एक बार फिर प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे।
  - **इतिहास:** उसने गंगा नदी का पवित्र जल इस झील में डाला था। इसी वजह से झील का नाम **चोल गंगम** पड़ा। विजयनगर काल के दौरान इस झील को **पोन्नेरी** कहा जाता था।
  - **जल स्रोत:** कावेरी की शाखा कोल्लिडम नदी से नहर द्वारा जलापूर्ति।
  - **संरचना:** झील के **अंडाकार** तटबंध को **लैटेराइट चट्टानों** से मजबूती प्रदान की गई है।
  - **उद्देश्य:** पेयजल और सिंचाई।

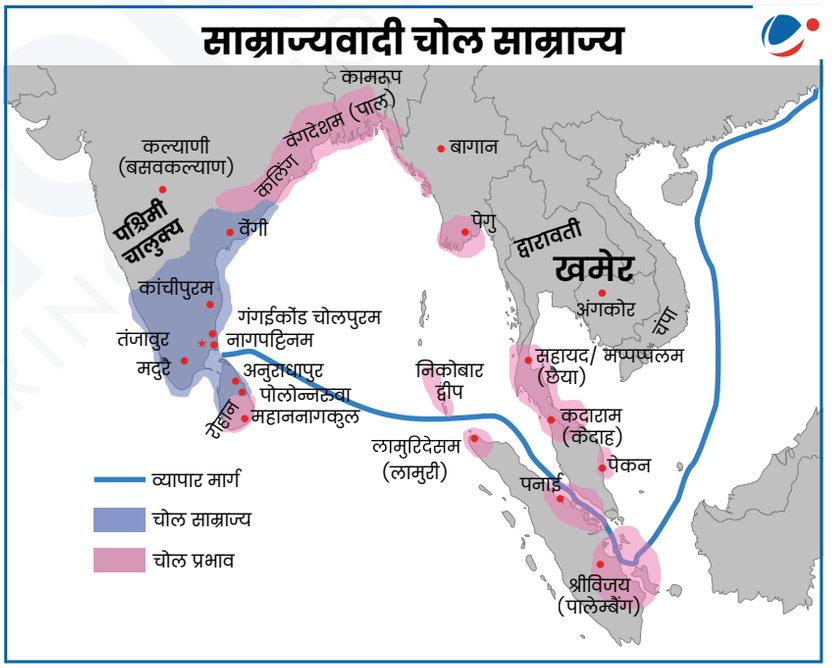

चोल साम्राज्य (9वीं शताब्दी - 13वीं शताब्दी) के बारे में

- **उत्पत्ति:** चोल पल्लवों के अधीन उरैयूर में सामंत के रूप में कार्य करते थे। **9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के नेतृत्व में चोल साम्राज्य की स्थापना** की।
- **प्रमुख अभिलेख: उत्तरमेरूर अभिलेख में** चोलों की प्रशासनिक और स्थानीय स्वशासन चुनाव प्रणाली का विवरण।
- **प्रशासन:** प्रांतों को **मंडलम** कहा जाता था। मंडलम के नीचे की प्रशासनिक इकाइयां **वलनाडु → नाडु → कुर्रम** और **कोट्टम** थीं।
- **स्थानीय स्व-शासन:** ग्राम सभा को **उर** या **सभा** के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों का चुनाव **कुडावोलाई प्रणाली** द्वारा।
- **कर प्रणाली: वेट्टि** (बंधुआ मजदूरी), और **कडमई** (भू-राजस्व)।

- **समुद्री शक्ति:**
  - **शक्तिशाली नौसेना:** राजराज चोल और राजेंद्र चोल शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। 1025 ई. में **श्रीविजय साम्राज्य पर अभियान** उल्लेखनीय रहा।
  - **व्यापार/कूटनीतिक संबंध:** श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ।
  - **प्रमुख बंदरगाह: महाबलीपुरम**, **कावेरीपट्टनम** (जिसे **पूम्पुहार** भी कहा जाता है), और **कोरकई**।
- **सांस्कृतिक उपलब्धियां:**
  - **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:** गंगईकोंडा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर।
  - विशेष रूप से **नटराज की उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा** के लिए प्रसिद्ध।

महत्त्वपूर्ण चोल मंदिर

विवरण	**बृहदेश्वर मंदिर के बारे में**	**गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में**	**ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में**
स्थान	तंजावुर जिला	गंगईकोंडा चोलपुरम	तंजावुर जिले के दारासुरम में
स्थापत्य शैली	द्रविड़	द्रविड़	द्रविड़ शैली, यह मंदिर रथ जैसा प्रतीत होता है।
अधिष्ठाता देवता	भगवान शिव	भगवान शिव	भगवान शिव
निर्माण काल	1010 ईस्वी	1035 ईस्वी	12वीं शताब्दी
निर्माता	राजराज चोल प्रथम	राजेंद्र चोल प्रथम	राजराज चोल द्वितीय
अन्य तथ्य	**पेरुवुदैयार कोविल**।	विमान की ऊंचाई 55 मीटर। अन्य नाम **बृहदेश्वर मंदिर**।	भगवान इंद्र के वाहन सफेद हाथी **'ऐरावत'** के नाम पर।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल	सूची में शामिल	सूची में शामिल	सूची में शामिल
प्रमुख विशेषता	शहर के भाग्य के उदय और पतन का वर्णन करते हैं।	**नटराज, दक्षिणामूर्ति, हरिहर, लिंगोद्भव, विष्णु, ब्रह्मा, महिषासुरमर्दिनी, ज्ञान सरस्वती आदि**।	भारतीय पुराणों में वर्णित कथाओं का विवरण। **संगीत की सात धुनों का प्रतिनिधित्व**।

निष्कर्ष

चोल गंगम झील और मंदिर चोलों की **इंजीनियरिंग क्षमता, समुद्री शक्ति, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक दृष्टि** को दर्शाते हैं। इनमें **उपयोगिता, कला और आध्यात्मिकता** का सुंदर संगम दिखाई देता है। इनकी विरासत भारतीय स्थापत्य कला, जल प्रबंधन, समुद्री अभियानों और शैव परंपराओं में आज भी जीवित है और भारतीय सांस्कृतिक गौरव को प्रेरित करती है।

8.2. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप (Maratha Military Landscape)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में **भारत के 44वें यूनेस्को धरोहर स्थल** के रूप में शामिल किया गया।

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के बारे में

- **भौगोलिक विस्तार:** महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
- **विविध और रणनीतिक अवस्थिति:** तटीय किले से लेकर पहाड़ी दुर्ग। ये सह्याद्री पर्वतमाला, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाट सहित विभिन्न भूभागों में स्थित हैं।
- **निर्माण:** 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच **छत्रपति शिवाजी महाराज से पेशवाओं तक, जो मराठा सामरिक दृष्टि और स्थापत्य कौशल** को दर्शाता है।

मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के किलें (12)	प्रमुख विशेषताएं
साल्हेर पहाड़ी किला	1672 में मराठों और मुगलों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध।
शिवनेरी पहाड़ी किला	छत्रपति शिवाजी का जन्मस्थान।
लोहगढ़ पहाड़ी किला	भज बौद्ध गुफाओं के नजदीक।
रायगढ़ पहाड़ी किला	शिवाजी की स्थायी राजधानी।
राजगढ़ पहाड़ी किला	**''हिंदवी स्वराज्य' का आधार; 1665 की पुरंदर संधि के बाद भी** मराठों के पास रहा।
जिंजी पहाड़ी किला (तमिलनाडु)	तीन पहाड़ी दुर्ग तथा मोटी दीवार का किला और खड़ी चट्टानें।
प्रतापगढ़ पहाड़ी वन किला	अफजल खान के साथ एक बड़ा युद्ध हुआ।
पन्हाला पठारी किला	ताराबाई के समय मराठा राज्य की राजधानी।
सिंधुदुर्ग द्वीपीय किला	अरब सागर में एक लघु द्वीप पर।
सुवर्णदुर्ग द्वीपीय किला	**बीजापुर के शासकों** द्वारा निर्मित।
खंडेरी द्वीपीय किला	1679 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मुरुद-जंजीरा दुर्ग में **सिद्दियों पर नियंत्रण** रखने के लिए।
विजयदुर्ग तटीय किला	इसे **"पूर्व का जिब्राल्टर"** कहा जाता है।

मराठा साम्राज्य के बारे में

- **स्थापना:** छत्रपति शिवाजी ने 1674 में की; दक्कन के राज्यों से स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण किया।
- **राजधानियां: रायगढ़ दुर्ग, जिंजी, सतारा** और **पुणे**।
- **शासन:** उत्तर में **पेशावर** से लेकर दक्षिण में **तंजावुर** तक।
- **प्रशासन:** '**अष्टप्रधान**' परिषद। इसमें आठ मंत्री थे: **पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाध्यक्ष**, और **पंडितराव**।
- **राजस्व नीति:**
  - **सरदेशमुखी:** संपूर्ण मराठा साम्राज्य के राजस्व पर लगाया गया 10% कर।
  - **चौथ:** पड़ोसी गैर-मराठा राज्यों से 1/4 हिस्सा वसूला जाता था।
- **पतन:** 1761 में **पानीपत के तृतीय युद्ध में** अहमद शाह अब्दाली से **पराजय** के बाद मराठा साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ।

निष्कर्ष

- भारत आज **44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों** और **62 अस्थायी सूची में शामिल स्थलों** के साथ अपनी समृद्ध विरासत संरक्षण क्षमता को प्रदर्शित करता है।

8.3. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज चैंपियनशिप {International Chess Federation (FIDE) Chess Championship}

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिव्या देशमुख जॉर्जिया के बाटुमी में भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर **FIDE महिला विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला** बनीं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली के बाद** ग्रैंडमास्टर बनने वाली दिव्या चौथी भारतीय महिला।
- दिव्या **कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026** के लिए क्वालीफाई हो गई।

भारतीय खिलाड़ियों द्वारा शतरंज में हाल में अर्जित की गई अन्य उपलब्धियां

- **2024** में, ग्रैंडमास्टर **गुकेश डोम्माराजू** सबसे कम उम्र (**18 वर्ष**) में विश्व शतरंज चैंपियन बने। उन्होंने डिंग लिरेन को हराया।
- भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने (2024) **45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड, बुडापेस्ट, हंगरी** में स्वर्ण पदक जीते।
- GM **प्रज्ञानानंद आर** (2023) विश्व कप फाइनल में पहुँचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने; विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय।
- अभिमन्यु मिश्रा (USA) 2019 में (10 वर्ष की आयु में) सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने और बाद में 2021 में उन्होंने जीएम (GM) नॉर्म्स हासिल किए।

FIDE विश्व चैंपियनशिप चक्र के बारे में

- **FIDE विश्व कप** से महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए तीन खिलाड़ी चुने जाते हैं।
- **कैंडिडेट्स टूर्नामेंट:** यह वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल से पहले की अंतिम प्रतियोगिता होती है।
- कैंडिडेट्स टूर्नामेंट: 8-खिलाड़ी **डबल राउंड-रॉबिन** प्रारूप में खेला जाता है; विजेता मौजूदा विश्व चैंपियन को चुनौती देता है।
- **क्वालीफाई करने के तरीकों में शामिल हैं:** पिछली विश्व चैम्पियनशिप का उपविजेता, विश्व कप के शीर्ष तीन फिनिशर, शीर्ष 2 ग्रैंड स्विस विजेता, FIDE सर्किट विजेता, और उच्चतम FIDE रेटिंग वाला खिलाड़ी।
- **विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच** पिछले विश्व चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच खेला जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के बारे में

- **अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं** की सर्वोच्च संस्था।
- **स्थापना: 1924, पेरिस**; IOC **मान्यता:** 1999
- **मुख्यालय:** लॉज़ेन (स्विट्ज़रलैंड)।
- **सदस्य: 201**

8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.4.1. कश्मीरी पश्मीना शॉल (Kashmiri Pashmina Shawl)

प्रधान मंत्री ने अपनी **घाना यात्रा** के दौरान, **हाथ से बनी कलाकृतियां जैसे- कश्मीरी पश्मीना शॉल** भेंट की।

कश्मीरी पश्मीना शॉल

- यह **चांगथांगी बकरी के मुलायम ऊन** से बुनी जाती है।
- यह अपनी **कोमलता और गर्माहट** के लिए मशहूर है।

अन्य हस्तशिल्प

- **बिदरीवेयर फूलदान (बीदर, कर्नाटक): जस्ते-तांबे से निर्मित, काले रंग की पॉलिश, चाँदी की महीन नक्काशी**। यह **सुंदरता, समृद्धि एवं सद्भाव** का प्रतीक हैं।
- **चाँदी का तारकशी पर्स (कटक, ओडिशा):** तारकशी कला से निर्मित, जटिल पुष्प और बेल-बूटे के डिज़ाइन आधुनिक शैली में।
- **मिनिएचर अंबावारी हाथी (पश्चिम बंगाल):पॉलिशदार कृत्रिम हाथी-दांत** से निर्मित, जो **प्राकृतिक हाथी-दांत का नैतिक विकल्प** है।

सूचीबद्ध सभी हस्तशिल्पों को, मिनिएचर अंबावरी हाथी को छोड़कर, सभी कलाओं को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है।

8.4.2. पिपरहवा अवशेष (Piprahwa Relics)

भगवान बुद्ध के पवित्र **पिपरहवा अवशेषों** की भारत वापसी हुई।

पिपरहवा अवशेषों के बारे में

- **खोज:** 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर **विलियम क्लैक्सटन पेप्पे** द्वारा **पिपरहवा, सिद्धार्थनगर (प्राचीन कपिलवस्तु), उत्तर प्रदेश** में।
- **महत्त्व:** भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेषों से जुड़े हैं।
- **मुख्य विशेषताएं:** इसमें **अस्थि अवशेष, सोपस्टोन और क्रिस्टल के ताबूत, बलुआ पत्थर का संदूक और स्वर्ण आभूषण** आदि शामिल हैं।
- **समयावधि:** लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व।
  - एक अस्थि-पेटी पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख अंकित है, जो बताता है कि ये अवशेष **शाक्य वंश द्वारा** रखे गए **बुद्ध के अवशेष** हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** भारतीय कानून के तहत इन्हें **'AA' श्रेणी की प्राचीन वस्तुएं** घोषित किया गया है, जिनका **निर्यात या बिक्री प्रतिबंधित** है।

9.1. सेलिब्रिटीज़ और उत्पादों का प्रचार (Celebrities and Endorsement of Products)

भूमिका

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई मशहूर हस्तियों पर **अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने, जुआ और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) कानूनों का उल्लंघन करने** का आरोप लगाया है। इनमें लोकप्रिय अभिनेता और टीवी होस्ट शामिल हैं।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

हितधारक	प्रमुख हित
मशहूर हस्तियां	➲ जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना, अन्यथा व्यक्तिगत विश्वसनीयता को जोखिम। ➲ आदर्श व्यक्तित्वों का नैतिक कर्तव्य उच्चतम नैतिक मानदंडों का पालन करना।
कंपनियां/ प्लेटफॉर्म	➲ **लाभ को अधिकतम करना** और बाजार में पहुंच को बढ़ाना। ➲ **कानून का पालन करना** और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना।
सरकारी एजेंसियां	➲ कानूनों को लागू करना, **उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना**, धन शोधन को रोकना। ➲ अवैध प्रचार पर अंकुश लगाकर **सार्वजनिक प्रणालियों में विश्वास बनाए रखना।**
समाज (विशेषकर युवा)	➲ मशहूर हस्तियों के प्रभाव में **सूचना पर आधारित निर्णय लेना।** ➲ **वित्तीय नुकसान, लत** या गैरकानूनी गतिविधि में भागीदारी की संभावना।

हानिकारक उत्पादों के प्रचार से संबंधित प्रमुख नैतिक मुद्दे

- **स्वायत्तता और सहमति:** भावनात्मक अपील जोखिमों को छुपाती है, जो **कांटियन नैतिकता** का उल्लंघन है; **ASCI प्रकटीकरण और सत्य दावों की आवश्यकता** करता है।
- **जवाबदेही और जिम्मेदारी: गांधीवादी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत** के अनुसार, प्रसिद्धि का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** भ्रामक प्रचार करने वालों को जवाबदेह ठहराता है।
- **परोपकार और गैर-हानिकारकता:** मशहूर हस्तियों का कर्तव्य **'अच्छा करना'** और **'कोई नुकसान नहीं पहुँचाना'** है। हानिकारक या अवैध उत्पादों को बढ़ावा देने से इन दोनों का उल्लंघन होता है।
- **रोल-मॉडल की सत्यनिष्ठा का क्षरण: सद्गुण नैतिकता** ईमानदारी पर बल देती है। भ्रामक विज्ञापनों की पुनरावृत्ति नैतिक अधिकार को कमजोर करती है।

हानिकारक उत्पादों के प्रचार को रोकने में प्रमुख चुनौतियां

- उच्च वित्तीय प्रलोभन नैतिकता पर हावी हो जाते हैं।
- मशहूर हस्तियां कंपनियों के दावों पर भरोसा कर लेते हैं इससे गलत सूचना का जोखिम।
- सेलिब्रिटी पूजा जवाबदेही में बाधा बनती है।
- तीव्र गति से उभरते क्षेत्र (क्रिप्टो, बेटिंग) नियमन से आगे निकल जाते हैं।
- नियामकों के पास व्यापक अनुमोदनों की निगरानी करने की क्षमता का अभाव है।

नैतिकतापूर्ण प्रचार अभियानों के लिए आगे की राह

- सेलिब्रिटी को आत्म-परीक्षण करना चाहिए, वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए, प्रमोशन का खुलासा करना चाहिए और जनकल्याणकारी कार्यों का समर्थन करना चाहिए।
- ब्रांड्स को सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- मजबूत फ्रेमवर्क: क्षेत्रवार नियम, अनिवार्य खुलासा, स्वनियामक परिषदें स्थापित करना।
- जागरूकता अभियान चलाकर आलोचनात्मक उपभोक्ता दृष्टिकोण विकसित करना।
- दंड से आगे बढ़कर सामूहिक नैतिक दायित्व निभाना।

निष्कर्ष

मशहूर हस्तियों के प्रचार-प्रसार में एक नैतिक भार होता है; प्रसिद्धि का उपयोग सार्वजनिक विश्वास के रूप में जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

10.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना {Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय मंजूर किया।

विशेषताएं

- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (**MoFPI**)।
- **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना**।
- **योजना अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक।
- **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2017 में **संपदा** नामक अम्ब्रेला योजना को मंजूरी दी। बाद में, कुछ घटकों को बंद करके इस योजना का नाम बदलकर **PMKSY** कर दिया गया।

उद्देश्य

- खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक आपूर्ति श्रृंखला के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए **आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण** करना।
- **किसानों को उनकी कृषि उपजों के बेहतर मूल्य प्रदान** करना।
- **कृषि उपज की बर्बादी को कम करना**, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना।

PMKSY के घटक

- **एकीकृत कोल्ड चेन:** खेत से उपभोक्ता तक कोल्ड चेन सुविधा; कंपनियाँ, सहकारी समितियाँ, SHGs, FPOs, NGOs, PSUs शामिल; फल और सब्जियों की कोल्ड चेन ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत।
- **एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर:** कम-से-कम 10 एकड़ भूमि में लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां।
- **फूड प्रोसेसिंग क्षमता:** मेगा फूड पार्क और APCs में इकाइयों का विस्तार/आधुनिकीकरण (PSUs, निजी कंपनियां, सहकारी समितियां आदि द्वारा)।
- **खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता:** परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन (HACCP, ISO 22000) के लिए सहायता।
- **मानव संसाधन व शोध:** 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 100 R&D परियोजनाएं स्वीकृत।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG):** 2018-19 के बजट में शुरू; प्रारंभ में टमाटर, प्याज, आलू (TOP) के लिए; दीर्घकाल में 22 फसलें शामिल, अल्पकाल में TOP से सभी फल-सब्जियां (TOP से TOTAL) तक विस्तार।
- **वित्तीय प्रबंधन**
  - **अंतर-योजना पुन: आवंटन:** मध्यावधि समीक्षा के बाद मंत्री 25% तक का पुन: आवंटन मंजूर कर सकते हैं।
  - **बचत का उपयोग:** प्रतिबद्ध देनदारियों से हुई बचत को नई परियोजनाओं में लगाया जाएगा।
- **जागरूकता:** अधिकतम हितधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार।

टॉपिक	मुख्य आंकड़े एवं तथ्य
डिजिटल उपनिवेशवाद	➲ डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए उठाए गए कदम ➲ **भारत:** ➜ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) ➜ **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002** ➜ ONDC (डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क) ➲ **वैश्विक:** डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स
ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन	➲ **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1965)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अश्लीलता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध के रूप में परिभाषित किया (अनुच्छेद 19)। ➲ **अश्लील सामग्री के विनियमन हेतु नियामक फ्रेमवर्क** ➜ IT अधिनियम 2000 ➜ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) द्वारा जारी IT अधिनियम, 2000 के अंतर्गत IT नियम 2021 ➜ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 294
राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025	➲ **विजन**: 'सहकार-से-समृद्धि' के माध्यम से सहकारी समितियों को **विकसित भारत 2047** के लिए प्रमुख चालक बनाना। ➲ **उद्देश्य**: 50 करोड़ नागरिकों को, जो या तो सदस्य नहीं हैं या सहकारी क्षेत्र में निष्क्रिय हैं, सक्रिय भागीदारी में लाना। ➲ **सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति:** 97वें संशोधन, 2011 ने सहकारी समितियों को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ संवैधानिक दर्जा दिया: ➜ **मौलिक अधिकार**: अनुच्छेद 19(1)(c) में "**सहकारी समितियां**" शब्द जोड़ा गया। ➜ **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत**: सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B शामिल किया गया। ➜ **नया भाग IXB:** सहकारी शासन के लिए अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए।
अंतर-राज्यीय जल विवाद	➲ विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी और संवैधानिक ढाँचा ➲ **अनुच्छेद 262**: यह अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है। ➲ **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956**: यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। ➲ **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956**: राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है।
मतदान के लिए आयु कम करना	**भारत में मतदान की आयु से संबंधित संवैधानिक प्रावधान** ➲ **अनुच्छेद 326** प्रत्येक ऐसे नागरिक के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। ➜ भारत ने **61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988** के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ➜ **मतदान का अधिकार** एक **सांविधिक अधिकार** है जिसे संसद के साधारण कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों को हटाना	➲ **अनुच्छेद 124(4)**: सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। ➲ **अनुच्छेद 124(5)**: संसद न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 द्वारा इस प्रक्रिया को विनियमित करती है। ➲ **अनुच्छेद 217(1)(b)**: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी तरह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है जैसे अनुच्छेद 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ➲ **अनुच्छेद 218**: यह अनुच्छेद 124 के खंड (4) और खंड (5) की प्रयोज्यता को उच्च न्यायालयों तक विस्तारित करता है।
भारत-यूनाइटेड किंगडम (UK) व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)	➲ **99% से अधिक टैरिफ लाइनें समाप्त**, जो भारत के लगभग पूरे व्यापार बास्केट को कवर करती हैं। ➲ भारत ने **89.5% टैरिफ लाइनों को खोला, जो UK के 91% निर्यात को कवर** करती हैं। ➲ UK भारतीय पेशेवरों और निवेशकों को **90 दिनों से लेकर 3 साल तक रहने की अनुमति** देता है। ➲ **संवेदनशील क्षेत्रकों** (डेयरी, अनाज, सोना, आभूषण, आदि) को संरक्षित किया गया है। ➲ निर्यातक **उत्पाद की उत्पत्ति का स्व-प्रमाणीकरण** कर सकते हैं।
भारत-मालदीव संबंध	➲ **भारत 1965 में स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता** देने वाले पहले देशों में से एक था। ➲ मालदीव पश्चिमी हिंद महासागर **(गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़) और पूर्वी हिंद महासागर (स्ट्रेट ऑफ मलक्का)** के बीच एक **'टोल गेट'** की तरह स्थित है। ➲ मालदीव को **4,850 करोड़ रुपये** का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और भारत-वित्तपोषित लाइन ऑफ क्रेडिट (LoCs) पर ऋण चुकौती को कम कर दिया गया है।
भारत-ब्राजील संबंध	➲ **द्विपक्षीय सहयोग:** 2006 से सामरिक साझेदारी। ➲ **वैश्विक सहयोग:** बहुपक्षीय मंचों (BRICS, BASIC, G-20, G-4, IBSA) और बहुपक्षीय निकायों (UN, WTO, UNESCO, WIPO) में सक्रिय रूप से संलग्न। ➲ **व्यापार:** 2024-25 में, द्विपक्षीय व्यापार 12.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारत व्यापार अधिशेष में था। ➲ **रक्षा सहयोग:** 2006 के समझौते ने संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की स्थापना की। ➲ **नवीकरणीय ऊर्जा:** ब्राजील ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की सह-स्थापना की और 2022 में ISA समझौते का अनुमोदन किया।
गिरमिटिया	**गिरमिटिया के बारे में** ➲ गिरमिटिया वे भारतीय **अनुबंधित श्रमिक** थे जो ब्रिटेन के **दासता उन्मूलन अधिनियम 1833** के कारण हुई श्रम की कमी को पूरा करने के लिए 19वीं शताब्दी में दूसरे देशों में चले गए थे। ➲ **"गिरमिट"** शब्दावली वास्तव में अंग्रेजी शब्द **"एग्रीमेंट"** का अपभ्रंश उच्चारण है। यह उस अनुबंध को इंगित करता है जिसके तहत इन श्रमिकों को भेजा गया था। ➲ **वितरण**: मॉरीशस, फिजी, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, और कैरेबियाई क्षेत्र (मुख्य रूप से त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, और जमैका)
कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP)	➲ **नोडल मंत्रालय**: विदेश मंत्रालय। ➲ **परियोजना विकास सलाहकार**: भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ➲ **परिवहन घटक**: ➜ **जलमार्ग**: म्यांमार में सितवे बंदरगाह से पलेत्वा तक कलादान नदी। ➲ **सड़क**: पलेत्वा से मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित जोरिनपुई तक।
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स	**ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में** ➲ यह **भारत के नेतृत्व** में गठित एक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सैनिकों के खिलाफ होने वाली **सभी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए जवाबदेही तय करने में मदद करना** है। ➲ यह समूह **'यूनाइटेड नेशन अलायन्स ऑफ सिविलाइजेशन' (UNAOC)** की एक प्रमुख शक्ति है और उसकी रणनीतिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लाल सागर	➲ यह उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक सीमांत सागर है। ➲ यह **बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर** से जुड़ता है। ➲ **सीमाएं**: मिस्र, सूडान, इरिट्रिया (पश्चिम में); इजराइल, जॉर्डन (उत्तर-पूर्व में अकाबा की खाड़ी के माध्यम से); सऊदी अरब, यमन (पूर्व में)।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025	➲ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 (2024 में) से सुधरकर **77 (2025 में)** हो गई है।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)	➲ **क्रियान्वयन और निगरानी**: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित और राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षण निकाय, राज्य-स्तरीय नोडल समितियों और जिला धन-धान्य समितियों की तीन-स्तरीय संरचना के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसकी समीक्षा नीति आयोग द्वारा की जाती है। ➲ **संतृप्ति-आधारित अभिसरण**: यह केंद्र और राज्य की योजनाओं और स्थानीय साझेदारियों को समेकित करता है। ➲ **प्रगति ट्रैकिंग:** 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) का उपयोग करके प्रगति को ट्रैक किया जाता है।
भारत में सार्वजनिक ऋण	➲ **सार्वजनिक ऋण** को 'राष्ट्रीय ऋण' भी कहते हैं। यह **सरकार** तथा **सार्वजनिक क्षेत्रक की अन्य संस्थाओं** द्वारा निजी क्षेत्र और विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण की कुल संचित राशि है। ➲ कुल 18,174,284 करोड़ रुपये के सार्वजनिक ऋण में से **आंतरिक ऋण 96.59%** है और **बाह्य ऋण 3.41%** है।
भारत में वित्तीय समावेशन	➲ **FI-इंडेक्स** देश भर में वित्तीय समावेशन को मापता है। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल है। ➲ इस सूचकांक में तीन उप-सूचकांक शामिल हैं: **पहुँच (Access), उपयोग (Usage)** और **गुणवत्ता (Quality)**।
डिजिटल इंडिया मिशन	➲ **क्रियान्वयन**: यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ➲ **लक्ष्य**: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) के माध्यम से एक **डिजिटल रूप से सशक्त समाज** और **ज्ञान अर्थव्यवस्था** का निर्माण करना। इसका दृष्टिकोण तीन क्षेत्रों- **डिजिटल अवसंरचना**, **मांग पर शासन**, और **डिजिटल सशक्तिकरण पर केन्द्रित है**। इन्हें नौ स्तंभों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिनमें **ब्रॉडबैंड हाईवे, ई-क्रांति, नौकरियों के लिए IT, और ई-शासन** शामिल हैं।
स्टेबलकॉइन्स	➲ स्टेबलकॉइन **एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी** है जिसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, कमोडिटी या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए- **टेथर (USDT),** जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होती है।
क्रॉपिक (CROPIC) पहल	➲ यह **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लिकेशन है। इसका उद्देश्य फसल चक्र के दौरान **जियोटैग किए गए** फसल के फोटो लेना है।
OECD-FAO ने एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034 जारी किया	➲ **जारीकर्ता**: **OECD और FAO द्वारा।** ➲ **विवरण**: यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कृषि जिंसों और बाजारों के लिए अगले दस वर्षों की संभावनाओं का एक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)	➲ **GCCs** को ग्लोबल इन-हाउस सेंटर्स (GICs) के रूप में भी जाना जाता है। ➜ **GCCs वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र** होते हैं जो अपनी मूल कंपनी को IT**, अनुसंधान और विकास और ग्राहक सहायता** जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। ➲ **भारत में जिम्मेदार कारक**: भारत लागत दक्षता, नीतिगत समर्थन, प्रतिभा की उपलब्धता और एक बड़े उपभोक्ता आधार के कारण उन्हें आकर्षित करता है।
एल्युमीनियम और कॉपर	➲ **एल्युमीनियम/बॉक्साइट**: भारत के भंडार मुख्य रूप से ओडिशा (41%), छत्तीसगढ़, आंध्र में हैं; ओडिशा उत्पादन में सबसे आगे (73%) है। वैश्विक स्तर पर, चीन (58%) शीर्ष उत्पादक है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत हैं। ➲ **कॉपर (तांबा)**: भारत के भंडार- राजस्थान (52%), मध्य प्रदेश, झारखंड में हैं; उत्पादन का नेतृत्व मध्य प्रदेश (57%) और राजस्थान (43%) करते हैं। वैश्विक स्तर पर, चिली (19% भंडार) सबसे आगे है, जिसके बाद पेरू और ऑस्ट्रेलिया हैं।
ऑपरेशन- मेड मैक्स	➲ यह अवैध फार्मा व्यापार पर रोकथाम लगाने के लिए **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** का एक ऑपरेशन है।
प्रलय मिसाइल	➲ यह एक **सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी** की ठोस प्रणोदक वाली अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है जो **हाइपरसोनिक गति (मैक 5 से ऊपर)** से उड़ान भर सकती है। इसकी रेंज **150 से 500 किमी** है।
भारत NCX	➲ यह एक **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास** है। ➲ यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU), गांधीनगर, गुजरात के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
जा माता	➲ यह **जापान और भारत के तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त समुद्री** अभ्यास है।
अर्बन रेसिलिएंस	➲ यह किसी आपदा की स्थिति में **वांछित कार्यों को बनाए रखने या तेजी से वापस लाने, परिवर्तन के अनुकूल होने, तथा सीमित प्रणालियों को शीघ्रता से रूपांतरित करने** की शहरी प्रणाली की क्षमता को संदर्भित करता है।
एथेनॉल सम्मिश्रण	➲ **एथेनॉल**: एक नवीकरणीय ईंधन (C_2H_5OH) जिसका उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किण्वन या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। ➲ **प्रकार:** ➜ **प्रथम पीढ़ी**: खाद्य फसलों से। ➜ **द्वितीय पीढ़ी**: लिग्नो-सेलुलोसिक बायोमास से। ➜ **तृतीय पीढ़ी**: जलीय बायोमास जैसे शैवाल। ➜ **चतुर्थ पीढ़ी**: इंजीनियर्ड पौधों से।

वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH)	यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह **संरक्षित क्षेत्रों**, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव संरक्षण, और **22 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों** (जैसे हिम तेंदुआ, एशियाई शेर) के लिए रिकवरी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ➲ **घड़ियाल**: क्रिटिकली एनडेंजर्ड (IUCN रेड लिस्ट)। वयस्क नर के थूथन के सिरे पर एक बल्ब जैसी संरचना होती है, जिसे "घड़ा (GHARA)" कहा जाता है। ➲ **स्लॉथ बीयर**: वल्नरेबल (IUCN रेड लिस्ट)। यह भारत, नेपाल और श्रीलंका का स्थानिक है। यह विशेष रूप से दीमक और चींटियों को खाता है और हाइबरनेट **में नहीं जाता**। कर्नाटक में स्थित **दरोजी स्लॉथ बीयर अभयारण्य** एशिया का पहला समर्पित अभयारण्य है।
वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)	➲ यह 1975 में हुआ एक **स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है। ➲ इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले। इसे एक लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। ➲ भारत ने **इसे 1976 में अनुमोदित** किया था। ➲ **प्रमुख पहल**: MIKE कार्यक्रम, **वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ** (ICCWC)।
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर	➲ यह प्रशांत महासागर बेसिन की परिधि में घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ वैश्विक स्तर पर लगभग **75% सक्रिय ज्वालामुखी** और **90% भूकंप** आते हैं।
सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट (SDGR) 2025 और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025	➲ **SDGR**: 2030 एजेंडा पर वैश्विक प्रगति की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्ट। यह चरम गरीबी में 8.9% आबादी, 11 में से 1 व्यक्ति के भूख का सामना करने, और 1.12 अरब लोगों के झुग्गी-झोपड़ियों में रहने जैसी चुनौतियों को उजागर करती है। **2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष** था। ➲ **NIF**: इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी के लिए शुरू किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के 5 वर्ष	➲ इसका मसौदा **कस्तूरीरंगन समिति** की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। ➲ **प्रमुख योजनाएं/ पहलें:** ➜ **पीएम श्री (PM SHRI)**: 14,500 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प। ➜ **निपुण भारत**: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। ➜ **एक राष्ट्र एक सदस्यता**। ➜ **उल्लास/ नव भारत साक्षरता कार्यक्रम**: वयस्क साक्षरता के लिए। ➜ **विद्यांजलि**: एक स्कूल स्वयंसेवक कार्यक्रम।
सामाजिक विलगाव	➲ **सामाजिक जुड़ाव**: दूसरों से संबंधित होना और उनके साथ बातचीत करना। ➲ **सामाजिक विलगाव**: अपर्याप्त सामाजिक संपर्क, तनावपूर्ण रिश्ते। ➲ **इसके रूप:** ➜ **अकेलापन**: वांछित और वास्तविक जुड़ाव में विसंगति। ➜ **सामाजिक विलगाव**: कम रिश्ते और सीमित संपर्क।
बाल दत्तक ग्रहण	➲ यह **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956** और **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** द्वारा शासित होता है। ➲ **नोडल एजेंसी**: **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)**: इसकी स्थापना JJ अधिनियम के तहत की गई है। यह घरेलू और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को नियंत्रित करता है। यह **बच्चों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993)** का पालन करता है।
काशी घोषणा-पत्र	➲ यह **नशा मुक्ति आंदोलन** के लिए 5 साल का रोडमैप निर्धारित करती है।
तलाश (TALASH) पहल	➲ **इसे** जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसायटी (NESTS)** ने **यूनिसेफ इंडिया** के साथ साझेदारी में इसे लॉन्च किया। ➲ **उद्देश्य**: यह एक **राष्ट्रीय कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को समर्थन देना है।
नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह	➲ यह **इसरो** और **नासा** का संयुक्त मिशन है। इसे सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
ब्लैक होल विलय	➲ इसका पता **LVK** वेधशालाओं के नेटवर्क (LIGO, Virgo, और KAGRA) ने लगाया गया। ➲ **गुरुत्वाकर्षण तरंगें**: अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा अनुमानित स्पेस-टाइम में 'रिपल्स'। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग	➲ यह **एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी (मल्टी-हॉप नेटवर्क)** है जहाँ एक रेंज में डिवाइस ब्लूटूथ क्लस्टर बनाते हैं। इससे डेटा किसी भी डिवाइस से अन्य सभी तक जा सकता है। संदेशों का प्रसारण नोड्स द्वारा होता है।

AI एलायंस नेटवर्क (AIANET)	➲ यह एक **अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क** है। इसका उद्देश्य समृद्धि और विकास के लिए AI प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती को गति देना है। ➲ **सदस्य**: भारत सहित 17 देश। ➲ **प्रशासक**: AI एलायंस रूस द्वारा प्रशासित।
WHO ने "3 बाय 35" पहल शुरू की	➲ इसका उद्देश्य 2035 तक स्वास्थ्य करों के माध्यम से **तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों को कम से कम 50% तक** बढ़ाना है।
फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक	➲ यह भारत का अपना **लोंगिट्युडिनल हेल्थ डेटाबेस** बना रहा है। इससे **प्रेसिजन मेडिसिन और बायोमेडिकल अनुसंधान** को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रारंभिक निदान, चिकित्सीय लक्ष्यीकरण और जटिल बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा।
चोल गंगम झील	➲ इसे **पोन्नेरी झील** के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीन मानव निर्मित झील है। ➲ इसका निर्माण **राजेंद्र चोल प्रथम (1014 से 1044 ई.)** ने गंगईकोंडा चोलपुरम में करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर **गंगईकोंडा चोल** की उपाधि धारण की थी। यह झील उनकी विजय का प्रतीक है। इसमें गंगा के पवित्र जल डाला गया था।
मराठा मिलिट्री लैंडस्केप	➲ **प्रमुख किले (12)**: इनमें **साल्हेर** (मराठा-मुगल युद्ध), **शिवनेरी** (शिवाजी का जन्मस्थान), **रायगढ़** (शिवाजी की स्थायी राजधानी), **राजगढ़** ('हिंद स्वराज' का पहला राजनीतिक आधार), और जिंजी हिल फोर्ट (तमिलनाडु) शामिल हैं। विजयदुर्ग को "पूर्वी जिब्राल्टर" कहा जाता था। ➲ **मराठा साम्राज्य**: इसकी स्थापना **छत्रपति शिवाजी** ने 1674 में की थी। यह 'अष्टप्रधान' प्रशासन और राजस्व नीतियों जैसे **सरदेशमुखी** (राज्य के राजस्व पर 10% कर) और **चौथ** (पड़ोसी प्रमुखों से राजस्व का 1/4वां हिस्सा) के लिए जाना जाता है। ➲ **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (WHS)**: अब भारत में 44 WHS (36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित) हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर 6th और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2nd स्थान पर रखता है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज चैम्पियनशिप	➲ **दिव्या देशमुख** FIDE महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला और चौथी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर बन गई हैं।
कश्मीरी पश्मीना शॉल	➲ इसे लद्दाख में पाई जाने वाली **चांगथंगी बकरी** के महीन अंडरकोट से बुना जाता है। ➲ यह अपनी कोमलता और गर्माहट के लिए प्रसिद्ध है। इसे **भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त** है।

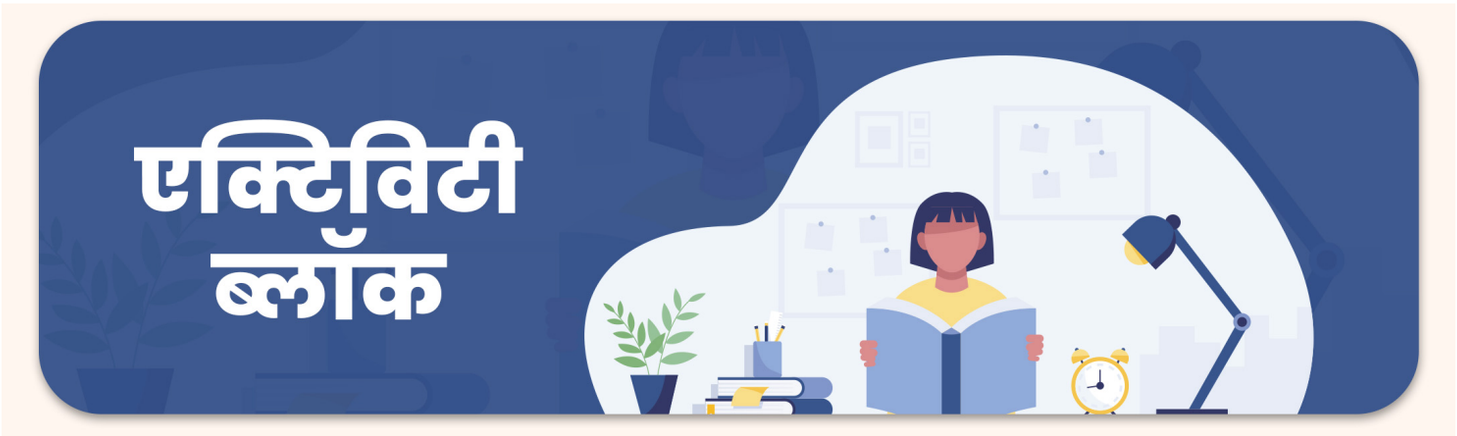

12.1. MCQS

1. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?

(a) 42वां संशोधन, 1976

(b) 61वां संशोधन, 1988

(c) 73वां संशोधन, 1992

(d) 97वां संशोधन, 2011

2. कौन सा निकाय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए धन के वितरण की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करता है?

(a) वित्त आयोग

(b) पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)

(c) नीति आयोग

(d) राज्य वित्त आयोग

3. भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा करने का अधिकार देता है।
2. सुप्रीम कोर्ट अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित मूल विवादों का निर्णय सीधे कर सकता है।
3. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

4. भारत में सहकारिता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए:

1. इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B के तहत जोड़ा गया।
2. संविधान का भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) सहकारी समितियों से संबंधित है।
3. बहु-राज्य सहकारी समितियां संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

5. चीन द्वारा निर्मित मेडोग जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?

(a) इरावदी

(b) मेकांग

(c) यारलुंग त्सांगपो

(d) सिंधु

6. गीलोंग ट्रीटी निम्नलिखित से संबंधित है:

(a) ब्रिक्स आर्थिक सहयोग

(b) AUKUS सबमरीन पार्टनरशिप

(c) मर्कोसुर व्यापार उदारीकरण

(d) इंडो-पैसिफिक क्वाड फ्रेमवर्क

7. ऐतिहासिक रूप से "गिरमिटिया" शब्द का अर्थ है:

(a) औपनिवेशिक छात्रवृत्ति पर विदेश में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्र

(b) औपनिवेशिक अनुबंधों के तहत अनुबंधित भारतीय श्रमिक

(c) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना के लिए भर्ती किए गए श्रमिक

(d) पूर्वी अफ्रीका में प्रवासी व्यापारी

8. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMTTP) भारत के पूर्वोत्तर को किस देश से जोड़ता है?

(a) बांग्लादेश

(b) भूटान

(c) म्यांमार

(d) थाईलैंड

9. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी।
2. नीति आयोग फसल उत्पादकता और ऋण तक पहुँच जैसे मानदंडों के आधार पर योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए 100 जिलों को अंतिम रूप देगा।
3. यह योजना केवल अनुदान और सब्सिडी प्रदान करती है और लोन या ऋण सहायता को इसमें शामिल नहीं करती है।
4. इस योजना के एक भाग के रूप में किसानों को विदेश में प्रशिक्षण के अवसर भी शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1, 3 और 4

10. रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी जिनकी मासिक आय ₹1,00,000 तक है और जो EPFO में पंजीकृत हैं, वे लाभ के पात्र हैं।
3. विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता अन्य क्षेत्रों की तुलना में लंबी अवधि के लिए प्रोत्साहन के पात्र हैं।
4. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन केवल एकमुश्त अनुदान के रूप में दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

11. भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत भारत में IPR के सभी रूपों का प्रबंधन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM) द्वारा किया जाता है।
2. भारत ने हाल ही में लोकार्नो वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया है, जो डिजाइनों के वर्गीकरण से संबंधित है।
3. भौगोलिक संकेत (GI) कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत पंजीकृत हैं।
4. 2023 तक पेटेंट दाखिल करने में भारत वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर पहुँच गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

12. प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रोजेक्ट 17A, वर्तमान में सेवा में मौजूद प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक श्रेणी) फ्रिगेट का अगला चरण है।
2. प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट मुख्य रूप से केवल पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
3. ये फ्रिगेट उन्नत स्टील्थ सुविधाओं और अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

13. एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय नौसेना के जहाजों से प्रक्षेपित करने के लिए विकसित एक स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट है।
2. ERASR में एक द्विन-रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन और स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग किया जाता है।
3. यह मुख्य रूप से सुपरसोनिक विमानों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

14. DRDO और IAF द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई अस्त्र मिसाइल महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. यह भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) है।
2. इसकी मारक क्षमता 100 किमी से अधिक है।
3. यह सभी मौसमों, दिन और रात की परिस्थितियों में अत्यधिक युद्धाभ्यास करने वाले सुपरसोनिक विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

15. अर्बन रेसिलिएंस की दिशा में भारत के प्रयासों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत की शहरी आबादी 2070 तक 1.1 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, और 2030 तक 70% से अधिक नई नौकरियां शहरों में ही पैदा होने की उम्मीद है।
2. प्लुवियल (वर्षा जनित बाढ़) का जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे 2030 तक वार्षिक नुकसान 5 अरब डॉलर होने का अनुमान है।
3. शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कुल निवेश का 50% से अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

16. भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
2. 2022 में संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) ने 20% मिश्रण लक्ष्य को 2030 से पहले यानी 2025-26 कर दिया है।
3. पहली पीढ़ी का एथेनॉल मुख्य रूप से लिग्नो-सेल्यूलोसिक बायोमास या कृषि अवशेषों से बनाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है।
2. नीति का उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, और कम से कम कक्षा 5 तक (अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक) शिक्षण का माध्यम स्थानीय भाषाओं में रखने की सिफारिश की गई है।
3. एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC) उच्च शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, जो एकेडमिक क्रेडिट के डिजिटल भंडारण की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

18. हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल विलय GW231123 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें दो ब्लैक होल का विलय हुआ, एक सूर्य से 140 गुना और दूसरा 100 गुना अधिक विशाल।
2. यह खोज LVK वेधशालाओं के नेटवर्क द्वारा की गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO और जापान में KAGRA शामिल हैं।
3. यह घटना ब्लैक होल के अत्यधिक विशाल और तीव्र गति से घूमने की प्रकृति के कारण ब्लैक होल निर्माण की वर्तमान समझ को चुनौती देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

19. हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।
2. तमिलनाडु में स्थित जिंजी हिल किला इस पदनाम में शामिल स्थलों में से एक है।
3. छत्रपति शिवाजी द्वारा अपनी स्थायी राजधानी के लिए चुना गया रायगढ़ हिल किला, इस लैंडस्केप का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

20. पिपरहवा अवशेषों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में खोजे गए थे और भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेषों से जुड़े हैं।
2. एक मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि का शिलालेख उन्हें मौर्य वंश द्वारा संग्रहित बुद्ध अवशेष होने की पुष्टि करता है।
3. भारतीय कानून के तहत, इन अवशेषों को 'AA' श्रेणी की प्राचीन वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इन्हें हटाने या बेचने पर रोक लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements)

1. 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। (T/F)
2. भारत में मतदान का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। (T/F)
3. सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक (NSCSTI) 2.0 ढांचा, मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। (T/F)
4. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) रोम संविधि के तहत स्थापित हुआ, जो 2002 से प्रभावी है। (T/F)
5. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर है, और 59 देशों में वीज़ा-फ्री यात्रा की अनुमति है। (T/F)
6. लाल सागर (Red Sea) को आस-पास की नदियों से बड़ी मात्रा में मीठा पानी प्राप्त होता है। (T/F)
7. डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) को RBI द्वारा अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है ताकि डिजिटल अपनाने (adoption) को ट्रैक किया जा सके। (T/F)
8. वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) 2012 से 5 क्षेत्रों- मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और इक्विटी बाजार– के आधार पर वित्तीय स्थिति की सापेक्षिक कठोरता/सहजता को मापता है। (T/F)
9. ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। (T/F)
10. टैलिसमैन सेबर अभ्यास फ्रांस, जर्मनी, भारत और अन्य देशों के बीच एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। (T/F)
11. भारत के बड़े शहरों में अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव के कारण रात का तापमान पास के ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार 1–2°C कम रहता है। (T/F)
12. पहली पीढ़ी का एथेनॉल शैवाल (algae) जैसी जलीय बायोमास से प्राप्त किया जाता है। (T/F)
13. घड़ियाल एकमात्र ऐसा मगरमच्छ है जिसमें नर-मादा के बीच स्पष्ट शारीरिक भिन्नता (sexual dimorphism) दिखाई देती है। (T/F)
14. CITES सचिवालय IUCN द्वारा प्रशासित है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। (T/F)
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 कोठारी आयोग की सिफारिशों पर तैयार की गई थी। (T/F)
16. WHO रिपोर्ट के अनुसार, युवा वर्ग (13–29 आयु समूह) वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अकेलापन महसूस करता है। (T/F)
17. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA), हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया है। (T/F)
18. निसार (NISAR) विश्व का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसमें L-बैंड और S-बैंड SAR को एक ही प्लेटफार्म पर जोड़ा गया है। (T/F)
19. चोल गंगम झील, जिसे पोननेरी झील भी कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन मानव-निर्मित झील है। (T/F)
20. मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, जिसे अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, केवल महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। (T/F)

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)

1. डिजिटल उपनिवेशवाद भारत की संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। हाल ही में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
2. मतदान की आयु कम करने से लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, लेकिन परिपक्वता और संचालन संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
3. द्विपक्षीय संबंधों को नया रूप देने में भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
4. चीन की मेडोग जलविद्युत परियोजना से भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
5. भारत का बढ़ता सार्वजनिक ऋण राजकोषीय स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समता के लिए एक चुनौती है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
6. हाल ही में स्वीकृत RDI योजना को भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। भारत में अनुसंधान एवं विकास की चुनौतियों का समाधान करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। अनुसंधान और नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। (10 अंक, 150 शब्द)
7. भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इस वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय और शासन संबंधी गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं जो अर्बन रेसिलिएंस के लिए एक खतरा हैं। इन्हें आपदा रोधी बनाने में भारतीय शहरों के सामने आने वाली प्रमुख कमजोरियों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और उनके समाधान के लिए प्रस्तावित सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
8. भारत में सटीक चिकित्सा और जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने में फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक के उद्देश्यों और महत्व का परीक्षण कीजिए। यह पहल जटिल बीमारियों से निपटने के लिए डेटा का लाभ कैसे उठाती है? (10 अंक, 150 शब्द)
9. भारत में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
10. ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है? इसके संभावित महत्व पर भी प्रकाश डालिए। (10 अंक, 150 शब्द)
11. जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज वित्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
12. भारत में अंतर्राज्यीय जल विवादों (ISWD) के समाधान में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
13. ऐतिहासिक संबंधों और बढ़ते जुड़ाव के बावजूद, भारत की अफ्रीका नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों की पहचान कीजिए और भारत-अफ्रीका साझेदारी को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

14. IT क्षेत्र में हाल ही में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी ने फ्यूचर ऑफ वर्क से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों को उजागर किया है। फ्यूचर ऑफ वर्क को आकार देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए और इन परिवर्तनों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने में सरकारी पहलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
15. क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा के लिए एक अस्तित्वगत खतरा और एक परिवर्तनकारी अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। मौजूदा डिजिटल अवसंरचना के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न प्रमुख जोखिमों पर चर्चा कीजिए और भारत की तैयारियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
16. एथेनॉल मिश्रण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। एथेनॉल मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इन बाधाओं को दूर करने के लिए की गई पहलों पर भी चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलना है। स्कूली और उच्च शिक्षा में NEP 2020 की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए और इसके कार्यान्वयन में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
18. NISAR (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार) उपग्रह मिशन के बहुआयामी महत्व पर चर्चा कीजिए, इसकी प्रमुख तकनीकी विशेषताओं और सतत विकास एवं आपदा प्रबंधन हेतु पृथ्वी अवलोकन में संभावित अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)
19. हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत की विरासत के एक अनूठे पहलू को उजागर करता है। इन लैंडस्केप्स में निहित स्थापत्य कला की कुशलता और रणनीतिक दृष्टि पर चर्चा कीजिए, और यह भी बताइए कि ये किस प्रकार मराठा साम्राज्य के सैन्य कौशल और अनुकूलनशील रणनीतियों को दर्शाते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
20. चोल गंगम झील और महान समकालीन चोल मंदिर शाही चोल राजवंश की स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक उपलब्धियों के गहन प्रमाण हैं। चोलों की विशेष रूप से जल प्रबंधन, धार्मिक परंपराओं और समुद्री शक्ति में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी बहुआयामी विरासत का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Study)

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के बढ़ते उपयोग के साथ, अवैध या हानिकारक उत्पादों का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी लगातार बढ़ती आलोचना का सामना कर रहे हैं। भारतीय क़ानून जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, ASCI दिशा-निर्देश, और उपभोक्ता मामले विभाग के हाल के निर्देश इन विज्ञापनों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी की कमी के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- नैतिक विज्ञापन और प्रचार को बढ़ावा देने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं?
- डिजिटल युग में सार्वजनिक हस्तियों के आचरण को बेहतर बनाने में सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा करें।
- एक ठोस रणनीति प्रस्तुत कीजिए जिसमें कानूनी सुधार, जवाबदेही तंत्र और जन-जागरूकता अभियान शामिल हों, ताकि अनैतिक सेलिब्रिटी विज्ञापनों - विशेषकर ऑनलाइन सट्टेबाजी और इसी तरह के हानिकारक उत्पादों - पर रोक लगाई जा सके।

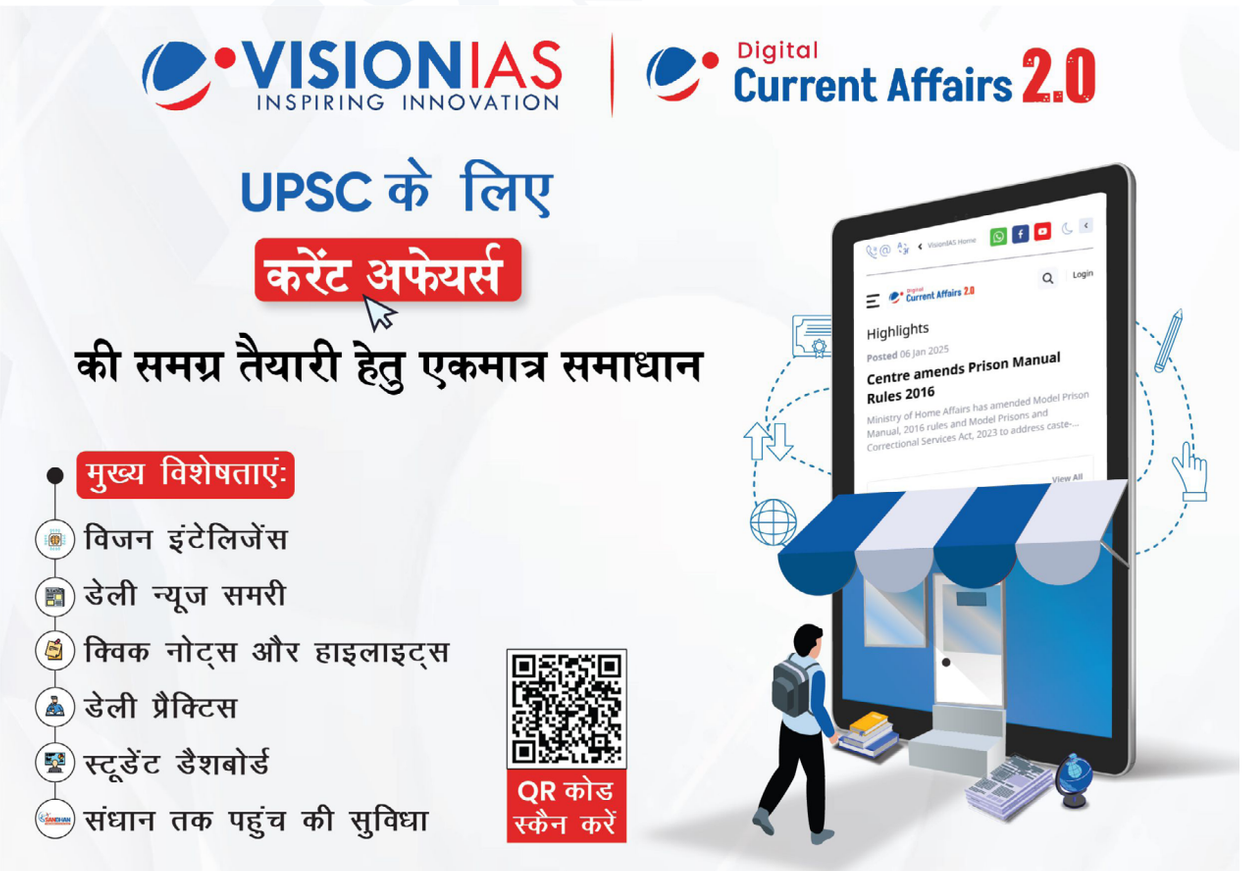

13.1. MCQ के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explantion)

1. उत्तर: B

व्याख्या:

- **61वें संशोधन 1988** द्वारा मतदान करने की आयु **21 से घटाकर 18 वर्ष** कर दी गई।

2. उत्तर: B

व्याख्या:

रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशें

- **पर्याप्त हस्तांतरण:** राज्यों को समयबद्ध हस्तांतरण रोडमैप बनाना होगा; स्थानीय कर्मचारियों (जैसे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता) पर नियंत्रण हस्तांतरित करना होगा।
  - **पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)** 3Fs पर प्रगति को मापने वाली **"हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट" तैयार करेगा।**

3. उत्तर: C

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** अनुच्छेद 262 वास्तव में संसद को अंतर-राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने की शक्ति देता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** सर्वोच्च न्यायालय मूल विवाद पर सीधे निर्णय नहीं दे सकता; वह केवल न्यायाधिकरण के निर्णयों की व्याख्या कर सकता है।
- **कथन 3 सही है:** अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

4. उत्तर: A

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को DPSP के रूप में बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा।
- **कथन 2 सही है:** इसने सहकारी गवर्नेंस के लिए भाग IXB (अनुच्छेद 243ZH-243ZT) भी जोड़ा।
- **कथन 3 सही नहीं है:** बहु-राज्य सहकारी समितियां संघ सूची में शामिल हैं, राज्य सूची में नहीं।

5. उत्तर: C

व्याख्या:

- तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी के विशाल मोड़ (ग्रेट बेंड) पर अवस्थित है

6. उत्तर: B

व्याख्या:

- AUKUS स्तंभ I के अंतर्गत गीलोंग ट्रीटी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों से संबंधित है

7. उत्तर: B

व्याख्या:

- गिरमिटिया अनुबंधित श्रमिक थे जो ब्रिटिश दासता उन्मूलन अधिनियम 1833 के बाद प्रवास कर गए थे

8. उत्तर: C

व्याख्या:

- यह पूर्वी भारतीय बंदरगाहों को म्यांमार और फिर मिज़ोरम से जोड़ता है

9. उत्तर: (b) केवल 1, 2 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** PMDDKY का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसकी निगरानी त्रि-स्तरीय संरचना (राष्ट्रीय, राज्य, जिला) के माध्यम से की जाती है।
- **कथन 2 सही है:** नीति आयोग कम फसल उत्पादकता, सामान्य फसल सघनता, ऋण पहुँच और भौगोलिक प्रतिनिधित्व जैसे मानदंडों के आधार पर 100 जिलों का चयन करता है।
- **कथन 3 गलत है:** यह योजना केवल अनुदान ही नहीं, बल्कि सब्सिडी और ऋण (जैसे, किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड सहायता के माध्यम से) दोनों प्रदान करती है।
- **कथन 4 सही है:** इसमें इज़राइल, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों में 500 किसानों के लिए विदेशी प्रशिक्षण शामिल है।

10. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** इसका नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, न कि MSDE।
- **कथन 2 सही है:** ₹1,00,000 प्रति माह तक वेतन वाले और ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इसके पात्र हैं। उन्हें दो किश्तों में एक महीने का EPF वेतन (अधिकतम ₹15,000) मिलता है।
- **कथन 3 सही है:** विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को अन्य की तुलना में अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है।
- **कथन 4 गलत है:** नियोक्ता प्रोत्साहन मासिक वित्तीय सहायता (₹1,000-₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह) है, न कि एकमुश्त अनुदान।

11. उत्तर: (c) केवल 1, 2 और 4

व्याख्या:

- **कथन 1 - सही:** भारत में सभी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रपत्र (पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कॉपीराइट, GI, सेमीकंडक्टर लेआउट, पादप किस्में, व्यापार रहस्य) DPIIT के अंतर्गत CGPDTM द्वारा प्रशासित किए जाते हैं।
- **कथन 2 - सही:** भारत ने लोकार्नो वर्गीकरण को अपनाया, जो औद्योगिक डिज़ाइनों को वर्गीकृत करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है।
- **कथन 3 - गलत:** भौगोलिक संकेत (GI) वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होते हैं, न कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा।
- **कथन 4 - सही:** वैश्विक पेटेंट दाखिलों में भारत 2020 में 9वें स्थान से बढ़कर 2023 में 6वें स्थान पर पहुँच गया।

12. उत्तर: (b) केवल 1 और 3

व्याख्या:

- प्रोजेक्ट 17A वास्तव में प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक क्लास) फ्रिगेट का अनुवर्ती है (कथन 1 सही है)।
- ये फ्रिगेट बहु-भूमिका वाला युद्धपोत होते हैं, न कि केवल पनडुब्बी रोधी (कथन 2 गलत)।
- इनमें बेहतर स्टील्थ विशेषताएं और अत्याधुनिक हथियार/सेंसर होते हैं (कथन 3 सही है)।

13. उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या:

- ERASR जहाजों से प्रक्षेपित किया जाने वाला एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है (कथन 1 सही है)।
- यह द्विन-रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज़ का उपयोग करता है (कथन 2 सही है)।
- इसे पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि सुपरसोनिक विमानों को (कथन 3 गलत है)।

14. उत्तर: (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- अस्त्र वास्तव में भारत का पहला स्वदेशी BVRAAM है (कथन 1 सही है)।
- इसकी मारक क्षमता 100 किमी से अधिक है (कथन 2 सही है)।
- यह सभी मौसमों में, दिन और रात में, सुपरसोनिक, अत्यधिक गतिशील विमानों से मुकाबला कर सकता है (कथन 3 सही है)।

15. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** भारत की शहरी आबादी 2020 में 480 मिलियन से लगभग दोगुनी होकर 2050 तक 951 मिलियन और 2070 तक 1.1 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। 2030 तक भारत में लगभग 70% से ज़्यादा नई नौकरियां शहरों में ही पैदा होने की उम्मीद है।
- **कथन 2 सही है:** प्लुवियल (वर्षा जनित बाढ़) का जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है, वर्तमान में वर्षा जल बाढ़ से होने वाला वार्षिक नुकसान 4 अरब डॉलर अनुमानित है, जो 2030 तक बढ़कर 5 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- **कथन 3 गलत है:** शहरी अवसंरचना में निजी क्षेत्रक का योगदान केवल 5% है, जबकि उनके पास परियोजना संबंधी नियोजन और दक्षता काफी अधिक है।

16. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 2025 तक भारत द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की।
- **कथन 2 सही है:** 2022 में संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (2018) ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से पहले यानी 2025-26 कर दिया है।
- **कथन 3 गलत है:** पहली पीढ़ी का एथेनॉल खाद्य फसलों जैसे अनाज, गन्ना, चुकंदर आदि से बनाया जाता है। दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल लिग्नो-सेल्यूलोसिक या वुडी बायोमास या कृषि अवशेषों से बनाया जाता है।

17. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** NEP 2020 स्वतंत्रता के बाद देश की तीसरी शिक्षा नीति है (पहली दो 1968 और 1986 में थीं, जिन्हें 1992 में संशोधित किया गया था)।
- **कथन 2 सही है:** बहुभाषावाद एक प्रमुख फोकस है, जिसमें कम से कम ग्रेड 5 (अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे) तक स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का माध्यम अनुशंसित है।
- **कथन 3 सही है:** एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) उच्च शिक्षा में एक प्रमुख विशेषता है, जिसे विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

18. उत्तर: (d)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है:** दो ब्लैक होल के आपस में विलय होने से एक ऐसे ब्लैक होल का निर्माण हुआ जिसका आकार सूर्य से लगभग 225 गुना बड़ा होने का अनुमान है। जिनमें से एक सूर्य से 140 गुना अधिक विशाल और दूसरा 100 गुना बड़ा था,

- **कथन 2 सही है:** इस घटना से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता LVK वेधशालाओं के नेटवर्क द्वारा लगाया गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO डिटेक्टर, इटली में VIRGO और जापान में KAGRA शामिल थे।
- **कथन 3 सही है:** यह विलय अब तक की सभी पूर्व खोजों से अधिक द्रव्यमान वाला है, जिससे ब्लैक होल की चरम सीमाओं की हमारी समझ को नया रूप मिला है। इसके अलावा, ये ब्लैक होल न केवल अत्यधिक विशाल थे, बल्कि बेहद तेजी से घूम भी रहे थे। अतः ऐसे में इनसे आने वाले सिग्नल को समझना कठिन हो गया था। साथ ही, यह इन ब्लैक होल्स के निर्माण से जुड़े जटिल इतिहास का संकेत भी देता है।

19. उत्तर: (b) केवल 2 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है:** मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों में फैले हुए हैं।
- **कथन 2 सही है:** तमिलनाडु में स्थित जिंजी हिल किला, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारह किलों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध है।
- **कथन 3 सही है:** रायगढ़ हिल किले को छत्रपति शिवाजी ने अपनी स्थायी राजधानी के रूप में चुना था, और यह वास्तव में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का हिस्सा है।

20. सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है: पिपरहवा अवशेष पिपरहवा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश** में खोजे गए थे, और ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बुद्ध के **पार्थिव अवशेषों (शरीर के अवशेषों)** से जुड़े हैं।
- **कथन 2 गलत है:** एक अस्थि-पेटी पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख अंकित है, जो बुद्ध के अवशेष होने की पुष्टि करता है, लेकिन उन्हें **शाक्य वंश** द्वारा जमा किया गया था, मौर्य वंश द्वारा नहीं।
- **कथन 3 सही है:** पिपरहवा अवशेषों को भारतीय कानून के तहत 'AA' श्रेणी की प्राचीन वस्तुएं घोषित किया गया है, जिनका निर्यात या बिक्री प्रतिबंधित है।

13.2 ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

उत्तर:

1. T	**2. F**	**3. T**	**4. T**	**5. T**	**6. F**	**7. T**	**8. T**	**9. T**	**10. T**
11. F	**12. F**	**13. T**	**14. F**	**15. F**	**16. T**	**17. F**	**18. T**	**19. T**	**20. F**

13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण (Approach to the Mains Practice Questions)

1. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** डिजिटल उपनिवेशवाद को परिभाषित करते हुए, इसके स्तंभों (आर्थिक, निगरानी, सांस्कृतिक) की व्याख्या कीजिए।
- **मुख्य भाग:** गोपनीयता, स्थानीय व्यवसाय, विनियमन में कठिनाई जैसे मुद्दों को उजागर कीजिए, भारतीय उपायों (DPDP अधिनियम 2023, ONDC, इंडिया स्टैक, वैश्विक वकालत) का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** डेटा स्थानीयकरण, डिजिटल संप्रभुता, गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए आगे की राह सुझाइए।

2. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** वैश्विक रुझानों (जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना) का उल्लेख कीजिए और फिर भारत के अनुभव (61वाँ संशोधन, 17 वर्षों का प्रस्ताव) के बारे में भी बताइए।
- **मुख्य भाग:** पक्ष और विपक्ष में तर्कों का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** नागरिक शिक्षा, मतदाता जागरूकता, क्रमिक सुधार जैसे उपायों को शामिल करते हुए आगे की राह सुझाइए।

3. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** CETA और विज़न 2035 का संदर्भ प्रस्तुत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** टैरिफ को समाप्त या कम करने, सेवा क्षेत्र के लाभ जैसे प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- **निष्कर्ष:** रणनीतिक मुद्दों के साथ उत्पन्न अवसरों को संतुलित करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

4. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** परियोजना का विवरण देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** परियोजना से जुड़े मुद्दों जैसे जल का हथियार के रूप में उपयोग, कृषि में व्यवधान, भूकंपीय जोखिम का उल्लेख करते हुए समझाइए कि इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है।
- **निष्कर्ष:** सीमा पार जल प्रशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

5. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** सार्वजनिक ऋण को सरकार के कुल उधार (आंतरिक + बाह्य) के रूप में परिभाषित करते हुए शुरुआत करें। और विकास के वित्तपोषण में इसके महत्व की व्याख्या करें। RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 का उल्लेख करें।
- मुख्य भाग: बढ़ते सार्वजनिक ऋण के कारणों, प्रभाव और सरकारी ढाँचे एवं प्रयासों पर चर्चा करें।
- **निष्कर्ष:** उठाए जाने वाले कदमों के साथ निष्कर्ष निकालें।

6. दृष्टिकोण

- **प्रस्तावना:** RDI योजना और उभरते तथा गहन तकनीकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को उत्प्रेरित करने के इसके उद्देश्य का संक्षेप में उल्लेख करें।
- **मुख्य भाग: RDI योजना के महत्व, भारत में अनुसंधान एवं विकास की चुनौतियों और सरकारी पहलों पर चर्चा करें।**
- **निष्कर्ष:** अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए आगे के उपायों के साथ निष्कर्ष निकालें।

7. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** भारत के तीव्र शहरीकरण और उसके प्रक्षेपण को संक्षेप में स्वीकार करें।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख कमजोरियों, लचीलापन निर्माण में चुनौतियों और सिफारिशों के मूल्यांकन का उल्लेख करें।
- **निष्कर्ष:** बहुआयामी सिफारिशों का कार्यान्वयन।

8. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक का विवरण।
- **मुख्य भाग:** इसके उद्देश्यों और महत्व का उल्लेख करें। और यह पहल रोगों से लड़ने के लिए डेटा का उपयोग कैसे कर रही है।
- **निष्कर्ष:** भारत में स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान को बदलने में बायोबैंक की महत्वपूर्ण भूमिका।

9. दृष्टिकोण

- **प्रस्तावना:** सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** इस मानसिक स्वास्थ्य संकट के पीछे के कारकों पर चर्चा करें।
- **निष्कर्ष:** सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ निष्कर्ष निकालें।

10. दृष्टिकोण

- **प्रस्तावना:** तकनीक के हालिया संदर्भ से उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग और इसके संभावित महत्व की व्याख्या करें।
- **निष्कर्ष:** तदनुसार निष्कर्ष निकालें।

11. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** पंचायती राज संस्थाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत विकास लक्ष्य, महिला सशक्तिकरण) के लिए वित्त का महत्व बताएं।
- **मुख्य भाग:** घटती धनराशि, सीमित अनुदान, कमजोर राज्य वित्त आयोग (SFC), खराब OSR जैसे मुद्दों का उल्लेख करें। भारत में की गई पहलों का उल्लेख करें।
- **निष्कर्ष:** आगे बढ़ने के तरीके के रूप में समिति की सिफारिशों, नियमित राज्य वित्त आयोग (SFC), समय पर चुनाव, हस्तांतरण रोडमैप के साथ उत्तर को समाप्त किया जा सकता है।

12. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** कानूनी ढाँचे के साथ उदाहरणों (कावेरी, रावी-व्यास, महानदी) का उल्लेख करें।
- **मुख्य भाग:** न्यायाधिकरण में देरी, राजनीतिकरण, आँकड़ों की कमी और आवश्यक सुधारों जैसी चुनौतियों का उल्लेख करें।
- **निष्कर्ष:** हितधारकों की भागीदारी के साथ समग्र बेसिन-आधारित प्रबंधन का उल्लेख कर सकते हैं।

13. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** भारत-अफ्रीका का ऐतिहासिक संबंध (उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग)।
- **मुख्य भाग:** भारत-अफ्रीका संबंधों में मौजूद चुनौतियां और साझेदारी को मजबूत करने के उपाय को लिखें।
- **निष्कर्ष:** भारत-अफ्रीका संबंध विश्वास और साझा विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित हैं।

14. दृष्टिकोण

- **प्रस्तावना:** हाल ही में हुई छंटनी (जैसे, टीसीएस, वैश्विक छंटनी) का संक्षेप में उल्लेख करें, फिर संक्षेप में फ्यूचर ऑफ वर्क को परिभाषित करें।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख चालकों, प्रभावों और सरकारी पहलों पर चर्चा करें।
- **निष्कर्ष:** समावेशी, न्यायसंगत और लचीले फ्यूचर ऑफ वर्क को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्कौशल, सामाजिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालें।

15. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम साइबर रेडीनेस के बारे में संक्षेप में परिभाषित करें।
- **मुख्य भाग:** क्वांटम साइबर खतरों और साइबर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा करें।
- **निष्कर्ष:** साइबर सुरक्षा के महत्व और आगे की राह पर संक्षेप में प्रकाश डालें।

16. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** भारत की हालिया उपलब्धियों और उनके महत्व को बताकर उत्तर की शुरुआत करें।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख चुनौतियों और शुरू की गई पहलों का उल्लेख करें।
- **निष्कर्ष:** इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की सतत सफलता के लिए बहुआयामी चुनौतियों (खाद्य, जल और ऊर्जा आवश्यकताओं में संतुलन) का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

17. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना:** भारत की तीसरी शिक्षा नीति के रूप में NEP 2020 का संक्षेप में परिचय दें, और इसके मूलभूत सिद्धांतों जैसे वैचारिक समझ, प्रौद्योगिकी एकीकरण और समानता पर प्रकाश डालें।
- **मुख्य भाग:** उपलब्धियों और कार्यान्वयन में आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं का उल्लेख करें।
- **निष्कर्ष:** संक्षेप में बताएँ कि NEP 2020 ने सराहनीय प्रगति हासिल की है, लेकिन वित्त पोषण, शासन, हितधारक समन्वय और अवसंरचनात्मक क्षमता के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

18. दृष्टिकोण:

- **प्रस्तावना**: NISAR मिशन और उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख तकनीकी विशेषताओं, महत्व और अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** सतत विकास, आपदा तैयारी और जलवायु लचीलेपन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में NISAR का महत्व, भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

19. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** हाल ही में मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है।
- **मुख्य भाग:** मराठा सामरिक दृष्टि और स्थापत्य कौशल पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। साथ ही सैन्य कौशल और अनुकूली रणनीतियों के प्रतिबिंब पर भी चर्चा करें।
- निष्कर्ष: यह सारांश देते हुए निष्कर्ष निकालें कि ये लैंडस्केप्स छत्रपति शिवाजी की दूरदर्शिता, मराठा इंजीनियरिंग की प्रतिभा और उनकी दुर्जेय सैन्य एवं प्रशासनिक दूरदर्शिता के चिरस्थायी प्रतीक हैं, जो भारतीय इतिहास के एक अनूठे दौर को दर्शाते हैं।

20. दृष्टिकोण:

- **परिचय:** शाही चोल राजवंश का परिचय दें।
- **मुख्य भाग:** जल प्रबंधन, धार्मिक परंपराओं के प्रचार और समुद्री शक्ति के विकास में चोल राजवंश के योगदान का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** चोल विरासत की पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकालिए।

13.4. केस स्टडी हेतु दृष्टिकोण (Approach to Case Studies)

- **प्रस्तावना:** इस केस को एक *नैतिक दुविधा* के रूप में प्रस्तुत करें, जहाँ विज्ञापन और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन की चुनौती है।
- विभिन्न हितधारकों (सेलिब्रिटी, कंपनियां, सरकार, उपभोक्ता, मीडिया, नियामक संस्थाएँ) की भूमिका और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।
- समझाएँ कि सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा डिजिटल युग में सार्वजनिक हस्तियों के आचरण को कैसे बेहतर बना सकती है।
- निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक रणनीति प्रस्तावित करें: स्व-नियमन, विनियमन, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जन जागरूकता, सामूहिक नैतिक कर्तव्य आदि।

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQ's				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

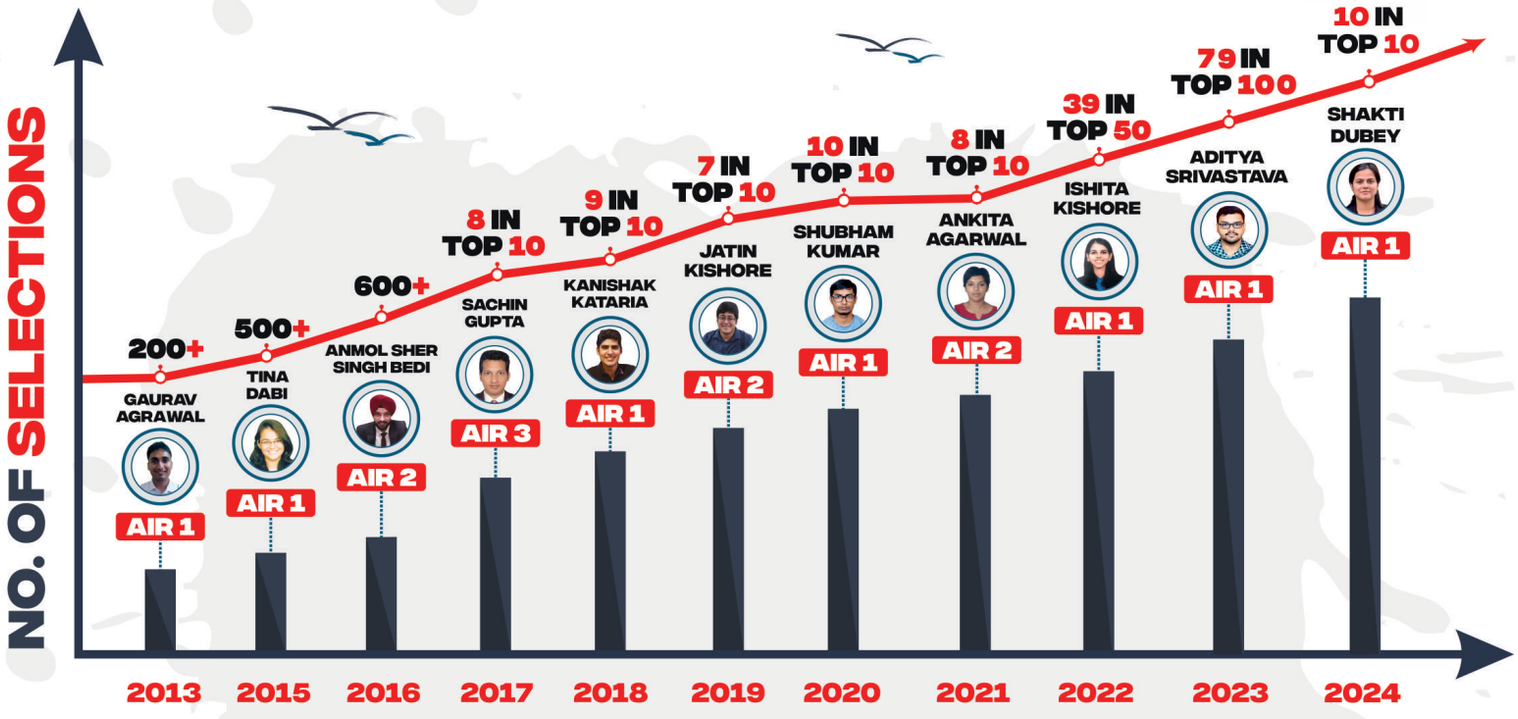

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM | 9 SEPT, 11 AM
18 SEPT, 8 AM | 25 SEPT, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 29 JULY, 6 PM | 22 AUG, 6 PM

हिन्दी माध्यम | **11 सितम्बर, 2 PM**

AHMEDABAD: 12 JULY | **BENGALURU: 25 AUG** | **BHOPAL: 18 AUG** | **CHANDIGARH: 18 JUNE**

HYDERABAD: 3 SEP | **JAIPUR: 5 & 10 AUG** | **JODHPUR: 10 AUG** | **LUCKNOW: 29 AUG** | **PUNE: 14 JULY**

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 15 सितम्बर**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

Shakti Dubey

Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

Shah Margi Chirag

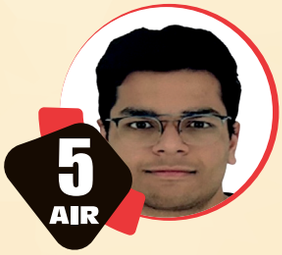

Aakash Garg

Komal Punia

Aayushi Bansal

Raj Krishna Jha

Aditya Vikram Agarwal

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

Ankita Kanti

Ravi Raaz

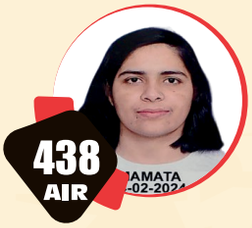

Mamata

Sukh Ram

Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची